₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जून 2019

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

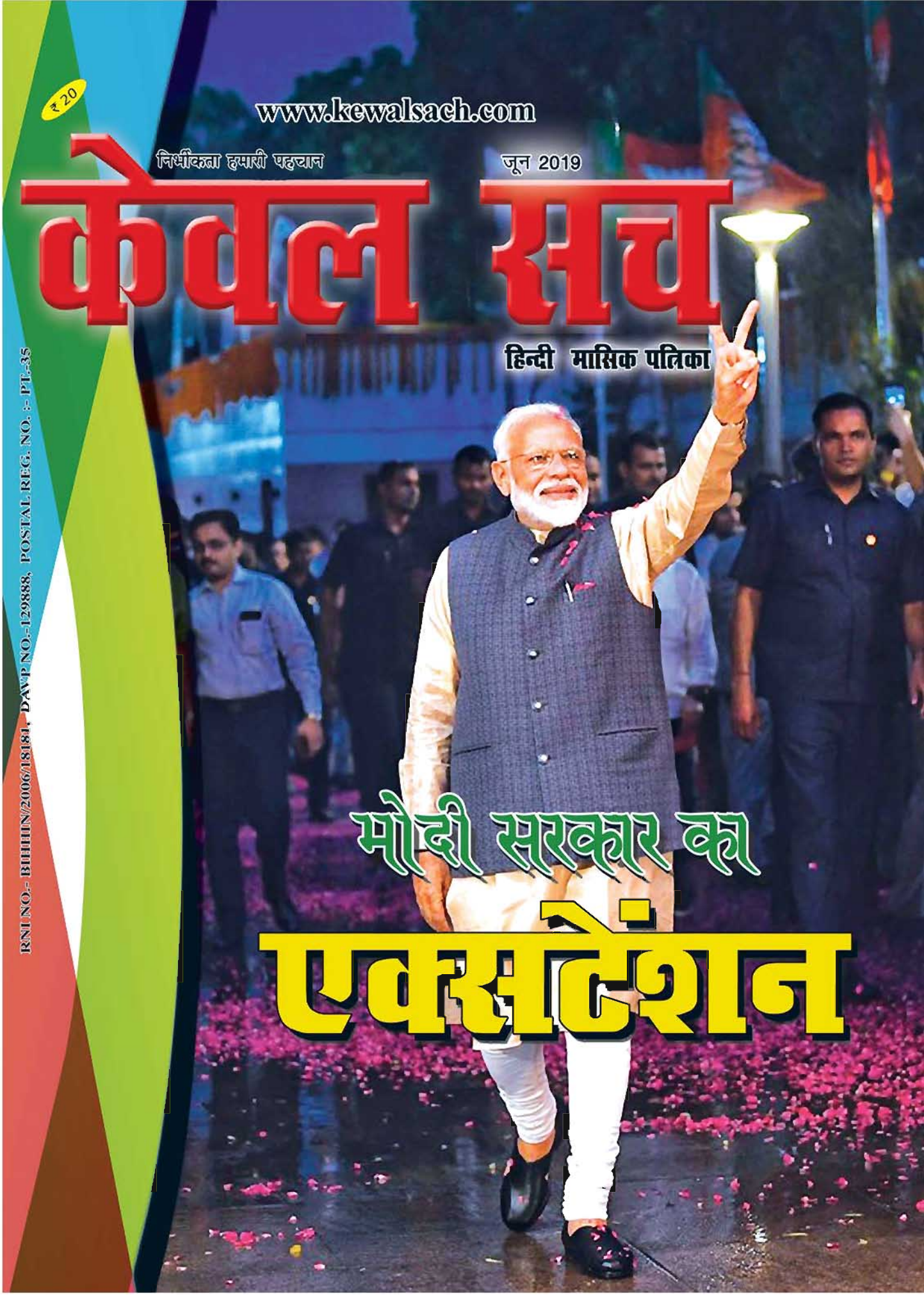

मोदी सरकार का

एक्सटेंशन

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAWP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.-35

बिहार एवं झारखण्ड की तेज़ी से बढ़ती पत्रिका

"केवल सच"

सबुत के साथ खबर लिखता है

केवल सच मिडिया ग्रुप

भ्रष्टाचार एवं दहशतगर्दी

और

मुखिया से मुख्यमंत्री

थाना प्रभारी से डीजीपी के

साक्षात्कर के लिए चर्चित

पत्रिका केवल सच

से आज ही जुड़े।

ब्रजेश मिश्र

संस्थापक सह संपादक

www.kewalsachlive.in

वेब पोर्टल न्यूज

24 घंटे आपके साथ

Mob. 09431073769, 9308727077

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

www.kewalsach.com

Kewal Sach TIMES

A National Magazine

www.kewalsachtimes.com

प्रधान कार्यालय- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

झारखण्ड कार्यालय- सेक्टर-1, ब्लॉक-22, फ्लैट-303, खेलगाँव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, होटवार, राँची (झारखण्ड)

सम्पर्क संख्या :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

दिनेश कार्तिक
01 जून 1985

सोनाक्षी सिन्हा
02 जून 1987

स्व०जॉर्ज फर्नांडीस
03 जून 1930

अनिल अंबानी
04 जून 1959

मुकेश भट्ट
05 जून 1952

महेश भूपति
07 जून 1974

शिल्पा शेट्टी
08 जून 1975

किरण बेदी
9 जून 1949

सोनम कपूर
9 जून 1985

सुबोधकांत सहाय
11 जून 1951

किरण खेर
14 जून 1955

शेखर सुमन
14 जून 1960

मिथुन चक्रवर्ती
16 जून 1950

लियंडर पेस
17 जून 1973

राहुल गांधी
19 जून 1970

मुकेश खन्ना
19 जून 1958

राज बब्बर
23 जून 1952

वीरभद्र सिंह
23 जून 1934

करिश्मा कपूर
25 जून 1974

धर्मेन्द्र प्रधान
26 जून 1969

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Sector- 1, Block - 22, Flat No.-303, Khelgown Houseing Colony, Ranchi - 834009 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

वंदे मातरम हो गया पूरा भारत

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

भारत माता की जय! वंदे मातरम्! गौ- रक्षा देश की रक्षा! जय श्रीराम! जय - जय श्रीराम के नारे से पूरा भारत गुंजयमान हो रहा है और राष्ट्र के कोने - कोने में मोदी की जय-जय हो गया है लेकिन आज भी देश का 50 प्रतिशत वोटर चुनाव में मतदान से वंचित रहता है, विभिन्न कारणों की वजह से। 303 सीट पर अकेले भाजपा अपने दम पर सदन में बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नरेन्द्र दामोदर दास मोदी एवं उप कप्तान अमित शाह ने विपक्ष तक को साफ कर दिया है, हद तो तब हो गयी जब एनडीए के घटक दलों को भी उतना महत्व नहीं दिया गया और भाजपा के दिग्गज भी मोदी - शाह के राजनीतिक वर्चस्व की वजह से चुप रहकर ही वंदे मातरम् कहना है। लोकसभा चुनाव 2019 को कैसे जीतना है इसकी रणनीति बनाने में कामयाब मोदी - शाह ने विपक्ष के रणनीति को ही हाईजैक कर लिया और उनके ही स्लोगन में विपक्ष को ऐसा चक्रव्यूह में फंसा दिया की वोटर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को एक सिरे से खारिज कर दिया। स्थिति इतनी भयावाह हो गयी की यूपी से राहुल गाँधी अपनी सीट तक नहीं बचा सके और बिहार में विपक्ष को नेस्तनाबूत कर दिया। यह तो भला हो अखिलेश यादव का अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी देकर खुद जहर ग्रहण कर लिया है। महागठबंधन की राजनीति खुद उनके लिए काल बन गयी जैसे 2014 में 0 पर आउट होने वाली बसपा 2019 में सपा के साथ मिलकर 10 सीट पर पहुंच गयी और सपा 2014 की तरह 2019 में 05 सीट पर सिमट कर रह गयी। विपक्ष की हर चाल पर मोदी एवं शाह की आवाज ने ऐसा पलट दिया जैसे लिड्डो में सीढ़ी - सांप वाला खेल चल रहा हो। भाजपा के बड़े - बड़े दिग्गज एवं स्टार प्रचारक को मोदी - शाह ने राजनीतिक छुट्टी दे दी है और भारत की माता की जय! वंदे मातरम! जय श्री राम! की जयघोष कराने का और मुट्ठी बांधकर मोदी - मोदी कराने की राजनीति शुरू हो गयी है। भाजपा - भाजपा -भाजपा के बजाय मोदी- मोदी-मोदी चाहे जितनी बार बोलते रहें का माहौल बन चुका है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल रहेंगे लेकिन मंत्रीमंडल में शामिल नहीं होकर यह कहा की हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। प्रचंड बहुमत का पावर क्या होता है यह सरकार के शपथ ग्रहण में ही दिख चुका है, जबकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता की बिहार में बिना नीतीश कुमार की किसी भी राजनीतिक दल की नैया पार नहीं लगेगी क्योंकि विभिन्न धर्म एवं जातियों के बीच नीतीश कुमार की विकास के लिए 07 निश्चय एवं संकल्प के लिए खास स्थान रखते हैं और शराब बंद एवं देहज बंद जैसे सामाजिक बदलाव के लिए आर्थिक बोझ सहकर भी प्रदेश को बीमार होने एवं शराब एवं दहेज से असमय मृत्यु दर को भी रोका है। जिस प्रकार भारत के हिन्दी राज्यों में पूरा भारत वंदे मारतम् एवं भगवा हो चुका है उसी प्रकार मोदी एवं शाह दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में भी घुसपैठ करने में कामयाब हो गये हैं। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में मोदी एवं शाह की जोड़ी ने बड़ी संख्या में सांसदों को सदन पहुंचाया और ममता बनर्जी की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में जय श्रीराम के नारों से भड़कने वाली ममता बनर्जी को उखाड़ फेकने की रणनीति बन चुकी है और उसमें ममता बनर्जी फंस चुकी है। उससे तो यह साफ दिख रहा है की भाजपा की नजर विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना है और ऐसा होता दिख भी रहा है जैसा बगावत त्रिमूल में दिख भी रहा है। लोकसभा में स्पष्ट एवं प्रचंड बहुमत की तरह ही राज्यसभा में भी भाजपा बहुमत में जल्द ही आ जायेगी जिसके बाद मोदी - शाह की पावर का महत्व सार्वजनिक रूप से दिखने लगेगा। मंत्री हो या पदाधिकारी उसपर पर भी पैनी नजर रहेगी जैसा की मीडिया में स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है की कुछ मंत्रियों को मीडिया मे बने रहने एवं छपने का शौक है उनको अपने काम पर फोकस करना होगा। जनता ने जो भरोसा मोदी सरकार पर किया है उसको हर हाल में पूरा करना होगा। विपक्ष की गठबंधन में भीतरी मनमुटाव एवं कूटनीति को घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देकर प्रचंड बहुमत प्राप्त करने में महारथ हासिल करने वाले मोदी ने विपक्ष के प्रत्येक वार को उनकी ही भाषा में पलटवार कर दिया है, जिसका एहसास विपक्ष को भी है की उसने भारत माता की जय! वंदे मातरम् जैसे स्लोगन के साथ न्याय नहीं किया है। पाकिस्तान का जितना झंडा दिखाया जा रहा है विपक्ष उतने ही बुरी पराजय का सामना कर रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2 चरण के चुनाव के मुद्दे को वोटरों को मोड़ने में मोदी कामयाब हो गये क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी को मुद्दा बनाने के बजाय विपक्ष चौकीदार चोर है और मुस्लिम धर्म की हिमायती होने का दावा से अधिक पाकिस्तान प्रेम को हवा दिया गया, जिसका आक्रोश वोटरों में स्पष्ट तौर पर दिखने लगा तो मोदी शाह ने भारत माता की जय! वंदे मातरम् का राजनीति को प्रभावकारी एवं धारदार बना दिया और वोटरों ने 303 का आंकड़ा पार करा दिया।

2019 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के पहले तक देश के कई सूरमाओं को भारत माता की जय एवं वंदे मातरम बोलने में शर्म महशूस होता था पर 23 मई 2019 को प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद विपक्षी दल खासकर क्षेत्रीय दलों का सूपड़ा साफ हो गया तथा कई परिवार एवं वंशवाद भी खुद ही नासूर बन गये और अपना पत्तन करा चुके है। परिणाम आने के बाद भले ही लालू यादव की तबियत खराब हो जाये पर सच तो यही है की मुलायम सिंह यादव एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा सहित कई सूरमाओं को लाचार बना दिया है। वंदे मातरम्, भारता माता की जय, जय श्रीराम जैसे उद्घोष से हर रैली में जनता को आन्दोलित कर देने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबको अचंभित कर दिया की बिना राम मंदिर की राजनीति के भी मोदी वंदे मातरम के दम पर प्रचंड बुहमत प्राप्त कर सकता है। ओवैसी और उसका भाई सहित जम्मू-कश्मीर की राजनीति करने वाले के मुंह पर देश की जनता ने ऐसा तमाचा जरा है उससे उबरने में वर्षों लग जायेंगे। देश में राष्ट्रीयता के महत्व को कैसे जीवंत किया जा सकता है और पुलवामा की घटना का राजनीति लाभ कैसे लिया जा सकता है यह मोदी - शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है। सवर्ण वोटरों को भी राष्ट्रीयता के नाम पर पूर्णरूपेण गोलबंद करने में भाजपा 100प्रतिशत सफल रही है और एनडीए भी कारगर दिखी। वहीं भारत माता की एकता तोड़ने एवं पाकिस्तानी झंड़ा दिखाने वाले दलों का भारत की जनता ने क्या हाल कर दिया है यह ममता, माया, लालू, अखिलेश से बेहतर कौन जान सकता है।

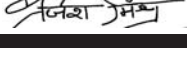

मई 2019

हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769, 9955077308
kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

उम्मीदवारों का अकाल

संपादक जी,

आपकी पत्रिका का संपादकीय दिल को झकझोर कर रख देता है। मई 2019 अंक का संपादकीय ''भाजपा में उम्मीदवारों का अकाल'' में वर्त्तमान में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही राजनीति को बहुत बेबाकी से लिखा गया है जो बिल्कुल सच है। आज कार्यकर्त्ता खुद को ठगा हुआ महशूस कर रहे हैं क्योंकि दल में वीवीआईपी उपर से आते हैं उन्हें टिकट मिल जाता है और वर्षों दल की सेवा करने वाले मुंह ताकते रह जाते है। सटीक व अच्छी खबर।

✦ **चिन्टू राय, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

दमदार खबरें

ब्रजेश जी,

मई 2019 अंक में '' परेशान हर्षिता चढ़ी स्कूल की बलि'', ''भाजपा की कमान संभालेंगे संजय जोशी'', ''मुख्यमंत्री को बदनाम कर रही है बीडीओ'', ''माय के बाद मुनिया समीकरण कितना असरदार'', नक्सलियों ने डकैती को दिया अंजाम'' और ''कहीं लातूर न बन जाये नवादा'' खबर में पत्रकारों ने वर्त्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्था के सच को उजागर कर दिया है। ऐसी खबरे वास्तव में आवाम को बहुत जानकारी देती है। सभी पत्रकार बधाई के पात्र हैं।

✦ **यादवेन्दु पाण्डेय, श्याम बाजार, कोलकाता**

ग्रामीण आगजनी

मिश्रा जी,

लोकसभा चुनाव के वक्त भी आपकी पत्रिका केवल सच ने इसको सिर्फ राजनीति का मंच बनाने के बजाय समाज से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। फायर सेफ्टी के विशेषज्ञ ललन कुमार ने मई अंक में ''अभिशाप है ग्रामीण आगजनी'' खबर में अभी मौसम के अनुकूल आग लगने की सभी प्रकार की संभावनाओं से अवगत कराना और उसके समाधान का मार्ग बताना, सच में मजबूत पत्रकारिता का परिचय है। आपकी पत्रिका समाज का दर्पण का काम कर रही है जिसपर सरकार को ध्यान देकर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए।

✦ **जगदीश मिश्र, चंदौली बाजार, चंदौली, यूपी**

महासंग्राम

संपादक जी,

मई 2019 अंक का कवर स्टोरी ''लोकसभा का महासंग्राम, सत्ता किसकी?'' में पत्रकार अमित कुमार ने अपनी खबर में स्पष्ट कर दिया था की इस महासंग्राम का असर क्या होगा। 16वीं लोकसभा चुनाव की एक - एक पहलू को बारीक ढ़ंग से लिखा गया है। केवल सच पत्रिका की बेबाकी का दाद देना होगा की उन पहलुओं को भी रखा गया है जिसपर सभी का ध्यान नहीं जाता। कई राज्यों की भी समीक्षा के साथ महागठबंधन पर सटीक आलेख लिखा गया है। इस अंक का सभी खबर न सिर्फ पठनीय है बल्कि दमदार और असरदार है।

✦ **प्रवीण पटेल, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली**

फनी तूफान

ब्रजेश जी,

मैं केवल सच का नियमित पाठक हूं और सभी खबरों को सनसनी नजरों से पढ़ता हूं। राजनीति के साथ जनसमस्याओं से जुड़ी खबर भी इस अंक का बेहतरीन है। पत्रकार ललन कुमार ने ''फनी चक्रवाती तूफान'' पर बहुत ही सटीक विश्लेषण के साथ खबर को रखा गया है, इसके कारण और बचाव दोनों की जानकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पाठकों के समक्ष रखते हुए फनी से हुई तबाही को भी खबर में उकेरा गया है। तूफान से हुई विपदा से निपटने का उपाय के साथ हर पहलुओं को पत्रकार महोदय ने खबर के माध्यम से जानकारी दी है, वह बधाई के पात्र हैं।

✦ **रमेश मरांडी, करमटोली चौक, राँची**

मिलावट

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका किसी भी खबर को दमदार लेखनी के साथ लिखता है जिसको पढ़ने के बाद पाठकों में जागरूकता आता है तथा जोश भी बढ़ता है। मई 2019 अंक ''सरसों तेल का जहरीला खेल'' की खबर में प्रदीप कुमार सिन्हा ने मिलवाटखोर एवं मिलावट के बाजार का पर्दाफास किया है। खाने के सामान में इस प्रकार की मिलावट से ग्राहकों को ठगा भी जा रहा है और उसको कई बीमारी भी दिया जा रहा है जैसा जहरीला सामान बेचा जा रहा है। इस खबर पर सरकार एवं विभाग को ठोस कार्रवाई करना चाहिए। सटीक व सोचनीय खबर है।

✦ **कमलेश वर्णवाल, रमना रोड, गया**

अन्दर के पन्नों में

सोन नदी को बचा लिजिए.....13

सेवा के नाम पर लूटते हैं बाबा.....81

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 14 अंक:- 157 माह:- जून 2019, मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

गोपाल मिश्र **0612/2362784**

संपादक

ब्रजेश मिश्र

09431073769

09955077308 08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

kewalsach_times@yahoo.com

प्रधान संपादक

दीपक मिश्रा 09334096060, 09717857012

सच्चिदानन्द मिश्र 09431878843

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 09430888060, 08873004350

अमोद कुमार 09431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 09308815605, 09122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

रीता सिंह 7004100454, 9308729879

उपसंपादक

डॉ० निर्मल आनन्द 08581837557

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 09576438501

शिवचन्द्र झा 08521329144

अजित कुमार त्रिपाठी 9430826676, 9294942868

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

सहायक संपादक

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

संजीव रंजन तिवारी 9430915909

कृष्ण कुमार चंचल 9430520291, 7870421678

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 09608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 09308454485

रणविजय सिंह यादव 09334612716, 09801111138

रवि कुमार पाण्डेय 09507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 09905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 08002647553, 09060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 09905203164

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 09835916650, 09430192929

ब्रजेश मिश्रा 07654122344, 07979769647

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो चीफ

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 09431732481

साहेबगंज :- अनंत मोहन यादव 09546624444

खूँटी :-

जमशेदपुर :-

हजारीबाग :- शैलेश मेहता 09973027485

जामताड़ा :-

दुमका :-

देवघर :-

धनबाद :-

बोकारो :- विनय कुमार सिंह

रामगढ़ :- दिव्य प्रकाश सिंह 08227979999

चाईबासा :-

कोडरमा :-

गिरीडीह :-

चतरा :- धीरज ठाकुर 09430353639

लातेहार :- रविकांत पासवान 09801637947

गोड्डा :-

गुमला :-

पलामू :-

गढ़वा :-

पाकुड़ :-

सरायकेला :-

सिमडेगा :-

लोहरदगा :-

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :- श्रीधर पाण्डेय 09470709185

(म०) :-

(ग्रा०) :-

भोजपुर :-

बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506

:-

गया (श०) :-

(ग्रा०) :-

औरंगाबाद :- मयंक कुमार 9852569398

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543

नालन्दा :- ललन प्रसाद 6299793069

:-

नवादा :- अमित कुमार 9934706928

:-

मुंगेर :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बेगूसराय :-

:-

खगड़िया :-

समस्तीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

वैशाली :-

:-

छपरा :-

सिवान :- सनोज कुमार 9955672241

:-

गोपालगंज :-

:-

मुजफ्फरपुर :- अविनाश कुमार 9470659050

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बेतिया :-

बगहा :-

मोतिहारी :-

दरभंगा :-

:-

मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141

:-

सहरसा :-

मधेपुरा :-

सुपौल :-

किशनगंज :-

:-

अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०) :-

नवगछिया :-

बांका :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०-09868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०-09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
सेक्टर- 1 ब्लॉक नं.- 22,
फ्लैट नं.- 303,
खेलगांव, होटवार, राँची- 834009
मो०- 9955077308, 9431073769

मध्य प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास,
बेलभाँटा, अभनपुर, रायपुर
(छत्तीसगढ़)
मो०-09835845781,
08602674503

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 7492868363

उत्तर प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उत्तराखण्ड कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

गुजरात कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

राजस्थान कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

हरियाणा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

कर्नाटक कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उड़ीसा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

आसाम कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- शम्भू नाथ मिश्र
रेलवे गेट नं.- 02 राजेन्द्र नगर
वार्ड नं.- 08, लंका, पोस्ट- लंका
जिला-नगावँ, दिसपुर (आसाम)
मो०- 08135023285, 07631376135

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश कुमार मिश्रा 07992327070
09631400205

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 09433567880
09339740757

उत्तर प्रदेश हेड

गदाधर नाथ मिश्रा 09452127278

महाराष्ट्र हेड

कमोद कुमार कंचन 07783822144

एक नजर इधर भी

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए-17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- United Bank Of India
IFSC Code :- UTBI0KKB463
PAN No. :- AAJFK0065A

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009

09437029875

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.)

N.B.C.C

08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000
		7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

www.kewalsach.com

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी रालोसपा	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

विशेष प्रतिनिधि

राजेश कुमार मिश्र	8757834700, 7004296529
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
मनीष कुमार कमलिया	9934964551
कामोद कुमार कंचन	8971844318, 9110187832
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
प्रदीप कुमार सिन्हा	9472589853, 6204674225
विवेक कुमार मिश्र	7461803110,
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
प्रणव कुमार कश्यप	8809903185
सलाम साबरी	9835094832
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
अजय कुमार	8409103023, 6203723995
राजेश कुमार	7632936806, 7563816708
अवधेश कुमार शर्मा	9304827131, 8789324045
शिव कुमार ओझा	9162841133, 9162746866
राजमंति पाण्डेय	6201672831, 9155794800
वंदना सिंह	7903669215,

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000,	9431096964
मुकेश कुमार	9835054762,	9304377779
जय प्रसाद	9386899670,	
कृष्णा प्रसाद	9608084774,	9835829947

ग्राहकों को ठग रही हैं मोबाइल कंपनियां

ब्रजेश मिश्र / प्रदीप कुमार सिन्हा

महासंचार क्रांति का युग है जिसकी वजह से पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो चुका है। किसी से बात करना हो या विडियो कॉलिंग यह आज इसलिए संभव है की गूगल ने इसे आसान बना दिया है। गूगल एक तरफ ग्राहकों को जागरूक भी करता है तो दूसरी तरफ चोरों को टिप्स जाने - अंजाने में दे भी देता है। टेलीफोन की घंटी बंद होने के बाद मोबाइल के रिंगटोन की दुनिया में भारत का हर एक नागरिक एक - दूसरे से कनेक्ट हो गया है। एक के बाद एक बड़ी कंपनी मोबाइल को बाजार में उतारा जिसको वाहन वाले से लेकर रिक्शे वाले के हाथ तक आसानी से पहुंच गया और जिओ का नेटवर्क आने के बाद तो मोबाइल बच्चों के हाथ का खिलौना हो गया। सोशल मीडिया के बढ़ते वर्चस्व ने मोबाइल को लोगों ने अपना जीवन ही बना लिया है और शरीर का एक हाथ परिवार के रिश्ते के बजाय मोबाईल पकड़ रहा है। ऐन्ड्रायड मोबाइल का बाजार ने लोगों को जहां सुविधाएं पहुंचायी तो चोर एवं ठगने वाले गिरोहों को भी रोजगार मुहैया करा दिया है। आज देशी एवं विदेशी मोबाइल कंपनियाँ मोबाइल की सुरक्षा के लिए IMEI No. से जोड़ा ताकि सेट गुम हो जाने, गिर जाने या छिन लिए जाने की सूरत में उसको IMEI No. के जरिये ट्रैक किया जा सके। आज देश में अपराधिक गतिविधियों को मोबाइल के माध्यम से ही डिटेक्ट किया जा रहा है वहीं चोर एवं चोरी का सामान एवं मोबाइल का IMEI No. को इरेज करके नया सॉफ्टवेयर चढ़ाकर उसको नया मोबाइल बना दिया जाता है और ग्राहक सिर्फ मुंह ताकता रह जाता है की उसका मोबाइल वापस आयेगा। भारत एक ऐसा देश जहां विश्वास का दावा करके जान तक कुर्बान किया जा सकता है और इन्हीं विश्वास का कत्ल बाजार में प्रोडक्ट बेच रही कंपनिया ग्राहकों को ठग रही है। 05 जी के दौर में एंड्रॉयड मोबाइल महंगी होती जा रही है तथा कई प्रकार का तकनीकि विकसित हो चुका होगा लेकिन मोबाइल की सुरक्षा को लेकर न तो मोबाइल कंपनियां गंभीर दिखती है और न ही सरकार एवं पुलिस - प्रशासन इसको प्राथमिकता में रखता है। मोबाइल आज जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसकी आदत दवा की तरह हो चुकी है की हांथ की उंगली मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं पहुंचे तो खुद को अपाहिज जैसा महशूस करता है, जिसके मद्देनजर इस आदत का बाजार करके कंपनियां रातों - रात अमीर से और अमीर होती जा रही हैं। मोबाइल को जिओ का कनेक्शन ने एंड्रॉयड रिक्सा - ठेला के हाथों तक बहुत ही आसानी से चाईना का मोबाइल ने उपलब्ध करा दिया है। कार एवं ऑटो के चालक तो पहले से ही मोबाइल से लैश थे ताकि पैसेंजर को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकें। मोबाइल का गुम होना या चोरी होना एक आम बात हो गयी है। लेकिन पुलिस की सोच एवं कार्रवाई में कोई अंतर नहीं दिखता और बस एक सनहा का नं देकर कहानी को वहीं समाप्त कर नये मोबाइल खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मोबाइल गुम हो या चोरी पुलिस वास्तव में उसकी पड़ताल करे तो जिस प्रकार आपराधिक घटनाओं का उदभेदन करने में पुलिस सफल हो रही है, उतने ही उत्साह एवं गंभीरता से पुलिस मोबाइल चोरी एवं गुम के मामले को आईटी के माध्यम से पकड़ने लगे तो चोरी की घटनाओं में भी कमी आयेगी और पुलिस की साख भी बढ़ेगी। सरकार को भी ऐसी कंपनी को निबंधन नहीं देना चाहिए जिसका IMEI को तोड़कर चोरी का मोबाइल बेचा या इस्तेमाल किया जा सके अन्यथा ऐसी कंपनी पर प्रतिबंध लगाना होगा जिससे चोरो एवं चोरी के मोबाइल का तोड़ने का गोरखधंधा कर रहे हैं। पटना का बाकरगंज में कई बार चोरी का मोबाइल बेचने एवं IMEI No.को ओवरलैप करके चोरी के मोबाइल को चारपहिया वाहन का ईंजन और चेसिस नं की तरह मिटाकर नया कर देते हैं जिससे चोरी या गुम हुआ मोबाइल का वापस पाने का सपना बनकर रह जाता है। पुलिस का आई टी सेल कितना कारगर है, यह देश के नागरिक के साथ - साथ पुलिस एवं सरकार भी अच्छे ढ़ंग से जानती है। बिहार में बालू एवं शराब को अवैध कमाई का जरिया बना चुके माफियाओं के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है अन्यथा चोरी हुए मोबाइल के आवेदन को गुम हो गया विषय नहीं लिखवाया जाता बल्कि मोबाइल आपको मिलेगा और चोरी का मोबाइल इस्तेमाल संभव नहीं है के विषय पर कार्रवाई होती पर जमीनी हकीकत यही है की थाना तो सनहा दर्ज करने के लिए भी दक्षिणा मांगती है। एपल कंपनी को छोड़कर सभी कंपनी सिर्फ IMEI No. के नाम पर सुरक्षा का हवाला देकर ग्राहकों को मूर्ख बनाकर महंगी - महंगी मोबाइल बेच देती है तथा मोबाइल का टूटने - फूटने एवं पानी में गिर जाने पर उसकी भारपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस करती है पर चोरी हो जाने पर जिस प्रकार 4 और 2 व्हीलर का इंश्योरेंस होता है मोबाइल में नहीं होता। मोबाइल की कीमत दिनो - दिन आसमान छूती जा रही है लेकिन सुरक्षा का ख्याल से न तो कंपनी कोई ठोस उपाय एपल कंपनी की तरह करती है और पुलिस प्रशासन, वैसे में पुलिस हाईटेक पद्धति से किसी केश का अनुसंधान कैसे करती है यह चिंतनीय विषय है। पुलिस यह मानकर चलती है की गुम या चोरी का मोबाइल लोगों को वापस मिल जाये उसके लिए कोई तकनीति का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि थाना में सनहा दर्ज कराने के नाम पर 500 रूपये उपर से देना पड़ता है अन्यथा आपके सीम से कोई कांड अन्य के द्वारा हो जाये तो पुलिस आपकों तंग नहीं करे। पुलिस थाने का मुंशी हो या दरोगा या फिर थानेदार न जाने क्यों सरकार एवं अपने विभाग के प्रधान के आदेश को ठेंगा दिखाती है या फिर जनता को गुमराह करने के लिए पुलिस को पिपुल्स फ्रेंडली बनने का स्वांग रचा जाता है। किसी का वाहन चोरी हो जाये या मोबाइल या अन्य कोई दस्तावेज आपको बगैर मुंशी एवं केश के आईओं को चढ़ावा चढ़ाये एक कदम जांच की पद्धति आगे नहीं बढ़ती जबकि मेट्रो शहरों में पुलिस के दहशत से चोरों का जीना हराम हो जाता है। बिहार - झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में पुलिस की करतूत से सरकार की हमेशा जगहसाई होती है जबकि नीतीश कुमार एवं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस पर राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ने दिया है की पड़ताल करती एक रिपोर्ट:-

कर लो दुनिया मुटठी में'' यह नारा रिलायंस कंपनी ने संचारक्रांति के दौर में दिया था और उसमें सफलता भी पायी थी। आज मोबाइल के बढ़ते वर्चस्व ने इसको और सच कर दिखाया है तथा मनुष्य के जीवन एवं रिश्ते में मोबाइल ने खास जगह बनाने में सफलता पायी है पर रिश्तों की यह सुरक्षित रहे इसका ख्याल न तो सोना–चांदी की कीमत की तरह बेच रही मोबाइल कंपनी रख पा रही है और न ही सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस विभाग। ग्राहकों को धोखा कैसे दिया जाता है यह सीखना हो तो भारत के बाजार में कदम रखिये और किसी बड़े कलाकारों से उसका विज्ञापन करवाईये, इसके बाद ग्राहक आपकी कंपनी से अधिक उन कलाकारों का चेहरा देखकर 95 फिसदी भारतीय ग्राहक उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं क्योंकि उनके अपने कलाकार पर पूरा भरोसा है की अमुक व्यक्ति किसी गलत प्रोडक्ट का प्रचार कर ही नहीं सकता पर वास्तविक सच्चाई बिल्कुल इससे इत्तर है। 21वीं सदी में खुद को अपडेट एवं हाईटेक रखने के लिए नई तकनीकि पर ही भरोसा करना है और जितना तकनीकि विकसित हो जा रहा है, असुरक्षा का महौल उतना ही विकसित हो रहा है। बिना एटीएम कार्ड के ही एटीएम से रूपये निकल जाते हैं और ग्राहक के मोबाइल पर यह संदेश आता है की आपके खाते से पैसा निकल गया है। अब गौर करने वाली बात है की आखिर साइबर चोरों को इतनी शक्ति एवं जानकारी कैसे मिलती है की अमुक व्यक्ति का पासवर्ड क्या है? ग्राहकों सैमसंग, नोकिया, एमआई, ओपो, विवो, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, एचटीसी, मोटोरौला, अइंटेल, पानासोनिक, सोनी, एलजी, एलवाईएफ, संसुई, जेन, पोको जैसी कई अन्य ब्रांडेड कंपनियाँ महंगी – मंहगी मोबाइल, लैपटॉप और आई पैड IMEI No. से सुरक्षा का दावा करके ग्राहकों को बेचने के लिए अपना प्रतिनिधी भी दुकान पर रखकर कस्टमर को समझाकर बेच रही है। पढ़ा लिखा ग्राहक भी किमत की परवाह किये बगैर सुरक्षा को प्राथमिकता देकर इसलिए खरीद रहे हैं की मोबाईल चोरी, छिनैती या गुम हो जाने पर IMEI No. से ट्रैक करके मोबाइल पाताल से भी खोज निकाला जाता है। बहुचर्चित सुशासन एवं कानून का राज स्थापित है का दावा करने वाली सरकार एवं पुलिस विभाग का मुख्यालय पटना सहित सभी जिला के मुख्यालय में इन दिनों मोबाइल चोरों का आतंक चरम पर है एवं पुलिस की लापरवाही की वजह से चोरों एवं जालसाज दुकानदारों का बाजार गर्म है। 25 से 50 हजार तक का मोबाइल ग्राहक इसी दृष्टिकोण से खरीदते हैं ताकि वह निश्चिंत होकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सके। देश के सभी महानगरों में पुलिस की चौकसी की वजह से चोर एवं मोबाइल दुकानदार किसी भी कंपनी का IMEI No. को डीलिट करके नया IMEI No. चढ़ा देता है लेकिन पुलिस विभाग की मुस्तैदी एवं ट्रैकर सिस्टम से चोर के गलत मंसूबे को धर दबोचती है और सलाखों के पीछे धकेल देती है। मोबाइल कंपनी भी अपने मोबाइल सेट का नं और IMEI No. को कैच करके उस चोरी या गुम हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को पकड़ सकती है कि उसकी कंपनी का मोबाइल कौन और कहां इस्तेमाल हो रहा है उसका टावर लोकेशन सहित गूगल के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है।

बताते चलें कि गुम या चोरी की मोबाइल का सनहा एवं प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी पुलिस की मेहरबानी का मोहताज होना पड़ता है तथा पुलिस बस इस मोबाइल के गुम या चोरी होने के बाद आप किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़े भर से ही सारोकार रखती है जबकि वह अपने थाना क्षेत्र के चोर एवं चोर मंडी की पूरी जानकारी के बाद भी उसको पकड़ने के बजाय ग्राहक/उपभोक्ता को समझा – बुझाकर वापस भेज देती है। अगर हकीकत में पुलिस इस दृष्टिकोण से जांच करती है तो चोर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को बहुत अधिक दिनों तक इस्तेमाल करने पर पकड़ा जा सकता है। राजधानी पटना का सबसे बड़ा कॉलोनी का थाना कंकड़बाग थाना, पत्रकार नगर, रामकृष्णा नगर और जक्कनपुर थाना क्षेत्र में चोरों का गिरोह काफी सक्रिय है तथा दुकानदार भी IMEI No. को बदलकर उसको नया करके बाजार में बेच देते हैं या वहीं चोर उस फोन का इस्तेमाल करता है। सूत्र यहां तक बताते हैं की चोरों के गिरोह के साथ पुलिस की भी मिलीभगत रहती है जिसकी वजह से चोरी गया मोबाइल को भी गुम हो गया का आवेदन लिखवाकर ग्राहक को नया मोबाइल खरीदने का रास्ता बता देती है। अगर चोर एवं चोरी के सामान का बाजार करने वाले गिरोह पुलिस के नेटवर्क से बहुत बड़ा है? क्या चोर से मजबूत साफ्टवेयर पुलिस के पास नहीं है? क्या IMEI No. को बदला जा सकता है? क्या कंपनी अपने मोबाइल सेट के नं से ट्रेस नहीं कर सकती की उसके उस सेट में कौन सा सिम काम कर रहा है? क्यों कंपनी IMEI No. का हवाला देकर ग्राहकों को गुमराह एवं धोखाधड़ी करके मोबाइल बेच रही है? सरकार जब मोबाइल की सुरक्षा की गारंटी ही नहीं लेगी तो CST और GST क्यों लेती है? पुलिस विभाग अगर मोबाइल को ट्रेस नहीं कर पाती तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जायेगा? हाइटेक संसाधनों से लैश पुलिस अगर मोबाईल को भी ट्रेस करने में विफल होती है तो विभाग के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की हालत हो जायेगी।

ग्राहकों के हितों के रक्षा के लिए ही अलग से मंत्रालय एवं विभाग भी बना लेकिन यह विडम्बना नहीं तो और क्या है की देश का

उपभोक्ता फॉर्म ऐसी नामी – गिरामी कंपनियों को ग्राहकों को गुमराह एवं धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के विरूद्ध क्यों नहीं दंडात्मक कार्रवाई करती? आखिरकार ग्राहकों को धोखा देने वाली कंपनी को इतना साहस कहां से आता है? गौरतलब है कि दिनांक 19 मई 2019 को समय लगभग 11.20 से 11.50 के बीच में कंकड़बाग थाना के पोस्टल पार्क स्थित काली मंदिर रोड के पास एक पत्रकार के हाथ से मोबाइल निकालकर स्वीच ऑफ कर लिया जाता है। आईटी सेल का मजबूत नहीं होना भी पुलिस की साख को कमजोर करता दिख रहा है क्योंकि आज के संचारक्रांति युग में मोबाईल का मॉडल नं Redmi Mix 2, IMEI No- 869033026974486 है इसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है जिसका कंकड़बाग थाना कांड संख्या- 476/2019 है और अनुसंधानकर्त्ता सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को बनाया जाता है। ममाले का पड़ताल एवं अनुसंधान करके पुलिस की तत्परता का परिचय देने में कितना कामयाब विजय कुमार सिंह होंगे यह यक्ष प्रश्न है। देखना है की दारोगा विजय कुमार सिंह इस मोबाईल को खोजकर चोर को सलाखों के पीछे धकेल पाते हैं या चोर पुलिस को मात देने में कामयाब होकर पुलिस विभाग के आई टी सेल को ठेंगा दिखाने में सफल हो जाता है।

विश्वसत सूत्र बताते हैं की चोरों के गिरोह में शहरों के जिला मुख्यालय में कई दुकानदार भी शामिल होते हैं जिसकी वजह से ग्राहकों को बहुत परेशानी होती है। थाना को यह मालूम है की उनके क्षेत्र में किस क्षेत्र में कौन सा गिरोह सक्रिय है पर घटना के बाद सक्रियता दिखाने के बजाय प्रारंभ के दिनों में गंभीरता को गौन कर दिया जाता है, इसके पीछे कई कारण है जिसे जनता और विभाग दोनों जानता है। आला अधिकारी का दवाब नहीं हो तो थाने में एफआईआर करना कितना मुश्किल है यह किसी पीड़ित व्यक्ति से पूछा जा सकता है। पुलिस विभाग की आई टी सेल की लापरवाही की वजह से चोर धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं और मोबाइल कंपनियों पर भरोसा करके महंगी मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक मुंह ताकते रह जाते हैं की आईटी की दुनिया में पुलिस से अधिक हाईटेक चोर हैं और इसको पुलिस विभाग को स्वीकार कर लेना चाहिए की सिर्फ बात बनाने एवं साधारण लोगों को अपमानित करने एवं सनहा दर्ज करने के अलावा पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही पुलिस अनुसंधान करती रही तो चोरों का मनोबल सातवें स्थान पर होगा और आई टी सेल पंगु होने का दंश झेलती रहेगी और अमाजनता खुद को ठगा हुआ महशूस करके कंष्ट झेलने को मजबूर हो जायेगी। किसी के एटीएम से बिना कार्ड का पैसा निकाल लेना और एटीएम का सीसीटीवी कैमरा लगे रहने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलना लापरवाही एवं स्थानीय प्रशासन एवं बैक की मिलीभगत होने की संभावना से कैसे इंकार किया जा सकता है। सातवें चरण के चुनाव के दिन कंकड़बाग थाना क्षेत्र में पत्रकार के हाथ से मोबाइल चोरी कर लिया गया जिसकी प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई जिसका कांड संख्या 476/2019 है के आई ओ विजय कुमार सिंह की सक्रियता का सवाल है की यह इसे कितना चुनौती पूर्ण लेते हैं। सूत्र बताते हैं की उनका खुद का भी मोबाइल उनकी जिप्सी से किसी चोर ने उड़ा लिया था और वह उसको भी खोजने में असफल रहे हैं। कुछ ऐसी घटना की जानकारी आजकल खूब मिल रही है, बाइक से चोर आते हैं और बात कर रहे है लोगों के हांथ से छीनकर भाग जाते हैं जैसा कई मामला भी सुर्खियों में है। मोबाइल ही नहीं चेन छिनैती का मामला भी पुलिस को दागदार बनाती है। शराब बंद होने एवं बालू के अवैध कारोबार में पुलिस ज्यादा दिलचस्पी लेती है ताकि सरकार का राजस्व बढ़े या नहीं पर उनका पैकेट हमेशा गर्म रहे। पत्रकारों के साथ भी सवाल पूछने पर धक्का-मुक्की करने वाले थानेदार एवं दरोगा और पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और विभाग ने एक घटना में कार्रवाई भी किया है। थाने में भी सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा और उसको जिला मुख्यालय से जोड़कर देखना होगा की थाने में कार्यरत पदाधिकारी अपनी उस आवाम के साथ कैसा व्यवहार करती है जिससे मिलने वाले राजस्व से उन्हें वेतन मिलता है।

खबर लिखे जाने तक पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल के विषय में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं की जबकि जानकार बताते हैं की पुलिस अगर चाह ले तो पताल में से भी वह पता लगाकर चोर को पकड़ सकती है। कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं की 06 माह के बाद भी पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल को ढूंढ़कर वाह-वाही लूटी है। प्राथमिकी दर्ज करने के लगभग 01 महीने का अपडेट भी कुछ पता नहीं चलता है, वैसे में पुलिस अगर मेहरबान हो तभी यह संभव है और वह आम आदमी के लिए मेहरबानी क्यों करें, यह अहम सवाल है। लोगों के बीच इस बात की चर्चा आम होती है की पुलिस अगर चाह ले तो एक चप्पल भी चोरी होने के बाद चोर को लौटाना पड़ता है। कंकड़बाग थाना में थाना प्रभारी रामाकांत प्रसाद, अभय नारायण सिंह जैसे पुलिस अधिकारी की हनक ऐसा था की कई वर्षों के बाद भी लोगों के जुबान पर उनका ही नाम है। पुलिस को आईटी सेल को बहुत मजबूत बनाना ही पड़ेगा ताकि संचारक्रांति के दौर में किसी भी जानकारी को खासकर साइबर क्राइम के क्षेत्र में चोरों को मात देने वाला तकनीकि को विकसित करना होगा अन्यथा चोरों का पकड़ने पुलिस के लिए नासूर बन जायेगा। इसी लापवाही की वजह से चोरो का मनोबल बढ़ा है। ●

सोन नदी को बचा लिजिए

मुख्यमंत्री जी

ब्रजेश मिश्र की रिपोर्ट:-

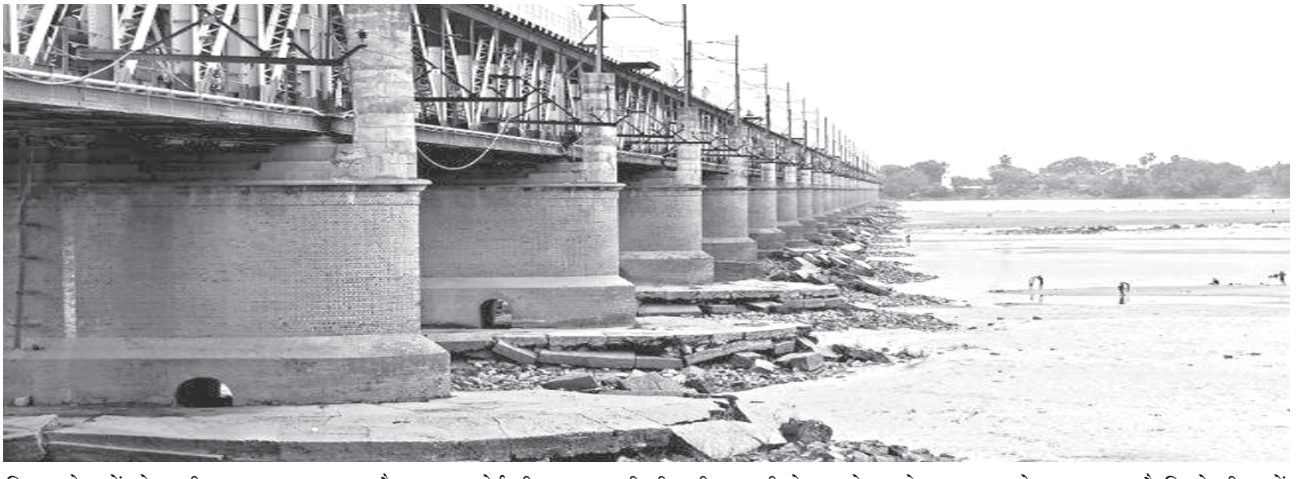

बिहार प्रदेश में सोन नदी का आज क्या महत्व है यह बात कोई भी आम आदमी भी बड़ी आसानी से बता देगा। सोन का बालू सोना उगल रहा है जिसने भी इसमें डुबकी लगायी वह आज मालो-माल हो गया पर सोन नदी अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है। सोन नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तरप्रदेश होते हुए बिहार में आकर वैशाली जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार की प्रमुख नदियों में इसका अपना खास महत्व है और इसका नाम सोन नदी इसलिए पड़ा की इसका बालू (रेत) पीला रंग का होता है, इसलिए इसको लोग सोना भी कहते हैं। गंगा एवं सोन नदी का संगम स्थल सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जिसको देखने पूरी दुनिया से प्रतिवर्ष लोग आते हैं। सोन बालू का इस्तेमाल भवन निर्माण में बिहार में 90 प्रतिशत होता है और सरकार की नीति की वजह से बालू के माफिया सोन को कंगाल बनाने में लगे हैं तथा सोन नदी के दोनों किनारे घाट पर बालू का स्टॉक 04 मंजीला ईमारत से भी बड़ा कर रखा है जो एनजीटी का खुल्लेआम उल्लंघन है। खनन विभाग के पदाधिकारी, जिला प्रशासन एवं स्थानीय थाना के मिलीभगत के साथ पत्रकारों का सहयोग भी बालू के सौदागरों को हिस्सेदार की तरह मिल रहा है जिसकी वजह से सोन का वजूद भी खतरे में जाता दिख रहा है। ब्रिटिश हुकूमत ने सोन नदी पर सड़क सह रेल पुल का निर्माण किया था। सोन नदी का उल्लेख रामायण के ग्रंथ में भी पढ़ने को मिलता है, सोना की तरह पीला चमकने के कारण सोन के बालू को दूर से ही इसको लोग पहचान लेते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के नाम से भी पहचान रखता है। सोन नदी अमरकंटक से निकल कर बिहार के वैशाली जिले में 700 किलोमीटर की यात्रा करके गंगामय हो जाती है। इसी नदी को पहले 'सोहन' के नाम से जानते थे जो पीछे बिगड़कर सोन बन गया। सोन नदी में रोहतास जिला में डिहरी ऑन-सोन पर बाँध बांधकर 296 मील लम्बी नहर निकाली गयी है जिसके जल से शहाबाद का सभी जिला, गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना जिला में लगभग 8 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह बाँध 1874 ई. में बनकर तैयार हो गया था। ज्ञात हो कि सोन नदी पर ही डिहरी ऑन-सोन में 03 किलोमीटर लम्बी सड़क पुल बना हुआ है और तीसरा लोकप्रिय एवं बहुचर्चित पुल सोन नदी पर आरा-पटना के जोड़ने वाला कोईलवर में अब्दुल बारी रेल सह सड़क पुल है, जिसमें नीचे बस एवं चार-तीन पहिया वाहन और उपर में रेल अपने गति दे रही है। 4726 फीट (1440 मीटर) लम्बी सोन नदी पर बना पुल लोहे का गाटर से बना इस दोहरे एवं दो मंजिला का निर्माण तकनीक व सुन्दरता लोगों को आज भी आकर्षित करता है। 1862 में यह पुल बनकर तैयार हो गया था और कोईलवर पुल बिहार के चर्चित स्वतंत्रता आन्दोलन के सेनानी अब्दुल बारी के नाम पर रखा गया। 1982 में रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में बनी फिल्म '' गाँधी '' में भी इस पुल को दिखाया गया था, जिसको सम्मान भी मिला। सोन नदी पर सन् 1965 में एक और पुल डिरी ऑन- सोन ग्रैंड ट्रैक रोड पर बनाया गया था ताकि आवागमन की सुविधा कारगर हो सके। बालू माफिया के बढ़ते आतंक की वजह से पुल का भी वजूद भी खतरे में दिखता है क्योंकि बालू को बेचने के चक्कर में वह यह भूल जाते हैं की यह पुल बिहार की धड़कन है और बालू चोरी एवं उत्खनन में स्थानीय माफिया के साथ स्थानीय प्रशासन एवं खनन विभाग के पदाधिकारी के साथ स्थानीय पुलिस भी अवैध कमाई करती है और सरकार के राजस्व को लूटा भी जाता है और प्रदूर्षित वातावरण एवं पर्यावरण को भी दूषित किया जाता है। जांच पड़ताल के नाम पर एक एसआईटी टीम का गठन की बात कहकर मामला को एक बार फिर दबा दिया जाता है, पर एक रिपोर्ट:-

'' सोन नदी का बहुत ही पौराणिक महत्व है जिसका वर्णन पवित्र ग्रंथ रामायण में भी मिलता है। मध्यप्रदेश के अमरकंटक से निकलकर यूपी के सोनभद्र होते हुए बिहार में सोन नदी बनकर गंगा नदी में विलय कर जाती है। धर्म एवं अध्यातम के साथ वर्त्तमान समय में व्यापार के दृष्टिकोण से सोन नदी सोना उगल रही है। इस कोहिनूर को सरकार एवं उसके पदाधिकारी बचाने के बजाय माफियाओं के साथ मिलकर निगल रहे हैं। बालू पर अधिपत्य जमाने के चक्कर में कितनी जाने जा चुकी है, कई सलाखों के पीछे हैं पर आज भी इस बालू से लोग करोड़ो रूपये अवैध ढ़ंग से अर्जित कर रहे हैं। बालू के भ्रष्टाचार पर सदन में बोलने वाले ही जब इसके सौदागर हैं भला कौन आवाज उठायेगा? ''

सोना आभूषण की तरह बेशकिमती हो चुका है सोन का बालू, जिसपर सबकी निगाहें हैं और जिसकी भी नजर इसपर पड़ी और सोन नदी की कृपा (सरकार के खनन एवं स्थानीय पुलिस) हुई तो भिखारी भी रातों-रात लखपति हो जाता है। इस बालू के लिए पहले भी खूनी संघर्ष वर्चस्व को लेकर होता रहा है तथा हिस्सेदारी एवं बालू घाट के लिए गोली-बारी कोई बड़ी घटना नहीं हैं। बिहार में शराब बंद होने के बाद बालू की किमत आसमान छू रही है और सरकार इसपर नियंत्रण के लिए ठोस एवं कठोर कानून बनाई भी लेकिन माफियाओं के वर्चस्व के कारण तत्कालीन प्रधान सचिव भूतत्व एवं खनन विभाग के के पाठक को ही हटा दिया गया। शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व को सरकार बालू से भी प्राप्त कर सकती है लेकिन अन्य नदी विशेषकर सोन नदी के स्थानीय घाट के माफियाओं एवं राजनीतिक संरक्षण के साथ पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत ने सरकार के राजस्व पर ही डाका डाल दिया है तथा एनजीटी के नियमों का खुल्लेआम उल्लंघन हो रहा है। बालू के अवैध कारोबार में कई एमएलसी और कई खूंखार लोग भी किसी न किसी कंपनी के कुछ प्रतिशत के हिस्सेदार हैं जिसकी वजह से कुछेक पत्रकार भी इसमें माला-माल हो रहे हैं। सोन नदी से बालू निकाल कर बिंदौल घाट हो या कोई अन्य उसके बगल में 04 मंजिला ईमारत जितना उँचा बालू का स्टॉक किया जा रहा है और खनन विभाग के पदाधिकारी अपना हिस्सा लेकर मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है की इतनी उँची बालू की ईमारत किस नियमावली के तहत की जा रही है? यह सोचनीय विषय है? कौन है इसके पीछे जो भारत सरकार एवं बिहार सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? कहां से मिल रहा है संरक्षण? स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? खनन अधिकारी एवं जिला प्रशासन इस मामले में इतना असंवेदनशील कैसे हैं? आखिरकार के के पाठक जैसे ईमानदार पदाधिकारी को क्यों हटाया गया? दानापुर थाना, मनेर थाना, बिहटा थाना, कोईलवर थाना, बिक्रम थाना, सहित अरवल एवं औरंगाबाद जिला सहित रोहतास एवं भोजपुर के सोन नदी के

''बालू का स्टॉक देखकर किसी भी व्यक्ति का दिमाग चकरा जायेगा। सोन नदी को दुधारू गाय की तरह दूह रहे बालू माफिया बालू का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं लेकिन सरकार, खनन विभाग एवं पुलिस पदाधिकारी सबकुछ खुली आँख से देखकर भी क्यों चुप है, इसका आंकलन किया जा सकता है। आतंकवाद/उग्रवाद से निपटने के साथ-साथ सोन नदी को लूटने वाले को प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बचाने की जरूरत है अन्यथा राजनीति की आपसी रंजिश में बिहार का धरोहर कहीं विलुप्त न हो जाये। राज्य सरकार को राजस्व देने वाला दुधारू गाय (सोन नदी) का कहीं प्राण ही नहीं हरण कर लिया जाये। पदाधिकारी पर सख्ती, बालू उत्खनन एवं बालू स्टॉक वाली जगहों पर तथा चलान काटने वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर अंकुश लगाया जा सकता है। ''

किनारे वाले थाना का प्रति रात की कमाई लाखों में है और सरकार का खजाना खाली हो रहा है। भले ही पुलिस अपराध पर नियंत्रण करे या नहीं पर शराब पीने वाले और बालू का कारोबार करने वालो से रात में कितनी कमाई करती है यह विभाग के वरीय पदाधिकारी औचक निरीक्षण के द्वारा देख सकते हैं कि उनके अधिकारी मुख्यमंत्री के सुशासन एवं कानून का राज के साथ क्या गुल खिला रहे हैं। खनन विभाग के पदाधिकारियों के चल-अचल संपत्ति की जांच करने पर ही स्पष्ट हो जायेगा कि वह सरकार की नियमावली का कितना पालन करवा रहा हैं और स्वयं भी कितना कर रहे हैं? कई बालू माफियाओं ने लोकसभा चुनाव 2019 के रणभूमि में उतरे पर संसद भवन नहीं पहुंच सके। राजनीति एवं अपराधिक दुनिया के दबंगों की मिलीभगत के साथ प्रशासनिक गुटबाजी के कारण सोने का भंडार बालू का चोरी बदस्तूर जारी है।

गौरतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार ने उपभोक्ता से मिल रही शिकायत एवं आसमान छू रही बालू की किमत पर नकेल कसने के लिए ही बिहार में बालू उत्खान और पत्थर खनन के लिए 2017 में एक नियमावली बनी (बिहार लघु खनीज नियमावली 2017) ताकि बालू के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध के साथ ग्राहको को उचित दर पर बालू उपलब्ध कराया जा सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी के के पाठक का नाम भला कौन नहीं जानता और यह भी जानता है की श्री पाठक के रहते गैर कानूनी काम करना नामुमकिन है। सख्त एवं कठोर कानून को पालन कराने की क्षमता के के पाठक में जितनी थी वह आज के पदाधिकारियों में नहीं है। खनन विभाग कितना सक्रिय है और उसके पदाधिकारी कितने कारगर हैं यह बालू माफियाओं ने साबित कर दिया है। व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ति के लिए सरकार के राजस्व के साथ खिलवाड़ के साथ-साथ पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है और बालू के डस्ट से लोग गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो रहे हैं। सोन नदी के दोनों किनारे बालू का अवैध उत्खनन एवं ढुलाई का कार्य जारी है और अगर पुलिस विभाग एवं खनन अधिकारी ईमानदारी से जांच करेंगे तो

'' इस नदी पर बालू माफियाओं की नजर गड़ी है की जब तक इसको पूरी तरह से लूटकर बर्बाद नहीं कर दिया जाये। सोन का बालू (रेत) सोना की तरह बेशकिमती है जिसको दबंग इसको पारस पत्थर भी मानते हैं, जो इस व्यवसाय से जुटा या जानकारी रखी वह भी धनपति हो चुका है। सूत्र बताते हैं की सोने की तरह चमकने वाले बालू की कीमत को समझने वाला ड्राईवर, इससे जुड़ा मुंशी - मैनेजर भी मालोमाल हो चुके हैं पर अपनी बदहाली पर आसूं बहा रहा है सोन नदी। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी बचा लिजिए सोन नदी को। ''

प्रत्येक महीने की अवैध कमाई 20 लाख रूपये से कम नहीं है और उससे अधिक अनुपात में खनन विभाग भी वूसली कर रहा है। अगर वसूली नहीं हो रही है तो जिलाधिकारी के द्वारा गठित टास्क फोर्स क्या कर रहा है? थाना क्या कर रही है? खनन विभाग का पदाधिकारी क्या कर रहा है? मीडिया भी इस गोरखधंधे में किसी न किसी रूप में शामिल है? पटना से आरा – सासाराम – बक्सर वाली मुख्य सड़क की स्थिति का जायजा अब उसी वक्त लग जायेगा जब बिहटा चौक से कोईलवर तक की यातायात को समझेगी। कोईलवर पुल पार करना किसी जंग में जीत से कम नहीं है और कोईलवर पुल के दोनों तरफ के पुलिस की वसूली यह साबित भी कर देती है की वह बालू माफियाओं से कितना मधुर संबंध रखते हैं। लघु एवं सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया बांध पर सड़क करोड़ों रूपये की लागत से बनाया गया परन्तु बालू लदे डंफर की रफ्तार से सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं बचा है। कोईलवर पुल से बिहटा की तरफ आने-जाने वाले यात्री सड़क एवं जाम की त्रासदी से त्राहीमाम कर रहे हैं। एक से बड़े एक दिग्गज बालू की माफियागिरी में लगा हुआ है। ब्राडसन कंपनी इन दिनों काफी सुर्खियों में है और अपने ही पार्टनर के बीच पिछले वर्ष गोलीबारी एवं मारपीट भी हुई थी और FIR भी दर्ज किया गया था। गुड्डू खान के अलावा 25 ऐसे लोग इस धंधे में शामिल है जिन्होंने सरकारी नियमों के आड़ में प्रशासनिक पदाधिकारी के मिलीभगत से आंख में धूल झोंक कर बालू से करोड़ों रूपये अवैध रूप में वसूल रहे हैं।

यह तस्वीर किस नियम का पालन करती दिख रही है? इस दृश्य को देखकर तो नहीं लगता की सूबे में सुशासन का राजपाट है? खनन विभाग के पदाधिकारी एवं पुलिस विभाग का इस जगह पर डियूटी कर रहा अधिकारी और कर्मचारी की आर्थिक स्थिति का जायजा निगरानी लेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

यह विडम्बना नहीं तो और क्या है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला नालन्दा में भी बालू के सौदागरों ने नदी तो नदी आस-पास का क्षेत्र को भी रौंदते हुए बर्बाद कर रहा है। बिहार सरकार के खनन विभाग के साथ पुलिस के पदाधिकारी की मिलीभगत ने बालू के सौदागरों को इतना शक्तिशाली बना दिया है की वह सरकार के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। ज्ञात हो कि बिहार में चर्चित नदियों में गंगा नदी, घाघरा नदी (सरयू नदी), गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, अजय नदी, कर्मनाशा

ओवरलोड बालू से भरा यह ट्रक परिवहन कानून का धज्जियां उड़ा रहा है। बालू से भरा ट्रक से पानी गिरने पर कठोर सजा एवं जुर्माना के बाद भी खुलेआम बालू माफिया स्थानीय पुलिस एवं खनन विभाग के पदाधिकारी से मिलीभगत करके ऐसा कृत्य कर रहे हैं। सड़कों पर कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदनाम हो उसका पूरा ख्याल शराब माफिया एवं बालू माफिया पदाधिकारी से मिलीभगत करके कर रहे हैं तथा एक तरफ सरकारी खजाना खाली हो रहा है तो दूसरी तरफ थाना एवं खनन विभाग के साथ एमवीआई के पदाधिकारी रातो-रात करोड़पति हो जा रहे हैं। बालू लदे ट्रक एवं डंफर अपने उपर हो रहे भ्रष्टाचार का सबूत देते हैं पर देखने वाला और उसपर कार्रवाई करने वाला विभाग ही जब आँख मूंद ले तो माफिया भला किसी के कंट्रोल में रहेंगे। करोड़ों की लागत से बनी सड़क भी ओवरलोड की वजह से असमय ही दम तोड़ देता है।

नदी, चानन नदी, क्यूल नदी, सकरी नदी को बचाकर पर्यावरण का सुरक्षित रखा जा सकता है लेकिन बालू के ठेकेदार उसपर गिद्ध दृष्टि लगाये बैठे हैं जिसका साथ स्थानीय पुलिस देती है जिससे सामाजिक रूप से आवाज उठाने वाले भी डर से दुबक जाते हैं। रोहतास जिला के नासरीगंज थाना क्षेत्र के तिलौथू, इंद्रपुरी, डालमियानगर, दरिहट घाट आदित्य मल्टीकॉम कंपनी के नाम से निबंधित है लेकिन निबंधित घाट के अलावा आस-पास के अन्य जगहों से बालू का उत्खनन होने के कारण से गोलीबारी का होना लाजमी है। लाल बालू, पीला बालू और उजला बालू का अपना-अपना दर है। बिहार में 502 बालू घाटों में सबसे अधिक घाट पटना में है और लगभग 83 घाट हैं जहां से बालू का उठाव होगा। महज 145 घाट पर ही कांटा है जिसमें 17 पटना में भी है। ज्ञात हो कि खनन विभाग के जारी आदेशानुसर अब बालू खनन से संबंधित जिलों को खनन से पहले पर्यावरणीय क्लियरेंस लेना जरूरी होगा।। यह अनुमति क्लियरेंस जिलों में DEIAA कर देना है, इसके बाद ही इन कलस्टरों से बालू खनन संभव है। बांका, नालन्दा गया और औरंगाबाद बालू के अवैध व्यापार को लेकर हमेशा चर्चा में बना हुआ है। औरंगाबाद के बारूण थाना एवं प्रभारी बिरेन्द्र पासवान सुर्खियों में है। प्रत्येक दिन गाड़ी पकड़ी जाती है और देर रात तक वसूली करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही कई कारणों क वजह से बिरेन्द्र पासवान को एसपी दीपक वर्णवाल से फटकार लग चुकी है तो व्यवहार न्यायालय ने आधा वेतन भी काट लिया है। बिहटा थाना के प्रभारी भी कई बार निलंबित हो चुके हैं। बालू के खेल में सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं पत्रकार भी शामिल हैं। सबका उद्देश्य बालू से अकूट संपत्ति अर्जित करना है, इस वजह से सड़क खराब हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, धूल के प्रकोप से गंभीर बीमारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार से गलत संदेश जा रहा है, नदी का अस्तित्व खतरे में है जैसी समस्या से निजात कैसे मिले इसपर ध्यान गाहे -बेगाहे देने वाला सरकार एवं पुलिस प्रशासन भी माफियाओं से मिल गया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नदी एवं व्यवस्था दोनो जर्जर होता जा रहा है।

सर्वविदित हो कि मुख्य सचिव बिहार तथा पुलिस महानिदेशक बिहार के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्रांक 3536 दिनांक 19/09/2014 तथा पत्रांक 330 दिनांक 29/01/215 एवं प्रधान सचिव खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से पत्रांक 4141 दिनांक 04/12/2015 पत्रांक 4398 दिनांक 31/12/2015, 1815/एम दिनांक 04/07/2016, 404/एम दिनांक 09/02/216 दिनांक1242/एम, दिनांक 27/04/2016 एवं 4106/एम दिनांक 20/12/2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षक को अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। लेकिन सच यही है की स्थानीय प्रशासन एवं खनन विभाग अधिकारी से मिलकर बालू माफिया सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम के लिए समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला में टास्क फोर्स का गठन हो जाता है। बालू की लीला में बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27/02/2012 को दीपक कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य से संबंधित मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा नयी बालू नीति तैयार कर अधि सूचना संख्या-2214/एम दिनांक 27/08/2013 द्वारा

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

के के पाठक, आईएएस

अधिसूचित किया जा चुका है। साथ ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 में आवश्यक संशोधन वर्ष 2014 में की गई है। नई बालू नीति तथा बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती पंचांग वर्ष 2014 से 2019 (05वर्ष) के लिए लोक नीलामी के माध्यम से की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27/02/2012 को SLP (C) 19629/2009 में पारित न्यायादेश के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण तथा वैज्ञानिक ढ़ंग से खनन कार्य हेतु निम्न दिशा-निर्देश निगत किये गये हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता, माईनिंग प्लॉन की अनिवार्यता, खनन पट्टा की न्सूनतम क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, खनन पट्टा की न्यूनतम अवधि वर्ष, बालू बंदोबस्ती हेतु नदीवार स्टेज का निर्माण, बालू उत्खनन से संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक है लेकिन यह सब सिर्फ कागजों में एवं विभागों में ही सुशोभित होता है।

बताते चलें कि बालूघाटों की बंदोबस्ती पंचांग वर्ष के आधार पर जिलावार एक इकाई के रूप में लोक नीलामी के माध्यम से की जाती है। नई बालू नीति में संशोधन नियमावली निहित प्रावधानों के अनुसार पटना, भोजपुर एवं सारण जिलों को एक इकाई रोहतास एवं औरंगाबाद जिलों को एक इकाई तथा जमुई एवं लखीसराय जिलो को एक इकाई के रूप में बंदोबस्ती का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य के 29 जिलों में बालू खनिज उपलब्ध है। इन जिलों को 25 बालू घाटों इकाईयों के रूप में संगठित किया गया है। लखीसराय, जमुई एवं सहरसा जिला के बालू बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती छोड़े जाने के कारण नये सिरे से बंदोबस्ती की कार्रवाई की गयी है। पूर्णिया एवं गोपालगंज जिला का बंदोबस्ती नये सिरे से की जा रही हैं। ज्ञात हो कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनन एवं स्टॉक के पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र का होना अति आवश्यक है। इसी संदर्भ में प्रत्येक बंदास्तीधारी/अनुज्ञप्तिधारी को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. - 1533क, दिनांक 14/09/2006 के निबंधनों के अनुसार वैध पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही साथ बंदास्तीधारी/अनुज्ञप्तिधारी भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला समाहर्ता द्वारा समस-समय पर निर्गत पर्यावरणीय संरक्षण और पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र से संबधित अन्य अनुदेशों का अनुपालन करेगा। लेकिन बिहार के पटना, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद सहित सोन नदी के सटे घाटों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के आदेशों का पालन तो दूर स्थानीय प्रशासन से मिलकर बालू माफिया सरकार के राजस्व पर डाका तो डाल ही रहे हैं बल्कि पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। अवैध बालू का कारोबार करने वाले माफियाओं से कहीं अधिक स्थानीय थाना एवं खनन पदाधिकारी जिम्मेवार हैं। सोन नदी के सटे थाना में प्रभारी बनने के लिए मुंहमांगी किमत देनी पड़ती है की चर्चा भी जोरो पर है। खनिज विकास निधि बनाकर सरकार सभी बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति अथवा अस्तित्व जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हो, खनिज विकास निधि में प्रति वर्ष पट्टा राशि का 02 प्रतिशत जमा करेगा, जिसे इस नियमावाली के अध्याय XVI में यथा उपदशित खनिज विकास फाउंडेशन

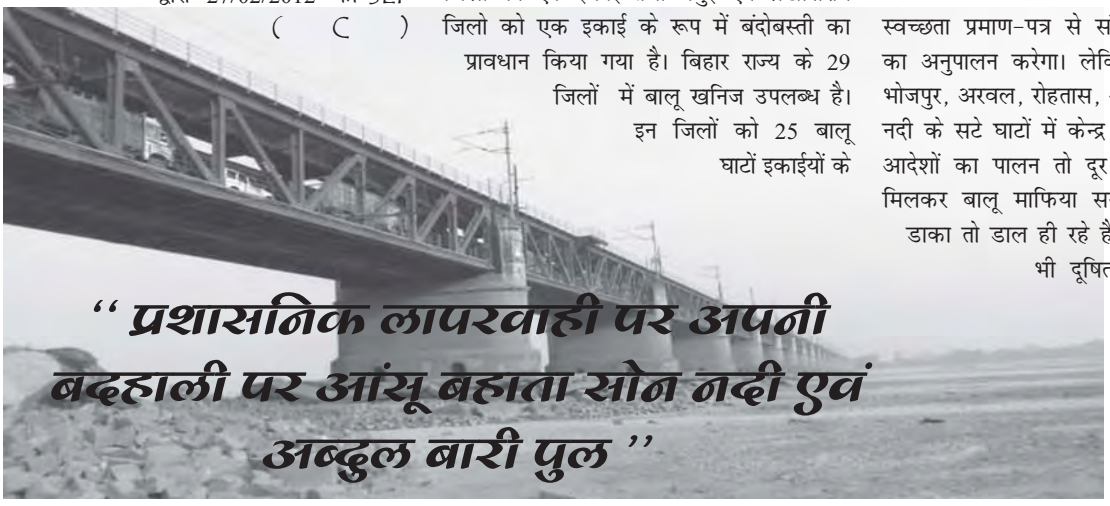
" प्रशासनिक लापरवाही पर अपनी बदहाली पर आंसू बहाता सोन नदी एवं अब्दुल बारी पुल "

द्वारा संचालित किया जायेगा। परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अंशदान का घटा एवं बढ़ा सकती सकेगी। सभी बालों घाटों पर शारीरिक श्रमिकों को महत्व देना भी अनिवार्य है। बालू घाटों के दशा में पोकलेन, लोडर्स, उत्खनक आदि जैसी किसी मशीन अथवा उपस्कर को समान्यतया उत्खनन के प्रयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। (1) बालू घाटों से बालू का उत्खनन अधिमानत: शारीरिक श्रमिक का उपयोग कर किया जाना चाहिए, परन्तु विभाग अथवा समाहर्ता किसी आपात स्थिति में अथवा श्रमिक की कमी होने पर उपर उल्लेखित मशीनों के प्रयोग की अनुमति दे सकेगा। (2) पर्यावरण के दृष्टि से बालू घाटों तथा उनकी परिस्थिति को संरक्षित करने के प्रयोजनार्थ विभाग और अधिक मार्गदर्शन निर्धारित कर सकेगा।

बताते चलें कि बालू घाटों पर खनन के लिए सामान्य प्रतिबंधित क्षेत्र:- (1) रेल पुल अथवा सड़क पुल से 300 मीटर तक खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी। (2) किसी श्मशान भूमि/धार्मिक स्थान से 50 मीटर तक खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी। (3) नदी के दोनों तरफ जल स्त्रोत 5 मीटर अन्दर खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी। (4) उपयुक्त के अतिरिक्त समाहर्ता खनन योजना में ही हरेक पट्टा के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

सर्वविदित है की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अधिकार दलित एवं महादलित को अपने प्रदेश में दिलवाया वह काबिले तारिफ हैं लेकिन दबंग आज भी सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए आज भी उनपर शोषण होता है जिसमें प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। ज्ञात हो कि बिहार सरकार ने वर्ष 1988-89 में पटना जिला के बिहटा थानाक्षेत्र के परेव के समीप बिन्दौल गांव में भूमिहीन 42 दलितों को 2-2 एकड़ जमीन दिया था, जिसका खाता संख्या-410 एवं प्लॉट संख्या 1856,1857, 1858 और 1859 है। इस जमीन से यह परिवार अपना जीवन यापन करता रहा है तथा सरकार को लगान भी देता रहा है लेकिन सोन बालू की बढ़ती मांगी और सोने की तरह बहुमूल्य किमत की वजह से बालू में माफिया का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है तथा एक महीने के बाद बरसात आ जायेगा के कारण से स्थानी दबंग बालू माफिया बन चुके हैं और सोन नदी का बालू का बहुमंजिला ईमारत जितना स्टॉक कर रहे हैं तथा नदी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। चिन्ता तो इस बात का है की इस कार्य में थाना एवं खनन विभाग के सक्रियता चरम पर है। दिनांक 02 जून 2019 को बिन्दौल के दलित जिनको बिहार सरकार ने जमीन आवंटित किया था उसी जमीन से जबरन रास्ता बनाकर बालू के सौदागर दलितों की जमीन कब्जा करना चाहते हैं की घटना की लिखित शिकायत (FIR) बिहटा थाना दर्ज की गई है जिसका कांड संख्या 520/2019 है। इस के अनुसंधान का दायित्व एसआई मनोज कुमार को मिला है। अब देखना यह होगा की बालू के सौदागरों के साथ यह कितनी सख्ती से निपट कर दलितों के जमीन को कब्जामुक्त कराते हैं या फिर सौदा करके स्थिति को यथावत बना दिया जायेगा? साथ ही साथ लिखित शिकायत जिलाधिकारी पटना को दिया गया है। खनन विभाग के प्रधान सचिव जब तक के० के० पाठक थे, तब तक बालू माफियाओं के लिए यमराज थे जहां नियम-कानून का पालन करना मजबूरी थी लेकिन आज बिहार के सभी 502 छोटे - बड़े घाटों से बालू की अवैध निकासी कर एक तरफ नियमों का सत्यानाश किया जा रहा है तो दूसरी तरफ नदी को बर्बाद किया जा रहा है। बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए के के पाठक ने ऑन-लाईन ई-टेंडर कराकर घाटों को आवंटित किया था तथा चलान के माध्यम से बालू की उपलब्धता को सुनिश्चित किया था पर बालू के सौदागरों की राजनीति के कारण के के पाठक को ही विभाग से तबादला हो गया लेकिन बालू के सौदागर की करतूत पर कोई कारवाई नहीं हुई। पिछले वर्ष भी बालू की हिस्सेदारी को लेकर कोईलवर एवं परेव के दो दंबगों के बीच आपसी मारपीट एवं गोलीबारी भी हुई थी। जिसकी प्राथमिकी दर्ज हुई लेकिन बालू से अकूट संपत्ति अर्जित करने की लालच एवं पार्टनर होने की वजह से मामला सोन नदी में दफन हो गया। चर्चा है की सोन नदी के बालू के अवैध कमाई में बिहार के कई एमएलसी कई - कई प्रतिशत हिस्सेदार हैं क्योंकि पूंजी उन्ही का है। वैसे तो कई माफियाओं का नाम उजागर हो चुका है तो कई सफेदपोश शराबबंदी की भारपायी कर रहे हैं और बदनाम मुख्यमंत्री हो रहे हैं। देश का प्रधान चौकीदार प्रधानमंत्री ने भी दलितों को बहुत सम्मान दिया है और एक मजबूत एक्ट भी बनाया लेकिन उसको उसका वाजिब हक नहीं मिलता और केन्द्र सरकार का पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है।

अब देखना है की बिहार के सूबेदार नीतीश कुमार इस गंभीर समस्या के निदान करते हुए बालू माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए सरकारी खजाने को भरा जाये तथा सोन नदी के अस्तित्व को बचाया जाये पर कितना सक्रिय होते हैं। वक्त रहते अगर सोन नदी से निकल रहे अवैध बालू को नहीं बचाया गया तो नदी भी इतिहास के पन्नों में सिमट जायेगा एवं पर्यावरण भी बिहार के कई जिलों का खराब हो जायेगा कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा। खनन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी के साथ लालची पुलिस पदाधिकारियों पर भी अंकुश लगाना होगा अन्यथा यह सभी मुख्यमंत्री को बदनाम करेंगे और अपनी नीजी संपत्ति बढ़ा लेंगे। बालू माफिया सिर्फ सोन नदी ही नहीं बल्कि विभिन्न नदियों को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करके नदी को खंडहर में तब्दील कर देंगे और सरकार सिर्फ जांच कमिटि गठन करके अपना पल्ला झाड़ लेगी।

मोदी सरकार का एक्सटेंशन

● अमित कुमार

एक बार फिर चौकीदार छा गया और वह भी ऐसा कि जिस चौकीदार को चोर बोलने वाले थे, वह विपक्ष में आज बैठने के लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2019 में राजग की सुनामी ऐसी आयी जिसने उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं सहित विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी की बोलती ही बंद कर दी। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक में भी माहौल भाजपामय नजर आया। ये मंजर कुछेक राज्यों का ही नहीं बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि भगवा किस तरह लहराने लगा है। एक तरफ 303 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी स्वयं खड़ी है तो इनके सहयोगियों ने भी 50 सीटों के साथ जीत हासिल कर 303+50 = 353 के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर 'चौकीदार चोर' जैसे अनुशासनहीन शब्दों के पर फूलस्टॉप लगा दिया। हालांकि इस सुनामी के कई मायने गिने जा सकते हैं। एक तरफ स्वयं मोदी विश्व पटल पर अपनी पहचान एक कद्दावर नेता के तौरपर बना चुके हैं तो दूसरी तरफ इनके रणनीतिकार कहे जाने वाले सहयोगी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरह देश के हर चुनावी क्षेत्रों को ध्यान देते हुए जो रणनीति बनायी, वह कारगर साबित हुए। हालांकि विकास के साथ हिन्दुत्व को लेकर चलने वाले मोदी का फैक्टर अप्रत्याशित चुनावी जीत में अहम माना जा रहा है।

गौरतलब हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव को मोदी के लिए ही जाना जाएगा, क्योंकि लोकसभा के 543 सिटों पर मोदी ही खड़े थे, ऐसा देखा गया है। सनद् रहे कि वह न सिर्फ चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा थे बल्कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी थे। लोगों ने वोट भी उन्हीं के नाम पर दिए। मोदी ने देश भर में घूमकर माहौल को भगवामय कर दिया। विपक्ष इस अंडरकरंट का अंदाजा भी नहीं लगा पाया। इस चुनाव की सबसे अहम बात यह रही कि मतदाताओं ने स्थानीय उम्मीदवार को महत्व देने बजाय मोदी के चेहरे को ही सामने रखा। दूसरी तरफ देखा नरेंद्र मोदी ने देश में विकास तो बहुत किया, लेकिन चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना कारगर साबित हुआ। देखा जाये तो उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में यह मुद्दा काम कर गया। लोगों को मोदी की बात समझ में आ गई और उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर

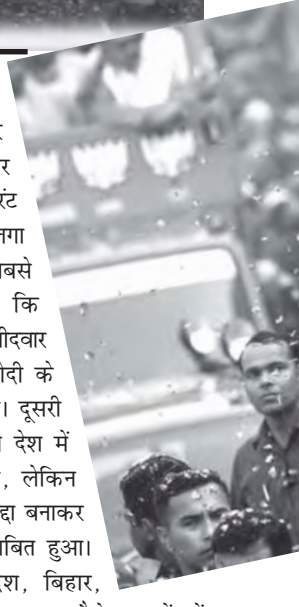

राजग और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर मतदान किया। ज्ञात हो कि चुनाव पूर्व पुलवामा की आतंकी घटना के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को भी लोगों ने उनके पक्ष में मतदान कर सराहा। मोदी ने जिस अंदाज में पाकिस्तान में स्थित आतंकियों से पुलवामा हमले का बदला लिया, लोगों को उनका यह अंदाज भा गया। इतना ही नहीं मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को जमकर सबक सिखाया। एक और बात यह भी थी कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में भी बेहद आक्रामक तरह से प्रचार किया। उनके कद के सामने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी समेत सभी नेता बौने नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। उनके आक्रामक चुनावी प्लान ने विपक्ष को भाजपा के समने धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में मोदी ने 'चौकीदार चोर' के जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को ही कठघरे में खड़ा कर कांग्रेस को राजीव गांधी के नाम पर ही चुनौती दे दी थी। इस चुनाव में एक चीज और देखा गया कि हिन्दुत्व का बड़ा मुद्दा भी एक बार पुनः साबित हुआ। उदाहरण के लिए देखे तो जिस तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैलियों में जमकर राम के नाम पर नारे लगाए गए। पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तरप्रदेश और बिहार में भी इस

मुद्दे ने अपना काम किया। साथ ही पार्टी ने उन्नाव से साक्षी महाराज, सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और अलवर से बाबा बालकनाथ को टिकट दिया। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ाकर भाजपा ने अपने पक्ष में मतों का सफलतापूर्वक

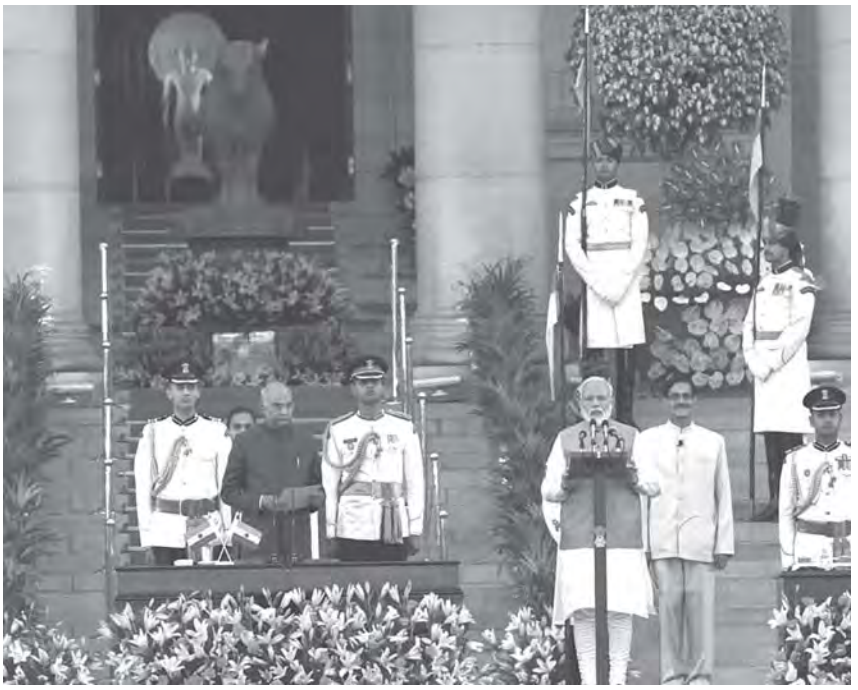

ध्रुवीकरण किया।

गौरतलब है कि इस चुनाव में एनडीए पहले की अपेक्षा ज्यादा एकजुट नजर आया। उद्धव ठाकरे जैसे असंतुष्ट सहयोगी नेताओं को भाजपा ने सफलतापूर्वक साधा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नामांकन के समय प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों को आमंत्रित कर एकजुटता का प्रदर्शन भी किया गया। मोदी ने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में भी सभाएं करने में गुरेज नहीं किया और जहां आवश्वकता थी इन दिग्गजों को भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया। यही कारण रहा कि एनडीए ने बिहार और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी भाजपा का चुनाव प्रचार बेहद आक्रामक था। राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन चलाया गया। देखते ही देखते भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 'मैं भी चौकीदार' लिख दिया। बस फिर क्या था, उनके प्रशंसकों के साथ ही आम लोगों में भी मोदी के इस अभियान से जुड़ने की होड़ मच गई। भाजपा ने हैशटैग्स का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया और इस माध्यम का जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल किया गया। इस सुनामी के समर में अगर विपक्षी उसमें समा गये तो इसके लिए चुनावी प्रबंधन कमिटि को भी माना जा सकता है और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का बेहतरीन चुनाव प्रबंधन भी भाजपा को इस चुनाव में बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ अगर कहे तो गलत नहीं होगा। वही पार्टी के शीर्ष नेताओं में जबरदस्त समन्वय दिखाई दिया। हालांकि टिकट के बंटवारे पर कयास लगाये जा रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी इस मैदान में होंगे किन्तु उन्हें चुनाव में खड़ा नहीं किया गया, बावजूद इन बड़े नेताओं में पार्टी के प्रति त्याग और समन्वय बना हुआ देखा गया। दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में जहां मोदी गए, वहां अमित शाह नहीं गए और जहां अमित शाह पहुंचे, वहां मोदी नहीं पहुंचे और इस प्रकार दोनो ने चुनाव प्रचार का जिम्मा बांटकर इस जीत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करा दी है।

सनद् रहे कि 2019 की 17वीं लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों पर सबकी निगाहें थीं, उनमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पर था। बीजेपी ने इस बार अपनी सीटें बढ़ाने के लिए यहां पूरी ताकत झोंक दी थी। नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लगातार बढ़ती कड़वाहट के तौर पर सामने आया। लगभग तीन महीने से दोनों दलों और उसके नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का

जो दौर चला, उसकी बंगाल के चुनावी इतिहास में दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान होने वाली हिंसा से दोनों दलों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अपनी रणनीति में बीजेपी को भारी कामयाबी भी मिली और उसके सीटों की तादाद जहां दो थी, वह बढ़कर 18 तक पहुंच गई। वहीं वोट भी वर्ष 2014 के 17 फीसदी के मुकाबले बढ़ कर 40 फीसदी से ज्यादा हो गए। नतीजों के बाद दो दिनों तक चुप्पी साधे बैठी ममता ने इसकी समीक्षा के लिए अपने आवास पर आयोजित पार्टी की आपातकालीन बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश कर सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी पर आपातकालीन हालात पैदा करने, केंद्रीय बलों को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने और चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया। लेकिन पार्टी के तमाम नेताओं ने एक स्वर में उनकी इस पेशकश को खारिज कर दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दरअसल, इस्तीफा देने की पेशकश कर एक तीर से दो शिकार करने का प्रयास किया गया है। इससे उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वास्तव में वह बंगाल के लोगों की सबसे बड़ी हमदर्द हैं और दूसरे वे आम लोगों से भावनात्मक रूप से और मजबूत जुड़ाव चाहती हैं। ममता अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी जगह लेने वाला पार्टी में कोई नहीं है। बावजूद इसके आठ साल पहले सत्ता में आने के बाद चुनावी नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पहली बार इस्तीफे की पेशकश की थी। ममता ने भगवा पार्टी की चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वही बीजेपी की चुनौती से निपटने की खातिर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए ममता कुछ कड़वे फैसले भी ले सकती हैं। अब उन्होंने सांगठनिक मामलों पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया है। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बंदूक की नोंक पर पार्षदों को अपने खेमे में ले जा रही है। दूसरी ओर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, ''अब टी-20 मैच शुरू हो गया है और पार्टी का लक्ष्य कम से कम ओवरों में अधिक से अधिक रन बनाना है।" वह कहते हैं कि लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी का लक्ष्य अगले साल होने वाले कोलकाता नगर निगम चुनावों में जीत कर निगम पर कब्जा करना है। दूसरी ओर मुकुल राय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के दो और माकपा के एक विधायक ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें मुकुल राय के पुत्र व बीजापुर सीट से तृणमूल विधायक शुभ्रांशु राय, बिष्णुपुर के तृणमूल विधायक तुषार भट्टाचार्य और हेमताबाद के माकपा विधायक देवेंद्र नाथ राय शामिल हैं। पचास से ज्यादा पार्षदों के पाला बदलने की वजह से बीजेपी ने एक झटके में उत्तर 24-परगना जिले की चार नगरपालिकाएं तृणमूल के कब्जे से छीन ली हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के रणनीतिकार माने जाने वाले मुकुल राय दावा करते हैं, कि तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। धीरे-धीरे उनको शामिल करने के बारे में फैसला किया जाएगा। वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, कि अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में तृणमूल के कई और नेता व विधायक भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में बीजेपी व तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़पे हुई। उत्तर 24-परगना व नदिया जिले में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसके अलावा कूचबिहार, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर व दक्षिण 24-परगना जिलों में इन झड़पों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो हो गये। उत्तर 24-परगना जिले के भाटपाड़ा इलाके में तो मतदान के पहले से ही हिंसा होती रही है। इस इलाके से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चार बार विधायक रहे अर्जुन सिंह ने इस बार बैरकपुर संसदीय सीट पर बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए पूर्व रेल मंत्री व तृणमूल उम्मीदवार दिनेश त्रिवेदी को हरा दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ममता की असली चिंता अगले साल होने वाले कोलकाता नगर चुनाव और वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव हैं। यहाँ नगर निगम चुनावों को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। एक राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, कि बीजेपी भले शहरी इलाकों की लोकसभा सीटें तृणमूल से छीनने में नाकाम रही हो, किन्तु उसने निगम के 144 में से 53 वार्डों में बढ़त बना चुकी है। इसी तरह विधानसभा की 294 में से 128 सीटों पर पार्टी को तृणमूल के मुकाबले ज्यादा वोट मिले हैं। कोलकाता नगर निगम बोर्ड

पर तृणमूल का कब्जा है। ऐसे में ममता और तृणमूल के लिए खतरा गंभीर हो गया है। इसी वजह से ममता ने भावी खतरों गंभीरता समझते हुए उनसे निपटने के लिए अभी से ही कमर कस ली है। उन्होंने कुछ मंत्रियों के विभाग बदल डाले हैं तो कुछ की छुट्टी ही कर दी है।

बहरहाल पश्चिम बंगाल के बाद पड़ोसी राज्य बिहार की अगर बात करे तो यहां इस 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे से स्पष्ट हो गया कि बिहार में भी एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर थी और विपक्ष इसे भांपने में नाकामयाब रहा। स्पष्ट तौरपर बिहार में भी इस चुनाव में राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। साथ ही, एनडीए के चुनावी प्रबंधन और रणनीति का भी तड़का लगा और उसने 40 में 39 सीटें झटक लीं। एनडीए शुरू से इस चुनाव की ठोस तैयारी करके चल रहा था। चाहे वह सीटों का चयन हो या उम्मीदवारों का बिल्कुल आसानी से और समय पर इसका बंटवारा कर लिया गया। बिहार में सीट बंटवारे से लेकर प्रत्याशियों की घोषणा और चुनाव प्रचार में जदयू की एकता सामने आयी थी। दूसरी ओर महागठबंधन को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली। इसके पीछे न सिर्फ इस घटक दलों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर पर सवाल उठे, बल्कि प्रचार के दौरान भी एकजुटता की भारी कमी दिखी। तीन नए दलों- हम, वीआईपी और रालोसपा को लेकर उसने अपना कुनबा तो बढ़ा लिया, मगर इसका लाभ गठबंधन को नहीं मिला। ज्ञात हो कि 2014 के लोकसभा

चुनावों में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 31 पर भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत हुई थी, जिनमें 22 सीटें अकेले भाजपा ने जीती थी और 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। 40 में से 39 सीटों पर बिहार में एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल कर ली। एक अकेले किशनगंज की सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर जावेद ने करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वही पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती को फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा और इस सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने जीत दर्ज कर ली। दूसरी तरफ बेगूसराय से मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार को बड़े अंतर से हराया। हालांकि गिरिराज चुनाव से पहले बेगूसराय भेजे जाने से नाराज थे, फिर भी मोदी की सुनामी में वह जीत हासिल कर लिये। सनद् रहे कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा को 1 लाख 90 हजार से अधिक वोटों से हराया।

बताते चले कि महागठबंधन का जातीय समीकरण और जातिगत आंकड़ा इन चुनावों में पूरी तरह से फेल होता नजर आया। लालू यादव के परिवार के दोनों सदस्य समधी चंद्रिका राय और बेटी मीसा भारती को हार झेलनी पड़ी। बिहार में मुस्लिम-यादव गठजोड़ की जो बात कही जाती रही, वह जमीन पर वोट में बदलते नहीं दिखे, बहरहाल लोकसभा चुनाव 2019 में आरजेडी खाता भी नहीं खोल पायी। चुनाव में जीत और बहुमत को लेकर लालू के छोटे बेटे व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस प्रकार से महागठबंधन के लोगों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार की दिशा तय करते नजर आये, उनकी सक्रियता पर पानी फिर गया। चुनाव के कुछ समय पहले ही महागठबंधन का हिस्सा बनी ''हम, वीआईपी और रालोसपा'' का जातीय समीकरण वाला जादू भी काम नहीं कर पाया। विडम्बना है कि कल तक लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व 'माय' समीकरण को पूरा भंजाया गया था और मुस्लिम तथा यादव एक साथ लालू प्रसाद के साथ चलने को तैयार थें, आज तेजस्वी यादव

ने वीआईपी की जोरदार प्रस्तुति से निशाद वोटरों की सेंधमारी को लेकर जो मुनिया (मुस्लिम+निषाद+यादव) को बनाया, वह फार्मूला भी फेल हो गया। वही लालू प्रसाद यादव का इस लोकसभा चुनाव में नेतृत्व न होने के कारण पूरा महागठबंधन का कूनबा मोदी की सुनामी में बह गया और जो थोड़ी इज्जत बचाने में कामयाब भी रहा तो सिर्फ किशनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ० जावेद ही रहे थे। इस चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार तो दूर, मीसा भारती को भी जीत नहीं दिला सके भाई तेजस्वी यादव। 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम हर किसी को सन्न कर गया। जिस तरह से पूरे देश के परिणाम एनडीए के पक्ष में आए, तमाम राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक यह सोचते रह गए कि यह मोदी लहर थी, आंधी थी या सुनामी। महागठबंधन की अगुवाई करने वाली आरजेडी को एक सीट तक मयस्सर नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी की राजनीति में यह पहला मौका बन गया, जब आरजेडी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं होगा। महागठबंदन के सबसे बडे नेता बने तेजस्वी यादव अपनी बडी बहन मीसा भारती को जीत नहीं दिला सके। अब सवाल यह उठना लाजिमी है कि क्या नेता के रुप में तेजस्वी यादव फेल हो गए? बिहार में लोकसभा के जिस तरह परिणाम आए, शायद इसकी इतनी उम्मीद तो खुद बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने भी नहीं की होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन के दलों में चुनाव में नरेन्द्र मोदी को चुनौती दी थी, परिणाम ने शायद इस चुनौती को बुरी तरह नकार दिया। अपने सहयोगियों को जिताना तो दूर खुद तेजस्वी अपने उम्मीदवारों तक को भी नहीं जिता पाए। मीसा भारती जो उनकी बडी बहन हैं और पाटलिपुत्र से उम्मीदवार थी, वह भी रामकृपाल यादव से हार गयी। इस हार के बाद कई तरह के सवाल पार्टी और लालू राबडी परिवार के भीतर उठेंगे कि अपनी बडी बेटी मीसा भारती और बडे बेटे तेजप्रताप यादव के नजरअंदाज कर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकार सौंपा था, क्या तेजस्वी उस पर खरे नहीं उतर पाए? क्या चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के भीतर अंहकार आ गया और महागठबंधन की सारी रणनीति अपने मुताबिक की? यहां तक कि अपने सहयोगियों को भी नजरअंदाज किया। खुद उनके परिवार में उनपर मनमाना करने के आरोप लगे। पूरे चुनाव अभियान में तेजस्वी के बडे भाई तेजप्रताप यादव ने कई मोर्चों पर उनका विरोध किया। टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के नेताओं पर भी कई बार सवाल खडे किये। यहां तक कि उन्हें अपने साथ चुनाव प्रचार में साथ ले जाने के लिए गिडगिडाते रहे, लेकिन तेजस्वी ने हर बार अपने बडे भाई को नजरअंदाज किया। ऐसे में जाहिर है कि चुनाव के रिजल्ट में आरजेडी की दुर्दशा पर तेजप्रताप चुप नहीं रहेंगे। वहीं, आरजेडी के उत्तराधिकार पाने की इच्छा पालने वाली मीसा भारती के लिए भी पार्टी की हार को पचाना मुश्किल होगा। अब तक तो मीसा भारती ने चुप्पी साधी, लेकिन यह चुप्पी कब तक रहेगी, कहना मुश्किल है। एक ओर पहले से ही पूरा परिवार मुश्किल में है, ऐसे में इस हार ने पूरे परिवार को और मुश्किलों में डाल दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेजस्वी के लिए बडा नेता बनने के लिए यह एक बडा सुनहरा अवसर था, लेकिन तेजस्वी ने इसे गंवा दिया। दूसरी तरफ आरजेडी की इस हार ने लालू प्रसाद यादव के विरोधियों को और खुलकर हमला करने का मौका दे दिया है। मीसा भारती को हराने वाले रामकृपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बहुत जल्द आरजेडी नाम वाली पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी आने वाले दिनों में इस तरह के और बयान आएंगे। बिहार में अब अगला लक्ष्य अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इस हार से आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पर बुरा असर पड़ना लाजिमी है। ऐसे में परिवार और पार्टी को बचाना तेजस्वी के लिए बडी चुनौती होगी।

विडम्बना है कि खुद को तार्किक, पढ़ा-लिखा और समझदार मानने वाले पत्रकारों-विश्लेषकों-बुद्धिजीवियों को नरेंद्र मोदी की जीत ने सकते में डाल दिया है। मोदी को मिली इस दूसरी जीत को वे चुनाव नतीजों के आने से पहले बिल्कुल नहीं भांप पाए। राजनीति अनिश्चित को निश्चित बनाने का खेल है और मोदी-शाह की जोड़ी ने यह कारनामा कर दिखाया है। लिबरल, मध्यमार्गी, वामपंथी या सेक्युलर धारा के पत्रकार सही भविष्यवाणी करने में अपनी नाकामी को लेकर सदमे में हैं, मानो ऐसा पहली बार हुआ हो। लेकिन यह सच नहीं है, 2004 के 'इंडिया शाइनिंग' वाले चुनाव में भी उन्हें नतीजे की भनक नहीं लगी थी और भी कई मिसालें हैं। मोदी और उनके साथी जिसे 'खान मार्केट गैंग' या 'लुटिएंस इंटेलेक्चुअल्स' कहते हैं, वह तबका जरूर सोच रहा होगा कि उसमें 'रॉ विज्डम' की कितनी कमी है। जीते हुए मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री बनने से पहले, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद इस राज से पर्दा उठाया है कि लिबरल राजनीतिक विश्लेषक क्यों नाकाम हुए। विजेता मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम गणित होता है। पिछले चुनाव अंकगणित के दायरे में चले होंगे लेकिन 2014 का चुनाव हो, 2017 (यूपी

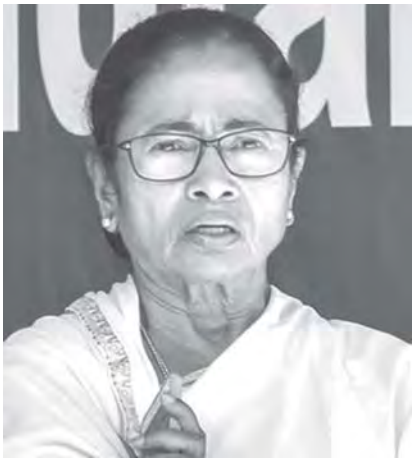

विधानसभा) का, या फिर 2019 का। इस देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि अंकगणित के ऊपर केमिस्ट्री होती है। समाज शक्ति की केमिस्ट्री, संकल्प शक्ति की केमिस्ट्री कई बार अंकगणित को परास्त कर देती है। हार्वर्ड बनाम हार्डवर्क वाली अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने हार्वर्ड वालों के जले पर नमक छिड़का। तीन-तीन चुनावों के बाद पॉलिटिकल पंडित नहीं समझे, तो इसका यही मतलब है कि उनकी सोच बीसवीं सदी वाली है जो अब किसी काम की नहीं है। जिन लोगों की सीवी 50 पेज की होगी, इतना पढ़े-लिखे हैं, इतनी डिग्रियां हैं, इतने पेपर लिखे हैं, उनसे ज्यादा समझदार तो जमीन से जुड़ा हुआ गरीब आदमी है। जो जीता वही सिकंदर, मारे सो मीर, विजेता ह ी

इतिहास लिखता है... ऐसे मुहावरे हम सब जानते हैं, मोदी एक अजेय नेता की तरह बात कर रहे हैं, तार्किक विश्लेषण करने की कोशिश करने वालों को वे भावनाओं की राजनीति से फिलहाल पीट चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए यूपी विध ानसभा चुनाव का जिक्र तो किया लेकिन दिल्ली और बिहार की हार को सफाई से गोल कर गए।

ज्ञात हो कि पिछले चुनावों के आंकड़े, राज्यवार विश्लेषण, नए बने गठबंधन और कृषि संकट जैसे ठोस मुद्दों का असर, इन सबका तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण गणित था। यहां तक कि बीजेपी के समर्थक समझे जाने वाले पत्रकार भी तार्किक विश्लेषण के बाद यही कह रहे थे कि सीटें कुछ घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं। यह बात गलत साबित हुई, गणित पिट गया। अब बात केमिस्ट्री की, जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण कठिन है, ये चीजें हैं देशभक्ति की भावना, भगवत भक्ति का पुण्य प्रताप, घर में घुसकर मारा जैसे मुहावरों का असर, बदला लेने और दुश्मन को डरा देने के बाद ताल ठोकने का सुख, इनके असर को कोई विश्लेषक कैसे मापेगा? बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पुलवामा और बालाकोट की घटना से काफी पहले साफ शब्दों में कहा था, चुनाव काम से नहीं, भावनात्मक मुद्दों से जीते जाते हैं। विकास नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चुनावी भाषणों में फुटनोट की ही तरह रहा, ऐसा नहीं है कि उनके पास गिनाने के लिए उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-धन योजना, किसान सम्मान निधि जैसी चीजें नहीं थीं, लेकिन उनका ज्यादा जोर पाकिस्तान/मुसलमान, देश की सुरक्षा, राष्ट्र का गौरव, भारत माता की जय और कांग्रेस की खानदानी राजनीति से हुए नुकसान पर केंद्रित रहा। वही जनभावना को समझने और उसका राजनीतिक दोहन करने के मामले में नरेंद्र मोदी इतने योग्य निकले कि बुद्धिवादी, तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच रखने का दम भरने वाले लकीर पीटते रह गए, फैक्ट चेक करने वाले पत्रकारों की ट्रेनिंग 'इमोशन चेक' करने की नहीं रही है। जनता के मूड को भांपने का हुनर शायद उन्हें नए सिरे से सीखना होगा। लोग खुलेआम कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, लेकिन वोट तो मोदी जी को दूंगा, आवारा गाय-बैल खेत चर रहे हैं लेकिन वोट मोदी जी को दूंगा, नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ लेकिन वोट मोदी जी को दूंगा...इन आवाजों को ज्यादातर पत्रकारों ने सुना लेकिन वे इससे यह मतलब नहीं निकाल पाए कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वे क्यों नहीं समझ पाए? इसलिए कि ज्यादातर पत्रकार ऐसे लोगों को परंपरागत मोदी भक्त मानते रहे जो उनकी नजर में पहले से कमिटेड वोटर थे। इन्हें नया वोटर मानने से लिबरल मीडिया ने इनकार कर दिया, एंटी इनकंबेसी का तर्क दिया गया, महागठबंधन को दलित+पिछड़े+मुसलमान = निश्चित जीत मानने की गलती गणित पर डटे सभी पत्रकारों से हुई। कहा गया कि मोदी यूपी के नुकसान की भरपाई बंगाल और ओडिशा से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड जैसे सभी राज्यों में बीजेपी की सीटों में कमी आने को एक ठोस तर्क माना गया, खास तौरपर उन राज्यों में जहां कुछ ही महीने पहले बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी थी, लेकिन इन सभी राज्यों में मोदी के नाम पर लड़ रहे उम्मीदवारों ने 2014 से ज्यादा सीटें बटोर लीं। लिबरल पत्रकार और विश्लेषक सरकारी योजनाओं का फैक्ट चेक कर रहे थे, बता रहे थे कि गैस का सिलिंडर तो मिला है, लेकिन अगले सिलिंडर के लिए पैसे नहीं हैं। इसी तरह शौचालय तो बने हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है या फिर जन-धन खाते खुले तो हैं लेकिन उनमें पैसा नहीं है। मुद्रा

लोन इतना कम है कि उससे कोई क्या कारोबार शुरू करेगा...वगैरह वगैरह। ये सब बातें तार्किक हैं और वास्तविक हैं लेकिन झोंपड़ी में रखे खाली ही सही, लाल सिलिंडर को देखकर गरीब को हर बार मोदी याद आता है, यह देखने में राजनीतिक पंडित चूक गए। इसके अलावा जिन लोगों को फायदा मिला या नहीं मिला, उन लोगों में अगली बार मोदी सरकार के आने पर कुछ और फायदे मिलने की जो उम्मीद जगी, उसे मापने का कोई तरीका पत्रकारों के पास शायद नहीं था। सरकार, मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ गुस्सा है लेकिन इसके बावजूद 'मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं' जैसे नारों का मर्म ज्यादातर विश्लेषक पूरी तरह समझ नहीं पाए। विपक्षी दलों और बीजेपी के परिश्रम की तुलना नहीं की जा सकती, टीवी पर रात दिन दिखने, तरह-तरह के इंटरव्यू से लेकर नमो चैनल तक, प्रचार बंद हो जाने के बाद गुफा में ध्यान लगाने के दृश्यों, मीडिया और सोशल मीडिया पर मोदी के छाये रहने के असर को तथाकथित तार्किक आकलन में फैक्टर नहीं माना गया। यही कहा गया कि लोग समझदार हैं टीवी देखकर वोट नहीं देते। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जैसे संस्थानों की बुरी हालत और रफेल जैसे मुद्दों को समझने-समझाने का दावा करने वाले पत्रकार मानने लगे कि जनता भी उनकी ही तरह सब कुछ समझ-बूझ रही है जिसका नुकसान मोदी को उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हर बार केमेस्ट्री यानी भावनात्मक मुद्दों की ही जीत होगी और ठोस तार्किक बातों की अहमियत खत्म हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि भावनाओं की राजनीति के असर को परखने के लिए हर बार तर्क का चश्मा काम नहीं आएगा।

गौरतलब हो कि कश्मीर में विवादित धारा 370 और 35ए का मसला इतना गंभीर है, जिसे हटाने को लेकर वर्षों से चर्चा होती रही किन्तु यह हो नहीं सका, कारण बस रहा तो इस क्षेत्र के अलगाववादी नेताओं के देशविरोधी कट्टरता का। हालांकि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पूर्व में भी इस धारा को हटाने का आश्वासन दिया था और इस बार 2019 के चुनाव में तो भाजपा ने अपने द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्र में तो धारा 370 और 35ए को हटाने का संकल्प लिया है। वही भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र में जारी इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि अगर भाजपा 2020 तक धारा 370 और 35ए हटाने का डेटलाईन दी है तो वह जम्मू-कश्मीर के साथ भारत के रिश्ते का आखिरी डेटलाईन होगा और जम्मू-कश्मीर का भारत से विलय संघ खत्म हो जायेगा। यह बयान शायद घाटी में रह रहे कश्मीरियों को पसंद नहीं आया, बाबत महबूबा मुफ्ती की हार हुई। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की छह में से तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और तीन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। हिंदू बहुल जम्मू डिविजन की दो सीटें (जम्मू और उधमपुर) और गैर-मुस्लिम बहुल लद्दाख सीट बीजेपी की झोली में बरकरार रही हैं, जबकि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई है। 2014 लोकसभा चुनाव में तीन सीटें जीतने वाली पीडीपी इस बार वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। जम्मू-कश्मीर में इस बार बीजेपी को 46.39% वोट मिले जबकि 2014 में उसे 32.4% मत मिले थे। पीडीपी 2.37% वोट ही ले पाई जबकि 2014 में उसे मिले मतों का प्रतिशत 20.5% था। 2008 के विधानसभा चुनावों से लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जम्मू क्षेत्र में लगातार बढ़ा है। यह बात वोट प्रतिशत में भी देखने को मिलती है और सीटों की संख्या में भी। बहुत से विश्लेषक जम्मू और लद्दाख में बढ़ते बीजेपी के इस प्रभाव के लिए कश्मीर के साथ बढ़ती खाई और ध्रुवीकरण को मुख्य वजह मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि 2019 चुनाव के नतीजों में भी इसी क्षेत्रीय और धार्मिक विभाजन की झलक देखने को मिली है। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना हैं कि 2014 में हुए संसदीय और फिर विधानसभा चुनावों में ही जम्मू और कश्मीर के बीच का क्षेत्रीय विभेद स्पष्ट हो गया था। नवंबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटें और फिर बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। बीजेपी जम्मू डिविजन से ये सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जबकि पीडीपी की अधिकांश सीटें घाटी से थी। इससे पहले उसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटों पर भी जीत हासिल की थी। जम्मू में 2008 में हुए अमरनाथ भूमि विवाद के बाद से कम्यूनल राजनीति की करंसी कैश कर गई है, तब से धीरे-धीरे विभाजनकारी राजनीति जम्मू क्षेत्र में पनप रही थी। उसी की नतीजा है कि जो बीजेपी जम्मू में कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जो मात्र पांच-छह सीटें यहां जीत पाती थी, उसने 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीती थीं, जो बड़ी बात थी। जम्मू क्षेत्र कश्मीर

के बीच हमेशा से खाई रही है और इसका अक्स चुनावों के परिणामों में भी देखने को मिलता है। जम्मू में किसी और पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं और कश्मीर में किसी और को। जम्मू क्षेत्र और कश्मीर के बीच में हमेशा से विभाजन रहा है। बस एक बार जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ था, तभी जम्मू के साथ-साथ कश्मीर में भी एक जैसा रुझान देखने को मिला था। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जम्मू में आमतौर पर कांग्रेस अधिकतम सीटें जीतती थीं, मगर अब उसकी जगह बीजेपी ने ले ली है। इसकी वजह क्या है? जम्मू की राजनीति पर बाकि देश की राजनीति का असर रहता है। उनका मानना है, आज तो जम्मू में बीजेपी को स्पेस मिल गया है वरना यहां कुछ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले जाती थी तो कभी पीडीपी भी। इनका भी कुछ जगहों पर असर था। कांग्रेस तो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख- तीनों क्षेत्रों में सीटें लाती रही है। मगर 2014 के बाद से जब देश मे हवा बदली है तो जम्मू में भी बदलेगी ही। जम्मू की राजनीति में पिछले 10 सालों में खासा बदलाव आया है। 10-15 साल में, खासकर 10 सालों में यहां का माहौल कश्मीरी विरोधी बन गया है। जो कश्मीर कहेगा, हमें उससे उल्टा करना है। ऐसा मानते हैं जैसे राष्ट्रवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया हो। कश्मीरियों को एंटी-नेशनल माना जाता है। तो एंटी-कश्मीर और प्रो-इंडिया पॉलिसी के मिलन से बनी भावना ही तय करती है कि जम्मू में चुनाव के दौरान किसे फायदा होगा। वही जम्मू क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत यहां के बदले हुए राजनीतिक हालात को बयां करती है। जम्मू के अधिकतर इलाकों में पीडीपी और एनसी का अच्छा खासा वोटबैंक है, जहां मुस्लिम आबादी है। दोनों के उम्मीदवार न होने पर माना जा रहा था कि यह वोटबैंक कांग्रेस को ट्रांसफर हो सकता है। बीजेपी के बागी भी चुनाव मैदान में थे। 2014 की तरह मुस्लिम और सेक्युलर वोटों के बंटने की संभावना भी इस बार नहीं थी। मगर नतीजे बताते हैं कि जम्मू में कम्यूनल राजनीति किस हद तक बढ़ चुकी है। सनद् रहे कि जम्मू से सीटें जीतने वाली बीजेपी और कश्मीर से सीटें जीतने वाली पीडीपी ने राज्य में सरकार चलाने के लिए जो गठबंधन बनाया था, उससे जम्मू और कश्मीर के करीब नहीं आए बल्कि दूर हो गए। जो विभाजन पहले से था, बीजेपी के समय और गहरा हो गया। बीजेपी-पीडीपी का गठबंधन दूरी को कम करने के बजाय इसे और बढ़ाने वाला बन गया। इस गठबंधन के कारण ही पीडीपी को नुकसान झेलना पड़ा है कि उसे एक भी सीट नहीं मिली और यहां तक कि महबूबा मुफ्ती को भी हार का मुंह देखना पड़ा। गौरतलब हो कि पीडीपी कहती थी कि हम हिंदुत्व को बाहर रखेंगे मगर फिर बीजेपी के साथ गठबंध न करके उसी को गले लगा लिया। फिर कश्मीर वादी का सूरते हाल भी बहुत बदला। 2016 में बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान पैलट गन के इस्तेमाल और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से पीडीपी का ग्राफ नीचे गिरा। इससे महबूबा मुफ्ती ने भी अपना जनाधार खो दिया। हालांकि कश्मीर में मतदान कम हुआ है और ऐसी स्थिति में यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी का प्रभुत्व बढ़ा या घटा है। वह कहती हैं, कश्मीर में चुनावी राजनीति को लेकर उदासीनता है। पार्टियों ने जनसभाएं नहीं कीं, रोड शो नहीं हुए।

खैर जो भी एक पीडीपी अध्यक्ष की घाटी में हार होने उनकी गिरती राजनीतिक साख का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और पुन: मोदी की अप्रत्याशित जीत का फायदा बहुत जल्द शायद भारत के नागरिकों को मिल सकेगा और धारा 370 और 35ए को खत्म करने के लिए अब विपक्ष में ऐसा कोई नहीं है जो इस मसले पर ज्यादा विरोध कर सकेगा। ऐसे भी देश ने मोदी को एक बार फिर से जनादेश दिया और इस जनादेश की एक ही व्याख्या है और वो दो शब्द हैं-नरेंद्र मोदी। ये जीत नरेंद्र मोदी की है। लोगों की जिस तरह की आस्था उभरी है उनमें वो अप्रत्याशित है। भारत की आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी एक व्यक्ति का हिंदू समाज पर इतना प्रचंड रौब और पकड़ राजनीतिक दृष्टि से बन गई है। ऐसा न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था और न ही इंदिरा गांधी के जमाने में। अगर इसको बड़े समीकरण में देखें तो लगभग 50 प्रतिशत वोट शेयर, सारी संस्थाएं बीजेपी के हाथ में हो जाएंगी। अगर कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तो राज्यसभा की संख्या में भी तब्दीली होगी। इनके पास सिविल सोसाइटी का जो संगठन है आरएसएस और जो तमाम दूसरी संस्थाएं हैं, वो अपनी तरह की सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारत की राजनीति में ये मौका बिल्कुल अप्रत्याशित है। अब अगर ये पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है तो इसके कई कारण बताए जा सकते हैं। जब हार होती है तो कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं। ये जरूर है कि विपक्ष बहुत कमजोर था। हर तरह से कमजोर था। रणनीति में कमजोर था। विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर गंठबंधन नहीं कर पाया, उसने जनता को एक तरह से ये ही संदेश दिया कि इनमें कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोच सकता है। कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना पाए। अगर आप देखें तो पिछले पांच दस साल में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का थीम ये रहा है कि भारत में एक पुरानी व्यवस्था थी। वो पुरानी व्यवस्था नेहरू-गांधी परिवार से जुड़ी हुई थी। वो व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। उस व्यवस्था ने भारत को गरीब रखा। 2014 में ये व्याख्या नरेंद्र मोदी के बड़े काम आई। उस समय सत्ता विरोधी वोट था। लेकिन पिछले पाँच साल में अगर आप कांग्रेस का विश्लेषण करें तो प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने के सिवाए किसी भी राज्य में किसी भी स्तर पर कांग्रेस के संगठन में कोई परिवर्तन आया क्या? यहां मोदी बात कर रहे हैं सांमतवादी राजनीति की और वशंवादी राजनीति की। कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीतती है। (राजस्थान के मुख्यमंत्री) अशोक गहलोत पहला काम क्या करते हैं जोधपुर में टिकट देते हैं (अपने बेटे) वैभव गहलोत को। (मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री) कमलनाथ पहला काम क्या करते हैं अपने पुत्र को छिंदवाड़ा से टिकट देते हैं। मोदी ने जो व्याख्या बना रखी है कि पुरानी व्यवस्था है वो इतनी कमजोर और परिवार पर निर्भर हो चुकी है कि उसमें तो कोई दम बचा नहीं। अगर ये सवाल करें कि ये जीत किस विचारधारा की जीत है तो ये बहुसंख्यकवाद की जीत है। स्वतंत्रता के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है। लोग मानते थे कि भारतीय राजनीति का केंद्र हमेशा सेंट्रिस्ट (मध्यमार्गी) रहेगा। लोग मजाक करते थे कि बीजेपी को अगर जीतना होगा तो उन्हें भी कांग्रेस की तरह बनना पड़ेगा। लेकिन वो मध्यमार्ग आज खत्म हो चुका है।

इस चुनाव में नकारात्मक प्रचार हुआ। अली-बजरंग बली की जो फ्रेमिंग थी। प्रज्ञा ठाकुर जैसे उम्मीदवार को लाया गया। ये कह सकते हैं कि 2014 में नई बात थी। आर्थिक विकास की बात थी। लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखें तो उनकी ज्यादातर बातें इसी दिशा में ले जाती हैं। या तो परिवारवाद के खिलाफ या फिर गर्व से कहें हम हिंदू हैं। तो हमें इस निष्कर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए कि ये बहुसंख्यकवाद की जीत है। मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है। तीन चार विषय हैं। भारत की नई पीढ़ी ने राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस का क्या बलिदान था, ये नहीं देखा है। उत्तर भारत में राजीव गांधी के बाद कांग्रेस का जबर्दस्त क्षरण शुरू हुआ। इनके पास उत्तर भारत में अच्छी

हिन्दी बोलने वाला ढंग का एक प्रवक्ता तक नहीं है। कांग्रेस सभी गुटों का विश्वास खो बैठी। उत्तर प्रदेश में हिन्दू दलितों और मुसलमानों का विश्वास खो बैठी थी। सवाल ये है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो उन वर्गों को जाकर ये विश्वास दिला सके कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपके प्रगति और विकास की बात करेंगे। उनमें भी एक धारणा बन गई कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उसे मुसलमानों में दिलचस्पी नहीं है। बीस-तीस साल तक इसका अंदाजा नहीं हुआ। वजह ये है कि उत्तर भारत में मंडल कमिशन के बाद से मंडल और कमंडल की राजनीति थी। एक तरफ हिंदुत्व का ध्रुवीकरण और उसको तोड़ेंगी जातियों वाली पार्टियां। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि अब ये जातीय और सामाजिक समीकरण को नए भारत में कामयाब बनाना बहुत मुश्किल है। दलित वोट भी आज बँट गया है। मायावती के पास जाटव के अलावा ज्यादा दलित वोट नहीं है। कांग्रेस और बाकि दल अब भी पुराने समीकरण में फंसे हुए हैं। इस समीकरण को मोदी 2014 में ही पछाड़ चुके थे। एक तरह से बीजेपी में ऊपर से आक्रामक राष्ट्रवाद है। मर्दवादी राष्ट्रवाद है, लेकिन ये भी सच है कि मोदी ने कहा कि वो महिलाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। गैस सिलिंडर दे रहे हैं। स्वच्छ भारत कर रहे हैं। क्या आप कांग्रेस का कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां वो कह सकें कि ये मुद्दा कल का है, हम इसे लेकर चलेंगे? कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत अच्छा था। लेकिन घोषणा पत्र को आप चुनाव के दो महीने पहले जारी करते हैं। भारतीय मतदाता मजबूत सुप्रीम कोर्ट और मजबूत निर्वाचन आयोग के महत्व को समझता है लेकिन अगर ये संस्थाएं मजबूत नहीं हैं तो इनका दोषी किसे ठहराया जा रहा है? लोग इसके लिए नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। वो इसके लिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं। वो मानते हैं कि ये वर्ग इतना बिकाऊ हो गया है कि उसे खत्म कर सकते हैं। दोष किसका है? आप कह सकते हैं कि सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है लेकिन ये प्रश्न तो उठता ही है कि जिस संस्थान के पास इतनी शक्तियां थीं वो संस्था अगर अंदर से खत्म हो रही है और स्वायतत्ता रखने वाले शैक्षणिक संस्थान खत्म हो रहे हैं तो उसका पहला दोष किसको जाएगा? उसका दोष संस्थान के पुराने अभिजात्य वर्ग पर होगा। अगर आप जनता से जाकर कहें कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफदारी कर रहा है तो वो पहला सवाल ये पूछेंगे कि इतने समर्थ जज अगर सरकार की चापलूसी कर रहे हैं तो इसमें सरकार को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? भारतीय समाज का आज का संकट ये है कि पुराने दौर के अभिजात्य (इलीट) वर्ग की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई है। मोदी बड़ी होशियारी से वही संकेत देते हैं। लुटियन्स दिल्ली, खान मार्केट गैंग। आप मजाक कर सकते हैं कि ऐसा कोई गैंग नहीं है लेकिन वो इस बात का सूचक बन गया है और लोगों के मन में ये घर कर गया है कि भारत का जो उच्च मध्यम वर्ग है, वो इतना बिकाऊ है कि अगर ये संस्थाएं खत्म हो रही हैं तो इसका दोष मोदी को नहीं इन संस्थाओं को जाना चाहिए। सवाल उठता है कि मीडिया के लिए दोष किसको दें? मोदी को दें या उन संस्थाओं के मालिकों को दें? जब ये कहा जाता है कि पत्रकारिता निष्पक्ष थी, निडर थी तब सवाल होता है कि कहां निष्पक्ष और निडर थी। वो निष्पक्षता के नाम पर पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहती थी। मैं नहीं कहता कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन जनता यही कह रही है। हमें इस बात का जवाब देना होगा कि हमारे समाज में क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि लोगों पर उनके झूठ का कम प्रभाव होता है और जो भी उस झूठ को उजागर करता है, उसके बारे में माना जाता है कि इसका कोई स्वार्थ है। ये सही है कि जहां भी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आती है, उसके खतरे होते हैं। प्रजातंत्र में वो अच्छा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक सामाजिक समीकरण भी है। इनका एक सांस्कृतिक एजेंडा है। ये कहा करते थे कि अल्पसंख्यको का हिंदुस्तान की राजनीति में एक वीटो था, जिसे हम अल्पसंख्यकों को बिल्कुल अप्रासंगिक कर देंगे। ये इनकी विचारधारा में निहित है। आज मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है।

गौरतलब है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से जो पार्टी का हार्डकोर धड़ा है, वो सवाल करेगा कि अगर अब आपने हिंदुत्व विचारधारा को स्थापित नहीं किया संस्थाओं में तो कब करेंगे? इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? ये दबाव आएगा तो मुझे नहीं लगता कि मोदी इसे रोकेंगे या पीछे हटेंगे। इसी चुनाव में देखा गया है कि मानक बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। दस साल पहले क्या कोई कल्पना करता था कि प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की स्टार उम्मीदवार होंगी। उनकी जीत पर आज जश्न मनाया जा रहा है। ये एक तरह का जहर है जिसे आप दोबारा बोतल में नहीं डाल सकते हैं। बहुसंख्यकवाद के खतरे इस चुनाव में बड़ी स्पष्ट रूप से उभरकर आए हैं। ये चुनाव उन परिस्थितियों में हुआ जहां भारत की आर्थिक व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है जितना प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। वास्तविक ग्रोथ रेट चार या साढ़े चार प्रतिशत है। बेरोजगारी की समस्या है, कृषि क्षेत्र में संकट है। इस सबके बाद भी अगर जनता ने इन्हें वोट दिया है तो यही निष्कर्ष निकलता है कि वो मजबूत नेता चाहते थे। दूसरा आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां बहुसंख्यकवाद का बहुसंख्यकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। वो समझते हैं कि हमें कोई क्या कर लेगा। ये भारतीय लोकतंत्र का बड़ा नाजुक मोड़ है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है तो कहा जा सकता है कि ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन ये उदारता की जीत नहीं है। ये संवैधानिक मूल्यों की जीत नहीं है। हम ऐसा भारत बनाएं,

जहां हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो, उसे ये खतरा नहीं रहे कि मैं जिस समुदाय से आता हूं, उसकी वजह से मुझे कोई खतरा है। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से एक सबक लिया जाना चाहिए कि वो लंबे वक्त के लिए धैर्य के साथ रणनीति बनाते हैं। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से लंबा खेल खेल रही है। अगर चुनाव में हार होती है तो सांस्कृतिक संस्थाओं पर ध्यान देते हैं। राजनीति में पीछे छूट जाते हैं तो सामाजिक काम करते हैं। उनकी रणनीति का ठोस आधार ये है कि एक ही बात को बार-बार बोलते जाइए ताकि कोई ये न कहे कि आप अपने लक्ष्य से हट गए हैं। रणनीति चुनाव के बीच में शुरू नहीं की जा सकती। कांग्रेस की ओर से देखें तो उनकी चुनाव मशीन पिछले साल या डेढ़ साल में सक्रिय हुई है। कांग्रेस के पास पैसे की कमी थी। हालांकि, कांग्रेस वाले खुद ही मजाक करते थे कि कांग्रेसी अमीर हैं, कांग्रेस पार्टी गरीब है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता चौबीस घंटे पार्टी के लिए काम करता है। रणनीति में आपको संगठन और विचारधारा चाहिए। 2014 में जब बीजेपी की जीत हुई थी, उसके दो साल पहले से माहौल बनाया जा रहा था कि हमारे सिस्टम में ये खामियां हैं। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। वक्ताओं की बात करें तो कांग्रेस में ऐसे दो या तीन नेता खोजने मुश्किल हैं जो हिंदी में अच्छे वक्ता हों। मजबूत सरकार के रहते संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती की बात करें तो सेना जैसी संस्थाएं जो पूजनीय मानी जाती थीं जिस पर कोई राजनीतिक आक्षेप कभी नहीं लगता था। पिछले छह से आठ महीने में उसका राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग हुआ है। आर्थिक तौर पर भी नाजुक दौर है। केवल मजबूत सरकार स्थिति दुरुस्त रखने की गारंटी नहीं देती। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो इस जनादेश का इस तरह इस्तेमाल करें कि भारत के संवैधानिक मूल्य सुरक्षित रहें और आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे। लेकिन जिस तरह का चुनाव अभियान था और जिस तरह के तत्व अब राजनीति में हैं, लगता है कि वो उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे।

बहरहाल 23 मई के चुनावी परिणाम के बाद एनडीए ने 30 मई को मोदी पार्ट-2 के सरकार गठन हेतु नये-पुराने मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन परिसर में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि उक्त अवसर पर सभी विपक्षी दलों के नेताओं, एनडीए समर्थित राज्य के सभी मुख्यमंत्री सहित 7 हजार लोगों को निमंत्रण दिया था। इस शपथ समारोह कार्यक्रम में में मुख्य

अतिथि के तौरपर छः देशों के संगठन बिमस्टेक को बुलावा था। हांलाकि भारत की ओर से मोदी ने इस शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया, जिससे पाकिस्तान में बहस का माहौल बना हुआ है। विदित हो कि समारोह में भारत और छह अन्य देशों के संगठन बिमस्टेक के सभी देशों- नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद के अलावा मॉरिशस और किर्गिस्तान के भी राष्ट्राध्यक्ष इस शपथ समारोह में शामिल हुए। मगर इस बार भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी उम्मीदें थीं कि वो भी भारत के इस बेहद खास पल का गवाह बनता। सनद् रहे कि पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी बढ़ी है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर चुनावी रैली में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। हालांकि चुनावों में उनकी प्रचंड जीत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस लहजे में उन्हें जीत की बधाई दी थी, उसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मोदी के राज्याभिषेक के मौके पर पाकिस्तान को बुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं इमरान खान ने चुनावों से पहले कहा था कि अगर भारत के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो शांति वार्ता की संभावना ज्यादा रहेगी। विदेशी पत्रकारों से बातचीत में इमरान ने कहा था कि बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी है और वो जीतती है तो कश्मीर को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। मोदी की जीत के बाद पाकिस्तान की मीडिया में इस बात पर बहस हो रही थी कि निमंत्रण मिलने पर प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत जाना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान की समा टीवी के न्यूज डिबेट में एंकर विश्लेषक से सवाल करती है, 'अगर न्योता दिया जाता है तो इमरान खान को भारत जाना चाहिए? विश्लेषक कहते हैं, मेरे ख्याल में जरूर जाना चाहिए। इमरान खान को मैं मुबारकबाद देता हूं। उनकी ख्वाहिश ये थी और उसका इन्होंने इजहार किया था कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुने जाते हैं तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की जीत पर संदेश भी भेजा था। वहीं दूसरे विश्लेषक कहते है, वो न भी जाएं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि समारोह में कोई बातचीत तो होगी नहीं। हां, अगर बातचीत के लिए विशेष तौर पर बुलाया जाता है तो परिणाम बेहतर निकलेंगे। क्योंकि जब इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, तो नरेंद्र मोदी नहीं आए थे।

खैर! 2019 का 17वां लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर काफी लंबा समय लिया गया, चुनाव अच्छे से कराये गये, परिणाम भी सामने हैं और रह गई बात मंत्रियों की सूचि की तो, मोदी सरकार पार्ट-2 में पुराने कई मंत्रियों के विभागों में फेर बदल किये गये है तो कुछ अभी भी उसी पद और विभाग में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है जबकि अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार 2 में पीएम मोदी समेत 58 मंत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली थी उनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 25 राज्य मंत्री

और 9 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शामिल हैं। शपथ लेने वाले 20 चेहरे मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए हैं।

विडम्बना है कि मोदी सरकार के पार्ट-2 में जहां बीजेपी और सहयोगी एनडीए के लोगों को मंत्रालय में जहां जगह दी गई तो वही भाजपा के पुराने सहयोगी जदयू के किसी भी सांसद को इस मंत्रीमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि इस निर्णय पर बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भले ही खुलकर अपनी बातों को नहीं रख रहे किन्तु कयास यह लगाया जा रहा था कि नीतीश सरकार में दो कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री की चाह रखे हुए थे, जिसे भाजपा ने ठुकरा दिया। इस बाबत बीते दिनों पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि एनडीए की बैठक के बाद संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमे श्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाकर हमलोगों ने समर्थन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के बुलावे पर 29 मई को हम दिल्ली गये थे। उसी समय यह बात कही गयी थी कि एनडीए के जिन घटक दलों के सांसद निर्वाचित हुए हैं, वैसे सभी दलों को मंत्री परिषद में सांकेतिक रूप से एक-एक सीट पर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी की लोकसभा में 16 जबकि राज्यसभा में 6 सीटें हैं जो सभी बिहार से हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए हमने कभी कोई प्रपोजल नहीं दिया। मंत्रिमंडल में सांकेतिक रूप से शामिल होने के मसले पर हमारी पार्टी की कोर टीम में शामिल नेताओं ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रि परिषद में शामिल होना ही साथ होने का प्रमाण नहीं है। हमलोग पूरे तौर पर एनडीए के साथ हैं। बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने गठबंधन किया था ताकि बिहार का पिछड़ापन समाप्त हो सके। इसलिए मंत्रि परिषद में हमारी पार्टी की भागीदारी नहीं होने से हमे कोई चिंता, परेशानी या अफसोस नहीं है। कैबिनेट में घटक दलों का आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हालांकि भाजपा को स्वयं पूर्ण बहुमत मिला है इसलिए वे निर्णय लेने के हकदार हैं। मंत्रि परिषद में सांकेतिक रूप से घटक दलों की भागीदारी हो, इसका निर्णय बीजेपी को करना था। बिहार में जो चुनावी कैंपेन किये गये, उसमें सबलोगों ने एक-दूसरे का साथ दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कैबिनेट में सांकेतिक रूप से भागीदारी को लेकर हमलोगों की कोई इच्छा नहीं है। केन्द्रीय कैबिनेट में सामाजिक समीकरण के सवाल पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इंकार करते हुए कहा कि यह उनका अंदरूनी मसला है। भाजपा की हारी हुई आठ संसदीय सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की है। किशनगंज के परिणाम की किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि भविष्य में केन्द्रीय कैबिनेट में जदयू के शामिल होने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि एलायंस में प्रारंभ में जो बातें होती हैं, वही आखिरी होती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सरकार को तय करना है कि आगे वे किस प्रकार से काम करना चाहेंगे। गठबंधन चाहे किसी से भी हो, हमलोग बिहार में गठबंधन के घटक दलों को आनुपातिक ढंग से मंत्रि परिषद में शामिल करते हैं। मंत्री पद को लेकर बिहार में किसका क्या कोटा होगा, वह पहले से ही तय है। उन्होंने कहा कि अटल जी के सरकार में भी यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन उस समय भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं था। अभी की बात अलग है क्योंकि भाजपा खुद पूर्ण बहुमत में है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रीपरिषद में सांकेतिक रूप से भागीदारी को लेकर किसी की कोई रूचि नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को इस बात को लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार में शामिल होना ही साथ रहने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पहले से ही हम यह कहते रहे हैं कि पिछड़े राज्यों को पिछड़ेपन से दूर निकालने एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष पहल करने की आवश्यकता है। धारा-370, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जैसे मसले पर हमलोगों की राय पब्लिक डोमेन में है। मुख्यमंत्री ने 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नवगठित मंत्रिपरिषद के सामाजिक समीकरण के प्रभाव से इंकार करते हुए कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा।

लिहाजा केन्द्र के मंत्री मंडल निर्णय पर भीतर ही भीतर दांत पिसते नीतीश कुमार ने केन्द्र के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तुरंत बाद ही बिहार में लंबे समय से रूके मंत्री मंडल के विस्तार को पूरा करने के लिए जदयू कोटे से 8 मंत्रीयों को शपथ दिलाया तो वही बिहार में एनडीए यानि सहयोगी भाजपा से किसी को भी मंत्री पद प्राप्त नहीं हुआ। अब इस खींचतान की शुरूआत पुन: बिहार एनडीए में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मोदी से नाराज नीतीश के इस रवैये पर चुटकी लेते हुए राजद प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने महागठबंधन में आने का पुन: स्वागत करते हुए कहा कि अगर नीतीश चाहे तो वह फिर से आ सकते हैं। अब देखना यह है कि बिहार में 17 वर्षों पुराना जदयू-भाजपा का रिश्ता

तिनके की तरह बिखर गया था, बाद में फिर से इस रिश्ते को मजबूत किया गया और अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इनके रिश्ते में पुन: दरार पैदा न हो जाये, जैसे हालात बता रहे हैं।

खैर! भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से नई सरकार बन गई है। नई सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा भारत की नई प्राथमिकताओं का संकेत है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा बढ़ाना और रोजगार का सृजन नई सरकार की चुनौतियां है। पांच साल पहले की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान को छोड़ दिया। पिछली बार सार्क के नेताओं को बुलाया गया था, इस बार बंगाल की खाड़ी पर बसे देशों के संगठन बिम्सटेक के देशों को बुलाया गया। यह फैसला विदेश नीति के क्षेत्र में दो संकेत देता है। एक तो पाकिस्तान को दरकिनार करने का संकेत, यदि वह आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को रियायतें नहीं देता। दूसरा संकेत यह कि भारत एक्ट ईस्ट को गंभीरता से ले रहा है और उसके लिए पूरब के पड़ोसी देशों के अलावा एशिया प्रशांत का इलाका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहेगा। यह इलाका अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक ओर चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और दूसरे इस इलाके को एशिया प्रशांत से इंडो प्रशांत का नाम देकर अमेरिका ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों के भविष्य को साफ कर दिया है। भारत ने भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ गुट बनाकर इस इलाके में अपनी दिलचस्पी का संकेत दे दिया है। अब पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को अपनी नई कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाकर मोदी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार के निशाने पर अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन होगा। जयशंकर चीन और अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं और विदेश सचिव के रूप में सामरिक महत्व के विषयों पर मोदी के साथ निकट रूप से काम कर चुके हैं। निर्मला सीतारामण को वित्त मंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और विदेश व्यापार के अपने अनुभवी सहयोगी को कारोबारियों में भरोसा बनाने और विदेशी सरकारों को आश्वस्त करने की जिम्मेदारी दी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। आर्थिक आंकड़ें भरोसा पैदा करने लायक नहीं हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन की दर पांच साल में सबसे कम 5.8 प्रतिशत रही और बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा रही। निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए भारत को भी बड़े औद्योगिक देशों की जरूरत है। मोदी की पहली सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी रोजगार के मोर्चे पर रही है। हालांकि हाल के चुनावों में यह कमजोरी राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दों के साए में ढंक गई, लेकिन अगले चुनाव

जीतने के लिए इसमें सफलता बहुत ही जरूरी होगी। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश के लिए कारोबार के आसान नियमों के अलावा घरेलू मोर्चे पर शांति तथा कुशल कामगारों की जरूरत होगी। कारोबार की शर्तों को और आसान बनाने की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण की होगी तो घरेलू मोर्चे पर शांति की जिम्मेदारी बीजेपी प्रमुख अमित शाह की होगी, जो मोदी के निकट सहयोगी हैं और जिन्हें मोदी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। अमित शाह को इन आशंकाओं को दूर करना होगा कि उनके गृह मंत्रालय का मुखिया बनने से भारत में सुरक्षा प्रतिष्ठानों में ध्रुवीकरण बढ़ेगा और उदारवादियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी ओर पार्टी के लिए दिखाया गया। उनका कौशल पुलिस सुधार और भारत को सुरक्षित बनाने के काम आ सकता है। वे गैर जिम्मेदार हिंदू संगठनों को भी अनुशासित कर सकते हैं, जो पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। उद्योग और व्यापार के लिए उचित माहौल बनाने की जिम्मेदारी नए मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय की होगी जो इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रमुख हैं। नरेंद्र मोदी का दूसरा मंत्रिमंडल अनुभव और नवीनता का मिश्रण है। आगे की सरकारों के लिए युवा राजनीतिज्ञों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी को मनमोहन सिंह पूरा नहीं कर पाए थे और यही कांग्रेस की हार का कारण भी बना था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से सबक लेकर नेताओं की ऐसी पौधा खड़ी कर रहे हैं जो उनके बाद भी देश को नेतृत्व दे पाए। देश के करीब-करीब हर राज्य को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी बनाने की भी नींव रखी है। विपक्षी दलों को कमर कस लेनी होगी। उनके लिए आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले।

विदित हो कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। भाजपा ने अकेले तीन सौ के आंकड़ों को पार किया और 303 सीटों पर जीत का परचम लहराने में सफल रही। अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ ने इस जीत को और प्रचंड बना दिया। एनडीए ने लोकसभा की कुल 353 सीटों पर कब्जा किया, वहीं कांग्रेस की अगुआई वाला यूपीए 92 सीटों पर सिमटकर रह गया। कांग्रेस के अकेले प्रदर्शन की बात करें तो काफी खींचतान के बाद पार्टी को महज 52 सीटों पर सफलता मिली। भाजपा

की इस बड़ी जीत के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने एक बार फिर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। 17वीं लोकसभा में सरकार के सामने आधिकारिक रूप से विपक्ष का नेता नहीं होगा। पिछली सरकार में भी ऐसी ही स्थिति थी। सदन में सरकार के सामने कई विपक्षी पार्टियां होती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस पार्टी को विपक्ष का नेता बनाने का मौका मिलता है जिसके पास कम से कम 10 फीसदी सीटें हासिल हों। यानी 543 सीटों वाले लोकसभा में विपक्ष का नेता उस पार्टी का होगा, जिसके पास कम से कम 55 सीट होंगी। इस बार कांग्रेस इस आंकड़े को छू पाने में सफल नहीं रही है। पार्टी के पास 52 सांसद हैं और विपक्षी नेता का तमगा हासिल करने से वो तीन पायदान नीचे रह गई। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस महज 44 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और उस बार भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिल पाया था। मोदी राज में न सिर्फ विपक्षी पार्टियों बल्कि विपक्ष के नेता के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में भारतीय लोकतंत्र किस ओर जाएगा? इस सवाल के जवाब में एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि हमारी संसदीय राजनीति में विपक्ष के नेता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान के अनुसार लोकतंत्र को चलाने के लिए होती है। संवैधानिक संस्थानों जैसे सीबीआई का निदेशक या सूचना आयुक्त की नियुक्ति या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में प्रतिपक्ष के नेता की बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष के नेता का ओहदा प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के स्तर का समझा जाता है। पिछली बार भी कांग्रेस इतनी सीटें नहीं ला पाई थी कि तकनीक तौर पर विपक्ष के नेता का दर्जा हासिल कर पाती, इस बार भी वो यह दर्जा पाने में नाकाम रही है। ऐसे में फर्क तो पड़ता है। जो आवाज एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हो सकती है, वो कृपा या सरकार की उदारता के कारण मिले दर्जे की नहीं हो सकती है।

ध्यान रहे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी समझा जाता है। विपक्ष सरकार के कार्यों और नीतियों पर सवाल उठाता है और उसे निरंकुश होने से रोकता है। संसद में अगर विपक्ष कमजोर होता है तो मनमाने तरीके से सत्ता पक्ष कानून बना सकता है और सदन में किसी मुद्दे पर अच्छी बहस मजबूत विपक्ष के बिना संभव नहीं है। भारतीय लोकतंत्र इस बात का गवाह रहा है कि जब भी कर्पूरी ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरोसिंह शेखावत, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता संसद में बोलते थे, सत्ता पक्ष उनकी बातों को संजीदगी से सुनता था। न सिर्फ सुनना, नीतियों और योजनाओं को विपक्ष की बहस से धार दिया जाता था और उसे जनोत्थान के लिए बेहतर समझा जाता है। एनडीए सरकार भी मजबूत विपक्ष के महत्व को समझती है। दिगर बात यह भी है कि सोलहवीं और सत्रहवीं लोकसभा के दौरान विपक्ष के नेता का न होने का यह पहला या दूसरा मामला नहीं है। इससे पहले, पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। इस दौरान कांग्रेस को सदन में 360 से 370 सीटें मिली थीं। उसके मुकाबले पहली तीन लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। सीपीआई को इस दौरान 16 से 30 सीटें ही मिली थीं। 1952 में देश में पहली बार हुए आम चुनावों के 17 साल बाद सदन को विपक्ष का नेता मिला। चौथे लोकसभा के दौरान साल 1969 में राम सुभाग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। उस लोकसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी में बंटवारे के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई थी और कांग्रेस के राम सुभाग सिंह को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता की मान्यता दी। वो 1970 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद कांग्रेस की जोड़तोड़ में कई बार कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए। 1979 में जनता पार्टी के जगजीवनराम पहले ऐसे गैर कांग्रेस नेता थे जिन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा मिला। पांचवें और सातवें लोकसभा के दौरान भी मुख्य विपक्षी दल के पास संख्या बल इतना नहीं था कि उनके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जा सके।

गौरतलब है कि मोदी की पिछली सरकार के दौरान कुछ चीजें पहली बार हुई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आरोप लगाया गया कि न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के दौरान भी उठापटक देखने को मिली। माना जाता है कि विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकार को अनेक बार अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं और वो निरंकुश नहीं होती। सनद् रहे कि पिछली बार भाजपा को 282 सीटें मिली थीं। लोकसभा में पार्टी बहुमत में थी, जिसकी वजह से कई विधेयकों को मंजूरी दिलाने में आसानी हुई। लेकिन तीन तलाक के मामले में यह विधेयक राज्यसभा में अटक गया। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सांसद हैं, जिनमें से 241 का चुनाव और चार सांसदों को नामित किया गया है। यहां भाजपा के 102 सदस्य हैं। राज्यसभा में बहुमत से पार्टी महज 20 सीटें कम है। विश्लेषकों के मुताबिक अगले साल भाजपा राज्यसभा में भी बहुमत में आ जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में बहुमत में आने के बाद भाजपा के लिए किसी भी कानून में बदलाव लाना और नया कानून बनाना आसान हो सकता है। लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्षी पार्टियां भी यह आरोप लगाती रही थीं कि इस बार भाजपा अगर सरकार बनाती है तो वो ऐसे फैसले लेगी, जो पहले कभी नहीं लिए गए हैं। हालांकि राज्यसभा में अगले एक साल तक एनडीए को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बाद जब गठबंधन वहां बहुमत में आएगा तो यह हो सकता है कि वो विवादित फैसले ले। तो क्या अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करने की ओर जाएगी पार्टी? भाजपा के घोषणा पत्र में जिक्र है कि उनकी सरकार अनुच्छेद 370 को हटाएगी। राम मंदिर बनाने का भी पार्टी का वादा है। चुनावों में पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया लेकिन उनके एजेंडे में यह शामिल है। जानकार बताते हैं कि ऐसे में साधु संन्यासी और संघ के कट्टर समर्थकों की ओर से यह दबाव बनाया जा सकता है कि सरकार राम मंदिर को लेकर अध्यादेश या विधेयक लाए।

बहरहाल पुनः एक बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जिस तरह बीते पांच वर्षों में उनके सरकार के द्वारा लायी गयी योजनाओं पर जो विकास की चर्चा की गई, उसमें अभी भी बहुत सी कमियां है, जो अब पुनः मिले पांच साल की सत्ता में इसमें सुधार लाना होगा। खासकर कुछ ऐसे मुद्दे जो सीधे तौरपर मोदी सरकार के जनाधार को और मजबूत करने में अहम है, जैसे-अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 और 35ए को हटाया जाना तथा किसानों के लिए लायी गई योजना पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य होगा। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार के शिशु अवस्था से युवा अवस्था के प्रवेश में ये कार्य कितने जल्द पूरे करते हैं, क्योंकि खुद को देश का चौकीदार बताने वाले नमो आज प्रचंड बहुमत से सदन में हैं तथा विपक्षियों द्वारा चौकीदार पर चोर होने का नारा जो दिया जा रहा था, उनके विरोध में नमो के सिपहसलार अपने नाम के पहले चौकीदार जोड़कर जो अपना समर्थन दिया था, वह आज सरकार के विभाग में मौजूद है। इसलिए यह चौकीदार की फतह है। अब देखना यह है कि चौकीदार देश की रक्षा-सुरक्षा और उन्नत्ति में कितनी चार चांद लगाती है, फिलवक्त मोदी सरकार पार्ट-2 की शुभकामनाएँ। ●

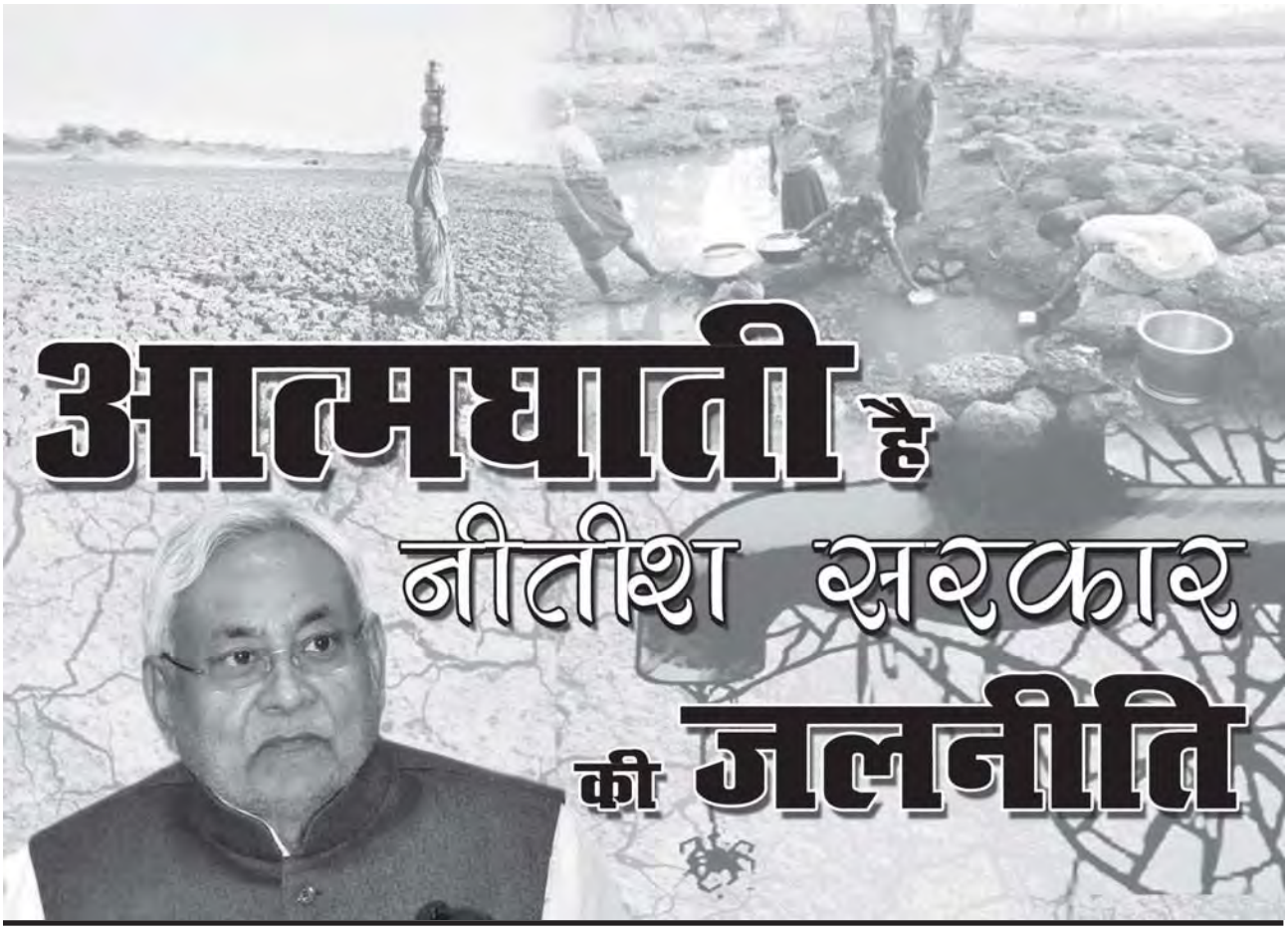

आत्मघाती है नीतीश सरकार की जलनीति

● ललन कुमार प्रसाद

नीतीश सरकार की जलनीति आत्मघाती है, क्योंकि एकांकी है। सरकार को केवल इस बात की फिक्र है कि जहाँ कही भी जल की कमी महसूस हो, वहां के भू-जल का दोहन करो और जितना अधिक कर सको, करो। कोई रोक-टोक किसी भी सरकारी स्तर पर नहीं है। सरकार को इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं है कि भू-जल स्तर पाताल में चला गया है। बिहार के 38 जिलों में से 22 जिलों के 110 से भी अधिक प्रखंडों में भू-जल स्तर क्रिटिकल जोन में पहुंच चुका है यानि भू-जल के खजाना में से 90 फिसदी से भी कुछ अधिक पानी निकाला जा चुका है। ऐसे में शीघ्र ही भू-जल का खजाना खाली हो जायेगा, तब कहां से पानी लायेंगे? बिहार की जनता पानी के बगैर बेमौत मर जायेगी। अगर सरकार भू-जल के खजाने को खाली करने पर तुली हुई है तो भू-जल का खजाना भरेगा कौन? सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सोच रही है। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, सरकार के मुख्य

सचिव सहित जल संसाधन, लघु जल संसाधन, राष्ट्रीय विकास, पर्यावरण, मत्स्य एवं पशुपालन, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज विभागों के प्रधान सचिव तथा नगर निगम के मेयर, ये सब क्या कर रहे हैं? इंजीनीयर मुख्यमंत्री, उनके वैज्ञानिक सलाहकार और इतने सारे उनके अनुभवी आईएएस हाकिम क्या कर रहे हैं? इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हर घर नल तो पहुंचा देंगे, लेकिन नलों में भरने के लिए जल कहां से लायेंगे? ऐसे में बगैर जल का नल किस काम का? नीतीश सरकार बताये कि अपने लगातार 13 वर्षों के शासनकाल में भू-जल का खजाना भरने के लिए एक फिसदी भी काम क्यों नहीं किया है? क्या सरकार और सरकार के काबिल आईएएस हाकिमों को इतना भी पता नहीं है कि भू-जल को रिचार्ज करने का एक मात्र साधन तालाब है और इसे लगातार 13 वर्षों में एक भी तालाब क्यों नहीं खुदवाया है। ऐसी सरकार किस आधार पर दावा कर रही है कि 31 मार्च 2020 तक हर घर में नल-जल पहुंचा देंगे। पूरे बिहार में भू-जल की स्थिति इतनी नाजुक है कि जो हर घर नल जल योजना, जो भी थोड़ी बहुत चल रही है, वह जल

के आभाव में बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है और निकट भविष्य में शीघ्र ही किसी भी क्षण बंद हो सकती है। सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री का हर घर नल जल योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही है। मसलन पिपरासी प्रखण्ड के किसी भी घर में नल से जल नहीं मिल रहा है। जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जरा अपने चमचो से सावधान रहिए नीतीश बाबू! वरना आगामी विधानसभा के चुनाव में सिर्फ जल की कमी को लेकर आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने पड़ोसी राज्य झारखण्ड से सबक लिजिए, जहां अब तक सैकड़ों तालाब खुदवाये जा चुके हैं, जिससे तालाबों के आसपास के लोग पानी की कमी को लेकर काफी राहत महसूस कर रहे हैं। रघुवर सरकार आगे भी सैकड़ों तालाबों के खुदवाने का काम जारी रखे हुए है।

जिस देश में सौ करोड़ लोग जल संकट वाले इलाकों में रह रहे हैं, 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं, 84 फिसदी ग्रामीण घरों में पानी के पाईप की पहुंच नहीं है, 70 फिसदी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, ऐसे में साफ पीने लायक पानी सभी को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है कि पानी अपने प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रहे। खासकर ग्रामीण भारत में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना तो सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में यह दर्ज है कि प्रत्येक देशवासी को साफ पानी मुहैया कराना राज्य का दायित्व है, लेकिन आज भी देश की कोई 17 लाख ग्रामीण बसावटों में से लगभग 78 फिसदी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। आज महज 4553 गांवों में नल जल और हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध है। आज हमारे देश की 18 फिसदी ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को पीने का पानी लाने के लिए हर दिन कई-कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये आंकड़े भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के हैं। नतीजा आज भी कोई 3 करोड़ 77 हजार लोग हर साल दूषित जल के इस्तेमाल से बीमार पड़ते हैं, जिससे हर साल करीब 7 करोड़ 30 लाख कार्य दिवस बर्बाद होते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 3900 करोड़ रूपये का नुकसान होता है। दूषित जल पीने से करीब 15 लाख बच्चों की हर साल मृत्यु हो रही है। आईआईटी (खड़गपुर) ने एक कराडाई विश्वविद्यालय के साथ 2005 से 2013 के बीच के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर बताया है कि असम, पंजाब, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भू-जल का तेजी से दोहन हो रहा है। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन में पानी का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। नीती आयोग द्वारा जून 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक बैंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 बड़े शहरों में भू-जल समाप्त हो जायेगा, जिससे करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि देश के कुछ भागों में एक मिटर प्रति वर्ष की दर से भू-जल स्तर गिर रहा है। ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन 'वाटर एड' की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनियां में भू-जल का स्तर तेजी से गिर रहा है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच वैश्विक भू-जल स्तर में 22 फिसदी की कमी आयी है। उसी अवधी में भारत के भू-जल स्तर में 23 फिसदी की कमी हुई है। ऐसा इसलिए की दुनियां के भू-जल का 25 फिसदी यानि एक चौथाई अकेले भारत इस्तेमाल करता है। अकेले हमारे देश में सलाना 35 बीसीएम (बिलियन क्यूबीक मिटर) यानि 35 अरब घन मिटर भू-जल का दोहन होता है। अर्थात् हमारा देश दुनियां में भू-जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दरअसल, पूरी दुनियां में पानी का सर्वाधिक इस्तेमाल खेती-किसानी में किया जाता है। लेकिन हमारे देश में उपलब्ध कुल पानी का 90 फिसदी खेती-किसानी में, 7 फिसदी उद्योगों में और 3 फिसदी घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए की भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में भू-जल का भंडार पिछले तीन वर्षों में 70 बीसीएम यानि 70 अरब घन मिटर से घटकर 38 बीसीएम यानि 38 अरब घर मिटर रह गया है। ऐसा इसलिए की देश में जितने भू-जल का दोहन होता है, उसका 42 फिसदी से भी कम पानी वापस धरती की कोख में लौटाया जाता है। अगर यही हाल रहा तो 2040 तक देश की आधी आबादी एक-एक बूंद पानी के लिए तरसेगी।

★ **बिहार सरकार की कुदृष्टि भू-जल पर पड़ चुकी है :-** बिहार सरकार की कुदृष्टि भू-जल यानि भूमिगत जल के भंडार पर पड़ चुकी है, जो कि बिहार की जनता के लिए जल की उपलब्धता को लेकर बहुत अशुभ संकेत है। जब सतही जलस्त्रोत नहीं रहेगा तो भूमिगत जलस्त्रोत कैसे बचेगा? सतही जलस्त्रोत ही भूमिगत जलस्त्रोत की जननी है। ऐसा इसलिए की सतही जलस्त्रोत से भूमिगत जलस्त्रोत अनवरत रिचार्ज रहता है। भूमिगत जलस्त्रोत को रिचार्ज करने का दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है और ना ही हो सकता है। लेकिन यदि सतही जलस्त्रोत समाप्त हो जायेगा तो भूमिगत जलस्त्रोत स्वत: ही समाप्त हो जायेगा। जब माँ ही नहीं बचेगी तो उसकी संतान का पालन-पोषण कौन करेगा? उसी तरह से जब सतही जलस्त्रोत जैसे-नदी, तालाब, झील, झड़ना, आदि ही नहीं बचेंगे तो भूमिगत जल भंडार का पोषण कैसे होगा? उसका अस्तित्व कैसे बचेगा? इसलिए यदि भूमिगत जलस्त्रोत को बचाना है तो सतही जलस्त्रोतों को समृद्ध करना ही होगा। तालाबों की संख्या में भारी इजाफा करनी ही होगी, क्योंकि सतही जलस्त्रोत को समृद्ध करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है और जिसे हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। भूमिगत जल स्तर को नीचे गिरने से बचाने के लिए तालाब ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वर्षा जल को सहेजने का सर्वोत्तम साधन तालाब ही है। यदि तालाबों की संख्या पर्याप्त बढ़ा ली जाये और उनका समुचित तरीके से रख-रखाव किया जाता रहे तो कोई शक्ति नहीं है जो भूमिगत जल स्तर को नीचे गिरा सके। इस ध्रूव सत्य को बिहार सरकार और केन्द्र सरकार अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि इस तथ्य को समझे बिना नीतीश सरकार की हर घर नल जल योजना, जो बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी योजना है, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है, यानि अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, वरना मुख्यमंत्री की हर घर नल जल योजना को बुरी तरह से फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता है।

★ **जल संग्रहण व जल संरक्षण का सर्वोत्तम साधन है तालाब :-** तालाब कल्प वृक्ष है। यह न तो कोई कल्पना है और ना ही कोई नारा या अतिश्योक्ति। यह तो प्रायोगिक रूप से प्रमाणित शुद्ध हकीकत है। आज तक पूरी दुनियां में ऐसा कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का इजात नहीं किया जा सका है, जो तालाब संस्कृति के आसपास भी पहुंच सके, बराबरी करना तो दूर की कोड़ी है। तालाब वर्षा जल का जितनी अधिक मात्रा में, जितनी उपयुक्त और सुरक्षित तरीके से जितनी सफलतापूर्वक सहेज लेता है उतना तो आज के सर्वाधिक विकसित किसी भी दूसरी तकनीक द्वारा संभव नहीं है। तालाब भू-जल यानि भूमिगत जल को रिचार्ज करने का एक अद्भुत और अतुलनीय साधन है। ऐसा इसलिए की तालाब भू-जल को बगैर एक सेकेंड के भी ब्रेक से सालों भर 24 घंटे हर मौसम में दिन रात रिचार्ज करता रहता है। अर्थात् तालाब भू-जल स्तर को नीचे गिरने से ब्रेक लगाने का सर्वाधिक असरदार व्यवहारिक साधन है।

यह ध्रूव सत्य है कि जहां जल है, वही जीवन है। तभी तो सभी सभ्यताएं नदी के किनारे ही पुष्पित पल्वित हुई है। पहले जगह-जगह पर ताल-तलैया, पोखर जैसे तमाम जल स्त्रोत थे और जमीन भी कच्ची तथा हरियाली से समृद्ध थी तो बारिस होती थी तो पानी स्वत: रिसकर भू-जल को रिचार्ज करता रहता था। अब तो हरियाली में भारी कमी हो गई है तथा ढ़ेर सारे जमीन का कंक्रीटीकरण हो चुका है। इतना ही नहीं ताल-तलैया, पोखर, आदि जैसे सतही जलस्त्रोत बहुत ही कम यानि ना के बराबर बचे हैं। फलस्वरूप धरती की कोख से इस्तेमाल हेतु हम जितना पानी ले रहे हैं, उसकी तुलना में बहुत ही कम पानी वापस लौटा रहे हैं। इसलिए जरूरी हो गया है कि ताल-तलैया और पोखर जैसे जलस्त्रोतों का समुचित रख-रखाव और भारी संख्या में नये तालाबों का बहुत तेजी से निर्माण किया जाये।

★ **जल संग्रहण व जल संरक्षण के इतर तालाबों के फायदे :-**

☞ तालाब भू-जल स्तर को नीचे गिरने से ब्रेक लगाते ही है, भरपूर मात्रा में सतही जल भी प्रदान करते हैं।

☞ किसानों के लिए लाईफ-लाईन है तालाब। धान, गेंहू, मक्का, तेलहन, दलहन, साग-सब्जी, फल-फूल, गन्ना, आदि के पौधों की सिंचाई के लिए हम जितना पानी चाहे तालाब से ले सकते हैं।

☞ सिंघाड़ा और मखाना की पैदावार केवल तालाबों से ही ली जा सकती है। तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना का उत्पादन करके किसान

मालोमाल हो सकते हैं।

☞ मछली पालन के लिए तालाब अतुलनीय है। तालाबों में मछली पालन कर मछुआरा समाज खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

☞ तालाबों की मिट्टी से कुम्हार मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मुर्तियां, टाइल्स, दिया, गमला, फूलदान आदि तैयार करके खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

☞ तालाब होने से पशु पालकों को मवेशियो को खिलाने-पिलाने, नहाने और उनके निवास स्थान को साफ-सुथरा रखने के लिए पानी की कोई कमी नहीं हो सकती है।

☞ क्षेत्र विशेष में पर्याप्त संख्या में तालाब होने से उस क्षेत्र विशेष की सड़के बरसात में डूबती नहीं है। क्योंकि बारिस का पानी बहकर तालाबों में शरण ले लेते हैं।

☞ तालाबों के चलते बरसात में खेतों की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों में जाने से बच जाती है। नतीजा नदियां गहरी बनी रहती है, उथली नहीं हो पाती है। फलस्वरूप बरसात में बाढ़ का प्रकोप काफी कम हो जाता है।

☞ यदि रोजगार की दृष्टि से देखा जाये तो लोगों को रोजगार मुहैया कराने में तालाबों की भूमिका बहुत ही अहम मानी जानी चाहिए।

★ प्रति व्यक्ति हर दिन पानी की वास्तविक खपत :- हर वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 80 लीटर पानी खर्च करता है-नहाने में 20 लीटर, कपड़ा धोने में 10 लीटर, शौच करने, ब्रश करने और सेविंग करने में 15 लीटर, खाना पकाने, बर्तन धोने और फल-सब्जी धोने में 20 लीटर, साफ-सफाई में 11 लीटर और पीने में 4 लीटर। कोई-कोई व्यक्ति नित्य दिन भर में दो बार शौच जाते हैं। ऐसे में प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसतन 80 लीटर से भी ज्यादा पानी खर्च करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बुढ़े तक कुल पांच आदमी के हर परिवार में हर दिन औसतन 260 लीटर पानी की खपत होती है। बड़ों की तुलना में बच्चों पर पानी की खपत कम होती है।

वैसे तो आम तौरपर एक वयस्क व्यक्ति प्रति दिन 2.5 से 4.0 लीटर पानी पीता है। लेकिन भोजन पैदा करने के लिए हर व्यक्ति को 2 हजार से 5 हजार लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अर्थात् पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के

अलावा अन्य कई कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसमें रूटीन काम की तुलना में कई गुणा अधिक पानी की खपत होती है। मसलन एक किलोग्राम चावल के उत्पादन में 2800 लीटर और एक किलोग्राम गेंहू के उत्पादन में 1600 लीटर पानी लग जाता है। एक किलोग्राम चीनी के उत्पादन में 2 हजार लीटर और एक लीटर दूध के लिए 200 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। एक कॉटन शर्ट तैयार करने में 2600 लीटर और एक जोड़ी जिन्स तैयार करने में 6800 लीटर पानी की खपत होती है। एक टन पेपर के उत्पादन में 40 टन पानी खर्च हो जाता है। एक टन सिमेंट के उत्पादन में 5200 लीटर और एक टन स्टील के उत्पादन में 2350 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। एक कार के उत्पादन में 148000 लीटर पानी लग जाता है।

★ एक नजर बिहार के तालाबों की स्थिति पर :- आजादी के समय बिहार में 1 लाख 98 हजार 452 तालाब थे-44 हजार 432 सरकारी और 1 लाख 54 हजार 20 प्राईवेट। उस समय बिहार का रकवा 1 लाख 75 हजार 877 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य का गठन हुआ, जो उसके पहले तक बिहार राज्य का हिस्सा था। झारखण्ड राज्य के गठन के बाद बिहार का रकवा 1 लाख 75 हजार 877 वर्ग किलोमीटर से घटकर 94 हजार 163 वर्ग किलोमीटर रह गया। झारखण्ड राज्य के गठन के बाद बिहार राज्य के हिस्से में 98 हजार 381 तालाब पड़े-31 हजार 634 सरकारी और 66 हजार 747 प्राइवेट। झारखण्ड राज्य के हिस्से में 1 लाख 71 तालाब पड़े-12 हजार 798 सरकारी और 87 हजार 273 प्राइवेट। उपरोक्त आंकड़े का स्त्रोत पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार सरकार है। अब बिहार राज्य में कितने तालाब बचे हैं, इसका आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध नहीं है और ना ही बिहार सरकार का पशु पालन एवं मत्स्य विभाग उपलब्ध करा रहा है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार आजादी के 72 वर्षों के बाद अब बिहार में मुश्किल से 16 हजार तालाब भी नहीं बच पाये हैं। अर्थात् लगभग 90 फिसदी तालाबों का अस्तित्व मिट गया है। मसलन पटना शहर को ही ले लिजिए। 1950-60 के दशक में पटना को तालाबों का शहर कहा जाता था, क्योंकि उस समय पटना शहर में 104 तालाब थे, जो अब घटकर एक दर्जन से भी कम रह गये हैं। पटना शहर में महज दस फिसदी ही तालाब बचे हैं। अर्थात् पटना शहर में 90 फिसदी तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री लगातार पिछले 13 वर्षों से पद पर बने हुए हैं। वे बिहार के विकास पुरूष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है। शहरों में भी फ्लाईओवरों का जाल बिछा दिया है। उनके चलते ढ़ेर सारे थानों को अपना भवन हो गया है। कई विश्वविद्यालयों को स्थापित कर उन विश्वविद्यालयों को अपना भवन उपलब्ध करा दिया है। पटना शहर में बिहार

म्यूजियम, बिहार शांति स्तूप जैसे दर्शनीय भवन बनवा दिये हैं। बापू सभागार और ज्ञान भवन जैसे शानदार सभागार बनावाये हैं। लेकिन बिहार की जनता को पानी मिले इसके लिए एक भी तालाब नहीं खुदवाया है और ना ही पुराने तालाबों के गाद को निकलवाया है। जिससे की बचे-खुचे तालाब अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। इतना ही नहीं अपने शासन काल में अच्छी-खासी संख्या में तालाबों को अधिग्रहित कर या नाजायज तरीके से कब्जा कर उनके जगह पर नई-नई कॉलोनियां, सरकारी कार्यालयों के भवन, पार्क आदि बनवाने से रोक सके हैं। ऐसे में पानी का संग्रहण और संरक्षण कैसे संभव हो सकेगा? जबकि तालाब ही पानी के संग्रहण और संरक्षण के सर्वोत्तम साधन है। पानी के संरक्षण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है वृक्षारोपण। इस मामले में भी नीतीश सरकार बुरी तरह असफल है। ऐसा इसलिए कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में उसके परिसर के दिवारों से सटे अंदर की तरफ से वृक्ष नहीं लगाये गये हैं। सरकारी अस्पतालों के परिसर के अंदर भी वृक्ष नहीं लगाये गये हैं। सरकारी कार्यालयों के परिसर के अंदर भी वृक्ष नहीं लगाये हैं। इन जगहों पर परिसर के अंदर भी पहले से जो थोड़े बहुत वृक्ष थे, उनमें से भी ढ़ेर सारे वृक्ष काट लिये गये हैं। सड़कों और नहरों के दोनो किनारों पर वृक्षारोपण नहीं कराये गये हैं। सड़कों का चौड़ीकरण के तहत यानि दो लेन से तीन लेन, तीन लेन से चार लेन, चार लेन से पांच लेन और पांच लेन से छः लेन बनवाने के दौरान करोड़ों वृक्षों की बली दे दी गई है। प्राईवेट तो दूर सरकारी भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि पानी के संग्रहण और संरक्षण को लेकर नीतीश सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जाये तो उन्हें दस में से दो नंबर ही मिलेंगे। इनके शासन काल में ढ़ेर सारे तालाबों का अस्तित्व मिट जाना तथा जो बचे हैं, उनके रख-रखाव यानि मेंटनेंस पर ध्यान नहीं दिया जाना, हर साल तालाबों से गाद नहीं निकाला जाना, आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर अगर नीतीश सरकार के जल संग्रहण और जल संरक्षण का मूल्यांकन किया जाये तो उन्हें 10 में से 2 के बजाये 1 ही अंक देना पड़ेगा। उनके नेतृत्व में बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, पीएचईडी और पर्यावरण विभाग आदि ने जो भी कुछ काम किया है, वह सिर्फ पानी की भयंकर कमी का रोना रोया जाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। नीतीश सरकार और उनके सरकारी मुलाजिम ही बताये कि पूरे

बिहार में एक भी तालाब क्यों नहीं बनवाये हैं, बचे-खुचे तालाबों के रख-रखाव का कार्य क्यों नहीं किया है और भारी संख्या में तालाबों का वजूद खत्म होने से क्यों नहीं बचाया है। आखिर नीतीश सरकार अरबों रूपये खर्च कर जल संग्रहण और जल संरक्षण के लिए क्या किया है? जनता के पैसों की ऐसी बर्बादी जनता के सेवकों द्वारा! आज स्थिति यह है कि बेलगाम अंधाधुंध भू-जल दोहन के चलते शहर तो शहर गांव के लोग भी बेहाल है। भू-जल दोहन के मामले में सरकार की ओर से कोई नियंत्रण नहीं है। नतीजा भू-जल का स्तर पाताल में चला गया है। बिहार के जमुई जिले के चकई प्रखंड में भू-जल का स्तर 1400 फीट से भी नीचे पहुंच गया है। जमुई की अधिकांश नदियों और ताल-तलैया में पानी घटता जा रहा है। भू-जल स्तर नीचे जाने से चापाकल बेकार हो गये हैं। जमुई के दक्षिणी इलाके में स्थित जंगल के एक दर्जन से भी अधिक जलस्त्रोत सूख गये हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कभी सूखते नहीं थे। इससे वहां पनाह लेने वाले नक्सलियों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। सुरक्षा बल सतर्क है और नक्सलियों को दबोचने के लिए पानी को हथियार बना सकते हैं। जमुई जिला के ढ़ेर सारे प्रखंडों में भू-जल स्तर में गिरावट के चलते लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सोना बाजार में डीप बोरिंग के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जमुई जिला के ज्यादातर प्रखंडों में हैंडपम्प और समरसेबल मोटर से काम चलाया जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर नदी, कुंआ और तालाब सूख गये हैं। नतीजा पशुओं को भी पानी की कमी सताने लगी है। ज्यादातर हैंडपम्प काम नहीं कर रहे हैं और जो कुछ हैंडपम्प काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसा इसलिए की हैंडपम्प एक दो बाल्टी पानी देने के बाद पानी देना बंद कर देते हैं। फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद थोड़ा पानी देते हैं। नतीजा जमुई जिले के ज्यादातर प्रखंडों के लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकते हैं। लोक स्वास्थ्य संस्थान, जमुई के कार्यपालक अभियंता बिन्दु भूषण अपने विभाग को प्रेषित रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि चकई प्रखण्ड में चापाकल लगाने हेतु 1500 फीट की गहराई तक बोरिंग की जानी चाहिए।

पूरे बिहार में हर जगह पानी को लेकर त्राहीमाम मचा हुआ है। शुद्ध पेयजल को लेकर मारामारी मची हुई है। 25 अप्रैल 2019 को मनेर के अदलचक डुमरिया में अदलचक निवासी विनय राय और देवराज राय के बीच नल जल योजना के तहत लगी नल के नीचे पानी गिराने को लेकर देवराज की पत्नी और बेटी में मारपीट हो गया। जिसमें माँ बेटी दोनो का सिर फट गया। दोनों को इलाज हेतु उनके परिजनों ने मनेर अस्पताल पहुंचाया, जहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ऐसे में उचित इलाज के आभाव में दोनों की जान भी जा सकती थी।

मधुबनी जिला के लोग पानी की भारी किल्लत से जुझ रहे हैं। लोग पीने के पानी का इंतजाम तो किसी तरह से कर ले रहे हैं, लेकिन मवेशियों को नहाने के लिए और पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मधुबनी जिला के राजनगर के रामपट्टीगंज टोला के किसान कल्लर यादव और इन्द्र कुमार यादव तथा महिनाथपुर के किसान चंदर यादव बैल और दुधारू भैंस सिर्फ इसलिए औने-पौने दाम में बेच दिया, क्योंकि प्रति मवेशी दिन भर में कम से कम दस बाल्टी पानी चारा खिलाने से लेकर पानी पिलाने तक में खर्च

हो जाता है, जिसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इंद्र कुमार यादव 20-25 हजार रूपये मूल्य का बैल महज 11 हजार रूपये में बेच दिया। कल्लर यादव ने 13 हजार रूपये मूल्य का बैल साढ़े सात हजार रूपये में बेच दिया।

पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के किसानों को पहले सिंचाई की कोई फिर्क नहीं रहती थी। लेकिन आज नौबतपुर में सड़कों के किनारे खुदे आहर में सोन नदी से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसके चलते ये आहर सूख गये हैं। नतीजा अब किसानों को सिचाई की कौन कहे, पीने के लिए भी पर्याप्त पानी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। पहले सोन नदी लिंक मझौली नहर से खेतों की सिंचाई होती थी, खूब धान पैदा होता था, पर आज नहर नाला बन गया है।

नवादा जिला के लूटविगहा और पिपराचक गांव की लगभग पूरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वालों की है। गांव के उपेन्द्र राजवंशी, देवानंद चौधरी और भूषण पासवान के परिजनों ने बताया है कि ज्यादातर जलस्त्रोत सूख जाने के कारण नदी के किनारे बना कुंआ ही सहारा बना हुआ है। पानी की भारी कमी के चलते लोग गांव से पलायन करने लगे हैं। गांव के कुछ लोग पानी की वजह से दूसरे जगहों पर चले गये हैं।

दरभंगा जैसी जगहों पर भू-जल स्तर काफी नीचे चला जाना चिंता का विषय है। बात यह है कि पहले दरभंगा शहर और शहर से सटे इलाकों में तालाबों की भरमार थी। इसलिए दरभंगा शहर 'पग-पग पोखर, माछ मखान' के नाम से विख्यात था। वहां भी अधिकतर तालाबों को पाटकर बहुमंजिली इमारते खड़ी कर दी गई है। अर्थात् वर्षा जल संचयन का साधन खत्म किये जाने से वहां का भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जिसके चलते सामान्य चापाकलों से पानी नहीं निकल रहा है। लोग समरसेबल बोरिंग कराकर लगातार भू-जल का दोहन कर रहे हैं। नतीजा बिहार के आधे से अधिक जिलों में जल संकट की स्थिति भयावह हो गयी है। अर्थात् नालंदा,

नवादा, शेखपुरा, गया, आरा, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, जमुई, लखीसराय, अरवल, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, सिवान, सितामढ़ी, वैशाली और मधेपुरा जिले के 112 से भी अधिक प्रखंड क्रिटिकल जोन में है। विशेषज्ञों का कहना है किसी भी जगह के भू-जल भंडार का 70 फिसदी तक पानी निकाला जाना सुरक्षित माना गया है, क्योंकि ऐसे भू-जल भंडार को पुनः पहले जैसी स्थिति में लाया जा सकता है। किसी भी जगह के भू-जल भंडार का 70 से लेकर 90 प्रतिशत पानी का निकाला जाना सेमी क्रिटिकल जोन माना जाता है। क्योंकि ऐसे भू-भंडार को पुनः पहले जैसी स्थिति में लाना अधिक कठिन हो जाता है।

राज्य भर में लगभग दो लाख चापाकल मरम्मत के आभाव में बंद पड़े हैं और भू-जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण लगभग डेढ़ लाख चापाकल काम नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो भू-जल पर कब्जा करने के लिए होड़ मची है। सरकारी निष्क्रियता का फायदा उठाकर जो संपन्न लोग हैं, वे पानी के लिए अधिक गहराई वाले समरसेबुल ट्यूबवेल लगा लिये हैं। पूरे बिहार में मनमाने ढ़ंग से भू-जल का दोहन हो रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बिहार में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नल-कूपों से 24 घंटे पानी का दोहन जारी है। लगातार दोहन से भूमिगत जलाशय खाली होते जा रहे हैं। स्थिति यही रही तो किसानों को धान की फसल के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा। एक ओर जहां सतही जलाशय जैसे नदी, तालाब, नहर, आहर, पईन, आदि सूख चूके हैं, वहीं भूमिगत जलाशय तेजी से खाली होते जा रहे हैं। भारी संख्या में तालाबों का खात्मा होने के कारण भू-जल के रिचार्जिंग के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना, जो लोगों की प्यास बुझाने के लिए चलायी जा रही है, विफल होती दिख रही है। लोगों के घरों तक नल तो पहुंच गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हर घर नल जल योजना के तहत गांवों में पेयजल लेने वालों को प्रतिमाह 30 रूपये शुल्क देना होगा। पानी की राशनिंग होगी और सरकार प्रति दिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी मुहैया करायेगी। पटना जिला के दनियावां प्रखण्ड के जिन वार्डों में हर घर नल जल को कार्यान्वित कर पानी मुहैया कराया जा रहा है, वहां के लोग फिलहाल इस भीषण गर्मी में भी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन आगे कर सकेंगे यह संदिग्ध है, क्योंकि भू-जल स्तर वहां भी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है।

बिहार सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत राज्य के 58 हजार वार्डों में से 21 हजार वार्डों में पाईप के जरीय पीने का शुद्ध पानी घरों तक पहुंचा दिया

राज्य में पिछले पांच वर्षों में बारिस की स्थिति

वर्ष	बारिस की मात्रा	सामान्य से कम
2014	849.3 मि०मी०	17 प्रतिशत
2015	744.7 मि०मी०	27 प्रतिशत
2016	971.6 मि०मी०	05 प्रतिशत
2017	936.8 मि०मी०	09 प्रतिशत
2018	771.3 मि०मी०	25 प्रतिशत
2019	---------	25 प्रतिशत (अनुमानित)

प्रत्येक साल 1 जून से 30 सितम्बर तक औसत बारिस

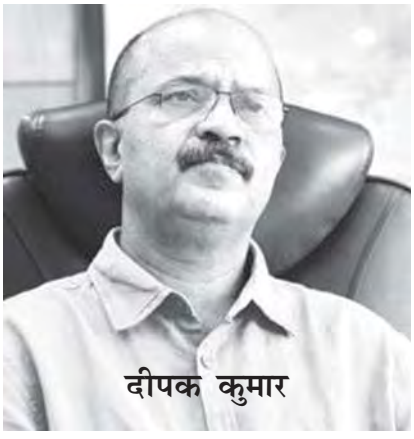
दीपक कुमार

के.के. पाठक

प्रत्यय अमृत

गया है और 20 हजार वार्डों में काम जारी है, जो कि आंशिक रूप से सही है। बिहार सरकार दावा करती है कि मार्च 2020 तक शहरी इलाकों में पाईप से पीने का शुद्ध पानी सभी घरों तक पहुंचा दिया जायेगा, यह भी संभव नहीं दिखता है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा दावा करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में 31 दिसम्बर 2019 तक हर घर नल का शुद्ध जल पहुंचा दिया जायेगा, यह भी संभव नहीं दिखता है। संभव है कि सरकार शहरों तथा गांवों में हर घर नल का जल पहुंचाने हेतु पाईप बिछाने का कार्य पूरा कर ले, लेकिन नलों में भरने के लिए जल कहा से लायेगा? ऐसा इसलिए सतही पानी कही नहीं दिख रहा है। भारी संख्या में तालाब, पोखर, आहर, नहर और कुंए सूख गये हैं तथा समान्य चापाकलों से पानी नहीं निकल रहा है। भू-जल का स्तर गिरकर पाताल में पहुंच चुका है तथा भारी संख्या में तालाब खुदवाने का काम तो दूर, इस कार्य को शुरू करने के लिए सर्वेक्षण का काम भी शुरू नहीं किया गया है कि तालाबों को खुदवाने का काम किन-किन जगहों

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

पर कराया जायेगा। ऐसे में तालाब खुदवाने का कार्य कब शुरू किया जायेगा, इसका कोई अता-पता नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री हर-घर नल जल योजना को झटका नहीं लगेगा तो और क्या होगा? फिलहाल जहां-जहां भी नल जल योजना चल रही है, वह भी बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। जो भी थोड़ा बहुत हर घर नल जल योजना की शुरूआत की गई है, वह भू-जल के आभाव में कभी भी किसी क्षण दम तोड़ सकती है। भू-जल की स्थिति अभी ही आपातकालीन अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने युद्ध स्तर पर भारी संख्या में बहुत ही तेजी से तालाब खुदवाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। फिलहाल जो हर घर नल जल की योजना चल रही है, वह चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के सिवाय कुछ नहीं है।

☆ **तेजी से खाली हो रहा है पटना शहर के भू-जल का खजाना :-** बिहार के तमाम क्षेत्रों की तरह पटना शहर में भी जल संकट गहराने लगा है। वीरचंद पटेल, अनिशाबाद, खगौल, फुलवारी और कंकड़बाग के इलाके में भू-जल

अरूण कुमार सिंह

अरविन्द कुमार चौधरी

जितेन्द्र श्रीवास्तव

कुछ यूं घट रहा है पटना शहर का भू-जल स्तर

इलाका	मई 2018	मई 2019	गिरावट
वीरचंद पटेल, सक्रिट हाउस जोन	14.67 मीटर	17.57 मीटर	3.16 मीटर
अनिशाबाद	12.59 मीटर	13.44 मीटर	0.85 मीटर
वेटनरी कॉलेज	12.90 मीटर	14.50 मीटर	1.60 मीटर
बी.एन. कॉलेज	10.60 मीटर	11.00 मीटर	0.40 मीटर
कंकड़बाग	13.78 मीटर	14.40 मीटर	0.62 मीटर
खगौल	11.08 मीटर	12.15 मीटर	1.07 मीटर
फुलवारी	12.40 मीटर	14.30 मीटर	1.90 मीटर

स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। पिछले 15 दिनों में पटना शहर के ग्रामीण इलाकों में भू-जल का स्तर एक फूट से तीन फीट नीचे तक गिरा है-प्रति वर्ष 1.5 फीट से लेकर 10 फीट तक की रफ्तार से। गुलजार बाग और ए.एन. कॉलेज इलाके में भी भू-जल स्तर में गिरावट आयी है। दुल्हिन बाजार सहित आसपास के इलाके के लोगों के बीच पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दुल्हिन बाजार के आसपास के इलाको में कही भी पोखर, तालाब और आहर में सतही जल दिखायी नहीं पड़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा पशु-पक्षी को भुगतना पड़ रहा है। भू-जल स्तर काफी नीचे जाने के कारण भरतपुरा, काब, दुल्हिन बाजार, कोरैया, सीही, निसरपुरा और घाना सहित एक दर्जन ग्रामीण इलाकों में हैंडपम्प ने पानी देना बंद कर दिया है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और बुडको का आंकलन है कि अप्रैल माह में भू-जल तेजी से 10 फीट नीचे खिसका है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भू-जल में इस गिरावट की प्रकृति का स्थायी होना है। पहले भी गर्मियों में भू-जल स्तर में गिरावट दर्ज होती थी, लेकिन बरसात में भू-जल स्तर बहुत हद तक मेंटेन हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अरवरत बेतहाशा बढ़ती आबादी के चलते भू-जल के दोहन में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। लगातार भू-जल की खपत में वृद्धि होने के चलते बरसात बाद निकासी की गई भू-जल की मात्रा का बामुश्किल 50 फिसदी ही पानी वापस धरती की कोख में लौटाया जा रहा है, यानि बामुश्किल 50 फिसदी ही मेंटेन हो पा रहा है। नतीजा मुख्य पटना शहर से लेकर शहर के ग्रामीण इलाको तक पानी के लिए मारा-मारी मची हुई है। नतीजा लोग सुबह-सुबह सब काम छोड़ पानी के जुगार में लग जा रहे हैं। इससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लोग समरसेबुल बोरिंग पम्प वाले पड़ोसी के घरों से पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। कई लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं।

★ **बिहार में बारिस की स्थिति:**- पिछले पांच साल से राज्य में सामान्य से कम बारिस होती आ रही है। मौसमी दशाओं के अध्ययन से पता चला है कि इस साल भी 1 जून से 30 सितम्बर तक 25 फिसदी बारिस कम हो सकती है। जेठ महीने (19 मई से17 जून तक) में पुरवईया हवा का चलना इस बात का प्रमाण है कि इस बात भी समान्य से कम वर्षा होगी, बिहारवासियों के लिए घातक साबित हो सकती है।

★ **इस साल बहुत हद तक दूर की जा सकती है जल संकट की समस्या :**- 100 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा एक तालाब को खुदवाने में अधिकतम 3 लाख रूपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि एक हजार ऐसे तालाब खुदवाये जाये तो कुल 300 करोड़ रूपये खर्च करने पड़ेंगे। राज्य के 29 जिलों के 112 प्रखंडों में जल को रिचार्ज करने हेतु तालाब खुदवाने के लिए अनुमति हेतु 29 अप्रैल 2019 को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक होने वाली थी, जिसमें आपदा प्रबंधन एवं ऊर्जा के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, जल संसाधन के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह, लघु जल संसाधन के प्रधान सचिव के.के. पाठक, ग्रामीण विकास के सचिव अरविन्द कुमार चौधरी और पीएचईडी के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव शामील होने वाले थें। बैठक हुई या नहीं, मुझे पता नहीं। यदि बैठक हुई तो तालाबों को खुदवाने का काम कब प्रारंभ होगा, मुझे पता नहीं। यदि कुछ तालाबों का खुदवाने का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाये तो 15 जून से बरसात का मौसम शुरू होने पर उन तालाबों में बारिस का पानी सहेजकर रखा जा सकेगा। ऐसे में बिहार सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि इस बार बारिस के पानी का कम से कम 50 फिसदी पानी को सहेजकर तालाबों में रख लिया जाये, जिससे की भू-जल रिचार्ज होता रहे और सरकार हर घर नल जल को सफल बनाने में पर्याप्त सफलता अर्जित कर सके। जब हमारे पुरूषार्थी इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछवा सकते हैं, सड़कों को फ्लाईओवर से पाट सकते हैं, विश्वविद्यालयों के भवनों का निर्माण करवा सकते हैं, बिहार म्यूजियम, बौद्ध शांति स्तूप, बापू सभागार, ज्ञान भवन, आदि जैसी शानदार भौतिक संरचनाएं खड़ी कर सकते हैं तो सूबे के लोगों की प्यास बुझाने तथा किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए हजारों की संख्या में तालाबों का निर्माण क्यों नहीं करा सकते? अवश्य करा सकते हैं। बिहार के लोगों के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें पुराने तालाबों का जिर्नोद्धार भी युद्ध स्तर पर कराना होगा। तालाबों से गाद को निकलवाना होगा। जिससे कि तालाब पूरी क्षमता से भू-जल को रिचार्ज करते रहे। बांधों से आज तक एक बार भी गाद नहीं निकाली गयी है, इसलिए बिहार में जितने भी बांध हैं उनकी गाद को निकलवाना होगा कि ये बांध अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके।

नीतीश सरकार हर घर नल जल को लेकर गंभीर प्रयास जरूर कर रही है। लेकिन बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार की यह जनकल्याणकारी योजना तभी अंजाम तक पहुंचेगी, जब युद्ध स्तर पर पूरे राज्य में भारी संख्या में तालाबों को खुदवाने का कार्य बगैर किसी विलंब के अविलंब शुरू करा देंगे, वरना उनकी इस महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना को फ्लॉप होने से बचा पाना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए की भू-जल के खजाना को समृद्ध नहीं करायेंगे तो नलों में भरने के लिए जल कहां से लायेंगे। मोदी सरकार भी जल संकट की समस्या को अच्छी तरह समझ रही है, तभी तो नरेन्द्र मोदी ने एक नया जल शक्ति मंत्रालय का सृजन किया है, जो देश की जल संकट की समस्या को लेकर निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। अब जल संकट की समस्या को इससे जुड़े मंत्रालयों को अपने जिम्मेदारी को एक-दूसरे मंत्रालयों पर थोपकर बच निकलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर नरेन्द्र मोदी कामचोर और गैर जिम्मेदार मंत्रियों को पदच्यूत करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण हैं-राजीव प्रताप रूढ़ी और उमा भारती। लेकिन जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए मोदी सरकार को भी युद्ध स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में भारी संख्या में तालाबों को खुदवाने का कार्य बगैर किसी विलंब के अविलंब शुरू करा देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

लापरवाह पुलिस एवं भ्रष्ट अधिकारियों के कारण नीतीश की छवि पर लग रहे दाग

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

आरंभ से ही नीतीश कुमार की छवि एक स्वस्थ राजनेता की रही है और बिहार के विकास के प्रति वे सदैव जागरूक रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ बिहार के विकास में कृतिमान स्थापित करना चाहते हैं। जिसका कारण है जीरो ट्रोंलरेंस के रास्ते पर चल रहे हैं। किन्तु दूसरी ओर नीतीश के विश्वासपात्र अधिकारी भ्रष्टाचार में कृतिमान स्थापित कर रहे हैं। 90/95 प्रतिशत से ज्यादा अधिकारी भ्रष्टाचार में गोता लगाते रहते हैं दूसरी ओर पुलिस के चाल और चरित्र अंग्रेज पुलिस से भी ज्यादा खौफनाक है, बिहार पुलिस से अपराधी नहीं सिर्फ इंसान भयभीत रहते हैं। पुलिस अपने वर्दी को सरेआम नीलाम कर रही है, पैसे और प्रमोशन के लिए कब और किसे हवालात में डाल दे यह कहना मुश्किल है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भ्रष्ट पुलिसकर्मी को जेल भेजने की आवश्यकता है। आज सबसे खतरनाक काम है, भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाना। भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाने के कारण त्रिगुणानन्द मुखिया दर्जनों बार जेल गए, भ्रष्टाचारियों ने पेशाब पिलाया, आज मृत्युशय्या पर मौत के इंतजार में आंसू बहा रहे हैं। आर आर एस के सबसे पुराने कार्यकर्ता 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र के हैं, अपनी गरीब बेटी के यहां फतुहा में ही लम्बे समय से रह रहे हैं। बावजूद भाजपा के लोग उनकी स्थिति भी जानने का प्रयास नहीं करना चाहते, ईमानदार और सामाजिक कार्यकर्त्ता देव कुमार सिंह, भ्रष्टाचार का विरोध करने के कारण 50 बार से भी ज्यादा जेल की यात्रा कर चुके हैं, माले के शैलेन्द्र भ्रष्टाचार के विरोध के कारण दर्जनों मुकदमों से जुझ रहे हैं। डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह भ्रष्टाचार के विरोध के कारण ही फतुहा पुलिस की आँखों का काँटा बन चुके हैं और आज भी मुकदमा से जुझ रहे हैं। पुलिस के चरित्र के कुछ उदाहरण ही काफी है। फतुहा में केनरा बैंक के छत पर एक पागल की भुल बस हत्या हो गयी थी, इस घटना को प्रमोशन पाने के लिए एक कहानी गढ़ा गया कि पुलिस मुठभेड़ में बैंक लुटेरा मारा गया फतुहा थाने में लक्ष्मीनिया पिस्तौल की कहानी आज भी सभी के जुवानों पर है। शिवदा शर्मा गोविन्दपुर फतुहा के दामाद को मोटर साईकिल की डिक्की में पिस्तौल दिखाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्कालीन फतुहा के विधायक स्वर्गीय सरयुग पासवान के वोलोरों गाड़ी से खून से लथ-पथ जैकट, पैंट जूता बरामद हुआ था, हत्या की घटना से साफ झलक रहा था, बार-बार इस घटना का प्रकाशित करने के कारण विधायक द्वारा जहर देने का मुकदमा पत्रकार लक्ष्मी नारायण पर ठोक दिया गया था, उस समय कुन्दन कृष्ण एस एस पी थे और जेल भेजने का तैयारी कर लिए थे। डा0 लक्ष्मी नारायण ने कुन्दन कृष्णन को स्वागत में साड़ी, साया, सिंदुर, टिकुली, ब्लाउज, ऐनक, कंघी बिहार सरकार मुख्यालय को भेजा था। सामान पहुंचते ही बिहार सरकार मुख्यालय में बवाल मच गया। अन्ततः मुकदमा समाप्त करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह के छोटे भाई की शादी में आए थे और उन्होंने स्वयं चर्चा निकाला कि डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह के विरूद्ध फतुहा विधायक द्वारा जहर देने का मुकदमा ठोक दिया, मैंने सच्चाई जानने के लिए फतुहा के बाल्मिकी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि सरयुग पासवान विधायक है और लक्ष्मी सिंह पत्रकार हैं वे बराबर विधायक के बारे में छापते रहते हैं इसी कारण जहर देने का मुकदमा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह दवा खिलाते नहीं है बल्कि हाथ पर देते हैं। जहर देने का सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार ने डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह से पूछा कि अब आपकी पुलिस तंग नहीं कर रही है ना, डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा कि आज तक एक चौकीदार भी नहीं आया है।

इधर फतुहा पुलिस ने अपना खौफनाक चेहरा डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह के सामने उजागर कर दिया। बताया जाता है कि डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह एवं उनके पुत्र के विरूद्ध मुकदमा ठोक दिया है तथा पुत्र को जेल भी भेज दिया है। बताया जाता है कि डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह के डिस्पेंसरी के सामने अज्ञात गाड़ी लगा हुआ था, ज्यादा जगह के कारण बराबर गाड़ी लगा रहता है। पुलिस ने आरोप लगाया कि गाड़ी के चालक है जबकि वह गाड़ी चलाना नहीं जानता है, जबकि दुसरी ओर डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह गाड़ी के इस्तेमाल करते हैं जबकि गाड़ी के उपर सीसी टीवी कैमरा देखने का प्रयास नहीं किया गया। कैमरा न देखना यह गम्भीर चिन्तन का विषय है, इस संदर्भ में पटना यूथ होस्टल में पुलिस उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर निम्न लोगों ने पुलिस के खौफनाक रवैया तथा निर्दोष को जेल भेजने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त किया। आक्रोश व्यक्त के सवालों में यूथ एजेंडा के सम्पादक प्रेम कुमार, देव कुमार सिंह, रामजतन सिंह यादव, अरूण पटेल, सुनीता, शोभा देवी, सेमीकान्ति, डा0 लक्ष्मी नारायण सिंह, पण्डित संजय कुमार झा, नागेन्द्र सिंह, प्रो0 विमल कुमार आदि मौजूद थे। उनलोगों ने कहा कि अपराध रोकने के लिए जल्दी-जल्दी बैठक जल्द से चार्जशीट पुलिस का तबादला और सस्पैण्ड से अपराध नहीं रूकेगा। अपराध रोकने के लिए

पुलिस द्वारा गलती करने पर बर्खास्त या जेल भेजना होगा। 3-4 काउण्टर करने वाले को ही थाना अध्यक्ष बनाना होगा, घूस मांगने पर सीधे जेल भेजना होगा, निर्दोष को जेल भेजने तथा दोषी को छोड़ने वाले पुलिसकर्मी को जेल भेजना होगा। नीतीश कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि अपराध के मामले को जीरो स्तर तक लाने हेतु ईमानदार पुलिस कर्मियों को विशेष छूट के साथ काम करने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। विजिलेंश को अत्यधिक सक्रिय करना होगा ताकि भ्रष्ट आचरण के बल पर करोड़ों की संपत्ति जमा करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। अपराध की घटनाएं बेतहासा बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार चाहें तो इसे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर तुरंत समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि वे वहीं नीतीश कुमार हैं जिनके कारण बिहार की जनता मध्य रात्रि में भी बेखौफ होकर घूमती थी। कहीं कोई डर-भय नहीं रहता था। अपराधी बिहार छोड़ कर कहीं और चले गये थे। वही नीतीश कुमार है जिन्होंने सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध संपत्ति को जब्त करके बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम किया था। एक बार पुन: नीतीश कुमार का पूर्व की तरह भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ●

गलत पुलिसकर्मियों को तबादले की जगह जेल भेजना व निलंबन ही होगा कड़ा दंड

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

पुलिस जब नियम एवं कानून को ताक पर रखकर काम करती है तब यदि जनता द्वारा सख्त विरोध किया जाता है तो संबंधित पुलिसकर्मी को तत्क्षण, निलंबन या लाईन हाजिर कर दिया जाता है। क्या ऐसे करने से पुलिस की मनोवृति बदल जाती है या घूस लेना, निर्दोष को गाली देना बंद कर देती है। या फिर बड़े अपराधियों की धड़-पकड़ आरंभ कर देती है? क्या उनके चरित्र में इस तरह की सजा से कोई बदलाव आ जाता है? मुझे तो लगता है कि यह तरकीब सिर्फ जनता की आँखों में धूल झोंकने भर के लिए होता है।

दरअसल पुलिस में खामिया भर्ती के समय से ही शुरू हो जाती है। जिस व्यक्ति का खानदानी इतिहास अन्याय का विरोध करने का रहा ही नहीं है, जिसका खानदानी इतिहास रहा है घूंसखोरी, कमीशनखोरी, अपराधियों के भय से कांपने का है, वह भी स्कूल से डिग्री लेकर पुलिस में भर्ती हो जाता है तथा पुलिस की वर्दी पहनकर मैदान में खड़ा हो जाता है। क्योंकि चूहा, नेवला का मुखौटा पहनकर सांप को पकड़ सकता है। दुनियां में कोई भी व्यक्ति के व्यक्ति चूहे को सांप पकड़ने की कला सिखा दे परन्तु चूहा सांप को देखते ही भाग खड़ा होगा। बाघ को पकड़ने के लिए देश की सभी बकरियों को संवैधानिक अधिकार मिल जाये तब भी बाघ के सामने बकरी खड़ी नहीं हो सकती है? इसी तरह गाय का मुखौटा बैल को पहना दिया जायेगा तो क्या बैल दूध दे सकता है? क्योंकि बैल अक्षम है। बैल को कितना भी ट्रेनिंग दे दें परन्तु घोड़े की तरह सवारी नहीं का सकता है। स्थानांतरण कौन सी सजा है यह आम जनता की समझ से बाहर है। जनता सिर्फ यह जानती है कि किसी भी मशीन का कोई भी पूर्जा खराब हो गया है या काम करने लायक नही है तो वह पार्ट-पूर्जा दूसरे मशीन में भी काम नहीं करेगा तथा खराब पूर्जा दूसरे एवं अच्छे मशीन को भी खराब कर देगा। कम पढ़े-लिखे मिस्त्री भी खराब समान को कबाड़खाने में डाल देता है वह दूसरी मशीन में उसे नहीं लगाता है।

अपराधी चाहे कितना भी ऊंचे पद पर हो या कितना भी धनी क्यों न हो, स्वाभिमानी पुलिस अपराधियों पर वैसे ही आक्रमण करती है जैसे नेवला सांप पर कर देती है। जिस पुलिस का खानदानी इतिहास अन्याय का विरोध करने का रहा ही नहीं है, वैसे पुलिस को खूंखार अपराधी, राजनीतिक अपराधी से सामना हो जाता है तो पुलिस की स्थिति वैसी हो जाती है जैसे बिल्ली के सामने चूहे की होती है।

पुलिस ही एक ऐसा विभाग है जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को कानूनी रूप से सुधार सकता है एवं कार्रवाई भी कर सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्र, जन वितरण प्रणाली में लूट-खसोट, विकास योजनाओं में गबन, अस्पताल, डॉक्टर एवं स्कूल में शिक्षक की अनुपस्थिति आदि में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर सकती है। परन्तु अपवाद में ही मिलेगा। एक उदाहरण पटना जिला के फतुहा प्रखंड अंतर्गत सुडिहा ग्राम के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को निरंतर अनुपस्थित रहने के आरोप में शिक्षक सकलदेव पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोई साधारण व्यक्ति पुलिस के दरवाजे पर जाकर ऐसी शिकायत करे कि शिक्षके अनुपस्थित रहते हुए फर्जी हाजरी तैयार करता है, तो पता चल जायेगा कि पुलिस क्या जवाब देती है। यदि उसी पुलिस को यही शिकायत एस.डी.ओ., डी.एम., मंत्री या न्यायालय के पहुंच-पैरवी वाला व्यक्ति शिकायत करे तो पुलिस शिक्षक को पकड़कर तुरंत जेल भेज देगी। पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करती है परन्तु अपराध में इस्तेमाल होनेवाला हथियार बरामद करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करती है। पुलिस चाहे तो अपराध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के उत्पादनकर्ता तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर सकती है। कानून के अनुसार अपराधी को गिरफ्तारी के साथ हथियार बरामद हो जाता है तो अपराधी से यह भी जानकारी लिया जा सकता है कि अपराधी हथियार खरीदा कहां से। जिस व्यक्ति से खरीदा है उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सख्ती पूर्वक पूछ-ताछ किया जा सकता है कि हथियार तुमने कहां से खरीदा है। इसी प्रकार पूछ-ताछ कर हथियार के कारखाना तक पहुंचकर गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा कर अपराध में कमी लायी जा सकती है। परन्तु वैसा करने के लिए राजनितिज्ञों के आगे आने की जरूरत है। राजनीति में आरक्षण के बल पर आनेवाले तथा ढ़ोंगी नेताओं से यह काम संभव नहीं है बल्कि जन समस्याओं की रगड़ से पैदा होनेवाले राजनीति से ही बदलाव हो सकता है। दर्जी के यहां तैयार नेता सीरिज बल्ब की तरह शोभा बढ़ाने के काम आते हैं। देश में बदलाव नहीं कर सकते हैं। विकास योजनाओं में लूट-खसोट हो रही है। सभी नेता खामोश हैं। है। ऐसा जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी द्वारा देने के बाद शिकायत कहां करेंगे ओर कौन सुनेगा यह एक गंभीर प्रश्न है। ●

जनसंख्या वृद्धि, सत्ता की सीढ़ी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पतन कई स्तरों पर हुआ है। धर्म की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से भावनाओं की दृष्टि से तथा चारित्रिक दृष्टि से भी पतन हुआ है। आज कोई भी राममनोहर लोहिया, कामराज, पटेल, जयप्रकाश नारायण की तरह वैचारिक ऊर्जा से परिपूर्ण नेता नजर नहीं आ रहा है। जनता ने भी नेताओं का चयन करने से पूर्व नेता का चरित्र, प्राकृतिक गुण, लक्षण, व्यवहार आदि की जांच-पड़ताल नहीं करती है। जनसंख्या वृद्धि सत्ता की सिढ़ी बन चुकी है। यह सोच नया नहीं है वैट्रिक ह्यूम की किताब छः डिस्नरी ऑफ इस्लाम, पृष्ठ नंबर 134 में पैगम्बर हजरत मोहम्मद का सुझाव है कि, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग दूसरे से कहीं अधिक संख्या में हो। कारण यह है कि जनसंख्या बढ़ने से नये मुल्क बनाने की मांग को बल मिलता है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने 84 वर्ष पूर्व नवम्बर 1926 में तेलगू समाचार में लिखा कि, मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह हिन्दुओं के एक बड़े समूह को पीट नहीं सकता बल्कि बुरी तरह से पीट सकता है जनगणना आयुक्त डोनॉल ने 1891 ई0 में ही कहा कि 620 वर्ष में हिन्दु समाप्त हो जायेंगे। 1991 की जनगणना के बाद डॉ0 रफिक जकारिया ने लिखा है कि मुसलमान 365 वर्ष के बाद भारत में बहुमत में होंगे। डॉ0 अम्बेडकर भारत के भविष्य को देखते हुए ही शायद मुस्लिम आबादी की समस्या को सुलझाने के लिए ही पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया तथा जनसंख्या अदला-बदली का सुझाव भी दिया था। ऐसा हुआ नहीं। यही नहीं मुस्लिम सामान्य नागरिक संहिता भी नहीं मानते।

परिवार नियोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम सिर्फ हिन्दुओं के लिए ही है। राजनीतिज्ञों की नजर में मुस्लिम गोलबंद वोट बैंक हैं। लिहाजा राजनीतिज्ञ इनकी प्रत्येक अखरपन को सैकुलरिजम और हिन्दुओं के राष्ट्र भाव को भी सांप्रदायिकता बताती है। चुनौति असाधारण है। मुस्लिम मजहब का वास्ता देकर परिवार नियोजन का विरोध क्यों करते है? तथ्य स्पष्ट है कि खुद को मजहबी बताकर अपनी आबादी बढ़ाते हैं। हिन्दु भी यदि ऋग्वेद के अनुसार संतती सूत्र पर चलने लगे तो जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्या होगा? ऋग्वेद (10,85,45) में नवविवाहितों के लिए प्रार्थना है कि, हे इन्द्रदेव आप उसे सौभाग्यशाली बनाये और दस पुत्रों वाली बनाये। आबादी बढ़ी है तो देश के भविष्य को देखते हुए। भविष्य को देखते हुए हिन्दु-मुस्लिम और अन्य जाति-धर्म के लोगों को भी नियमन और जनसंख्या असंतुलन पर गहन विचार करना एवं मानना राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेकिन इस्लामी जीवनशैली में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के संबंध में कोई चिंतन नहीं है। अरब मुल्कों में आबादी नियंत्रण के विरोध में 'शाल्फिया' मुभमेंट चला था। 1988 में इस्लाम जनसंख्या वृद्धि दर 20 प्रतिशत थी। यह विकसित देशों की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक कई इस्लामी देशों में नियंत्रण के कार्यक्रम अपनाये हैं। ईरान ने आबादी के रफ्तार को 3.2 प्रतिशत से घटाकर 2.2 प्रतिशत कर दिया है। पाकिस्तान ने भी जनसंख्या नीति की घोषणा 2002 में ही है। मिस्त्र, जार्डन, तजाकिस्तान, कुबैत, ओमान, कतर, सउदी अरब, बनई और अजर बैजान की आबादी इस प्रयास से स्थिर हो गई। अलबेनिया, फिलिस्तीन और सिरिया की आबादी ऋणात्मक है।

लेकिन भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ाव नीति जारी है। कुछ मुस्लिम विद्वानों ने आबादी नियंत्रण की बाते की मगर मुस्लिम प्रसर्नल लॉ बोर्ड के चेयरमैन ने परिवार नियोजन को गैर इस्लामी बताकर सबका मुंह बंद कर दिया। भारतीय मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि को सत्ता की सिढ़ी मानते हैं। इसी लोभ में जनसंख्या बढ़ाने में लगी है। दूसरी बात है कि जो लोग भारत को धर्म-निरपेक्ष कहते हैं। उनसे पूछे कि मुस्लिम अपने धर्म के अनुसार चार शादी कर सकते हैं। जबकि रामायण ग्रंथ के अनुसार दशरथ की तीन पत्नियां थी। फिर हिन्दू एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। संसार में मुख्य रूप से चार धर्म प्रचलित है। हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौध धर्म, ईसाइ धर्म इन चारों धर्मों में अवातर कई धर्म है। हिन्दू धर्म को छोड़कर शेष तीनों धर्मों के मूल में धर्म चलाने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा? जैसे मुस्लिम धर्म के मूल में मो0 साहब, बौध धर्म के मूल में गौतम बुद्ध और इसाई धर्म के मूल में ईसा मसीह मिलेंग। परन्तु हिन्दु धर्म के मूल में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कारण है कि हिन्दू धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है। यह सामुहिक निर्णय पर आधारित है।

फिलहाल बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु तमाम भारतवासियों को सचेष्ट होना पड़ेगा, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम-सिक्ख हो या इसाई। जनसंख्या नियंत्रण के कानून से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय नेताओं को भी चाहिए कि वह मुसलमानों को वोट बैंक ना समझे, अन्यथा मुसलमानों की बढ़ती आबादी एक ना एक दिन देश की अर्थव्यवस्था को नेस्तानाबूत करके छोड़ेगा। देश की अखंडता पर भी खतरा हो सकता है। जन संख्या वृद्धि रोकने के लिए चुनाव में भाग लेने, सभी तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। यह सभी धर्मों के नागरिकों पर लागु करने की आवश्यकता है। ●

सांसद का भव्य स्वागत

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

फतुहा में नवनिर्वाचित कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भवय स्वागत किया गया। इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फतुहा सहित पटना साहिब क्षेत्र में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोडुंगा। उन्होंने कहा कि लोगों को मिलने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने जनता को आभार व्यक्त किय तथा जीत दिलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। इस अभिनन्दन समारोह में भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, संजीव यादव, ई0 सत्येन्द्र सिंह, केशर प्रसाद, मुन्ना यादव, रणधीर यादव, राम मिस्टो सिंह, जितेन्द्र मिस्त्री, दीलीप पासवान, अरूण झा, रणजीत यादव, विजय कुमार वत्स, राजेन्द्र राणा पासवान, पप्पु जी, बेबी देवी, लाडली कुमारी, पिंकी देवी, मनीषा कुमारी, रिया देवी, रिंकी कुमारी, मनीता कुमारी, मीणा कुमारी, सुनीता देवी, बसंती देवी, बवीता देवी, संजु देवी, रिया देवी, सुनीता देवी, शकुन्तला देवी, रूबी देवी, सीमा देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, अंजली देवी, मीणा देवी, पुनम देवी ब्यूटी देवी, जुली देवी, रूबी कुमारी, सवीता देवी, आदि फतुहा भाजपा नगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष शोभा देवी ने रविशंकर प्रसाद को गीता धर्म ग्रंथ भेट किया, पुस्तक भेंट मिलते ही भाव विभोर हो गए और कहा कि धन्य हो शोभा बेटी ऐसी तोहफा मुझे शायद पहली बार मिली है। शोभा ने विकास के लिए मांग पत्र भी दिया जो निम्न प्रकार है :-

☞ फतुहा में बस स्टैण्ड, टेम्पु स्टैण्ड एवं यात्री

शेड का निर्माण होना चाहिए।

☞ शुद्धपेय जल के लिए चार जल मिनार का निर्माण हो एवं हर पंचायत में भी जल मिनार का निर्माण हो। फतुहा को स्वच्छता मिशन से जोड़कर चार सुलभ शौचालय, जगह-जगह पेशाब खाना जहाँ जरूरी है निर्माण करना जरूरी है, तभी स्वच्छ एवं सुन्दर फतुहा क्षेत्र बन सकेगा क्योंकि यहाँ हजारों यात्री गंगा स्नान को आते हैं।

☞ शिक्षा के विकास और युवकों को रोजगार तथा नौकरी के लिए सरकारी कॉलेज तथा बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में स्कील इण्डिया के तहत आई० टी० आई० प्रशिक्षण केन्द्र का होना भी आवश्यक है।

☞ खेती कृषि क्षेत्र एवं किसान हित में बाजार समिति प्रांगण में गोदाम का निर्माण, अनाज की नगद बिक्री कि व्यवस्था तथा मल्टीकोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना ही फतुहा को विकसित क्षेत्र बनायेगा कृषि को उद्योग का दर्जा मिले।

☞ रोड को साफ स्वच्छ रखने के लिए सब्जी मार्केट का निर्माण, रोड से अलग बनाकर शहर एवं गॉव का विकसित एवं फुट पाथ दुकानदार को मान सम्मान दिलाना अति आवश्यक होगा रोड भी अतिक्रमण मुक्त होगा।

☞ फतुहा ब्लाक में खेती की रोपनी, कटनी, जुताई आदि मशीन भाड़ा पर मिले और उसका प्रशिक्षण किसान को मिले। ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र हो क्योंकि गरीब किसान मशीन खरीदने में सक्षम नहीं है।

☞ फतुहा रेलवे गुमटी पर तुरन्त पुल निर्माण कराई जाए तथा फतुहा मस्ताना घाट के सामने पीपा पुल निर्माण किया जाए। गंगा पार के ग्राहकों को सुविधा होगी।

☞ भाजपा मीडिया प्रभारी डा0 लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आज लाखों निर्दोष लोग जेल में हैं जिसका परिवार जिन्दगी मौत से गुजर रहा है। आप कानून बना दें कि निर्दोष को जेल भेजने वाले पुलिस अधिकारी को भी जेल जाना होगा। तथा दोषी को छोड़ने वाले का भी जेल जाना होगा। साथ ही साथ अपराध में ईस्तेमाल होने वाला हथियार बरामद करना ही होगा तथा हथियार निर्माण स्थल का उदभेद करना होगा। ऐसे ठोस कदम उठाये जाने से 90/95 प्रतिशत अपराध में कमी आ सकती है। तथा यह भी कानून बना दें ताकि भ्रष्ट कर्मचारियों तथा घूस मांगने पर तबादला, संस्पेण्ड के बदले बर्खास्त या जेल भेजना होगा अन्यथा अपराध पर नियंत्रण संभव नहीं है। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

पटना का रवि बन गये रविशंकर

● रंजीत कुमार सिन्हा

पटना साहिब संसदीय सीट से 17वीं लोकसभा चुनाव में पटना साहिब संसदीय सीट से जीत हासिल करने के लिए 6 विधान सभा के विधायक मंत्री को अपना-अपना पारफॉर्मेंस दिखाने का अवसर सामने दिखाई दे रहा था। पटना सहित लोकसभा सीट, बिहार की सुनिश्चित सीटों में से एक है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में फतुहाँ विधान सभा क्षेत्र जो 90% किसानी बेल्ट है, राजधानी की सीट होने के बावजूद राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है। कार्य करने की दृष्टि से कार्यकर्त्ताओं के लिए बड़ी चुनौती एक ही विधान सभा में ग्रामीण एवं पटना महानगर होने के कारण संगठनात्मक रूप से जोड़ने के बजाये कार्यकर्त्ताओं के बीच सहयोग एवं तालमेल की कमी संगठन में बैठे वरिष्ठ नेताओं को ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद उदासीन है। ये गठबंधन की सीट है लोजपा-जदयू की यहाँ वोट की कमी है, कभी बढ़त नहीं मिलती कोई लिडरशीप नहीं है, इन बातों के कारण उपेक्षित है।

अच्छे परिस्थिति में सभी कार्य करते हैं, विपरीत परिस्थिति में कार्य कर फसल उपजाना किसान मोर्चा ने संभाला। राजनीतिक रूप से बंजर जमीन को नरेन्द्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं, किसान पंचायत, किसान चौपाल, किसान जनसम्पर्क, किसान महासमागम, किसान स्वास्थ्य मेला जैसे कई सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम, शिविर लगाकर ग्रामीण खेत खलिहान मजदूर-किसान, नौजवान के बीच सम्बंध स्थापित किया। मोर्चा के नेतृत्व चाहे तपती धुप हो, मुसलाधार बारिस, कड़कड़ाती ठंड में अपने कार्यकुशलता के साथ कृषक क्षेत्र को उर्वरा प्रदान की। लोगों को परिवार की तरह सम्बंध स्थापित किया। अब चुनाव में फसल काटने एवं मजदूरी पाने की बारी आयी कार्यकर्त्ता आशा भरी निगाह से देख रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे दो लोगों को फतुहा का प्रभारी का दायित्व सौंप दिया गया, जो लहलहाते फसल को रौंदकर तहस-नहस करने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं में कटूता पैदा कर दी, जोड़ने के बजाए संगठित कार्यकर्त्ताओं को तोड़ने लगे, प्रभारी अपरिपल्व, अव्यवहारिक अकुशल दिखाई पड़ रहे थे, संवाद की कमी, बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर दिया, सोंच यह कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते? लेकिन प . दीनदयाल, अटल जी के आदर्शों एवं मोदी जी के कुशल प्रबंधन के भाव को आगे बढ़ाते हुए किसान मोर्चा, मंडल, कार्यकर्त्ताओं ने संघ के मार्गदर्शन, आशीर्वाद से समन्वय स्थापित कर फतुहाँ विधान सभा अंतर्गत 29 पंचायतों में इस प्रचंड गर्मी के बीच, पन्ना प्रमुख, शक्ति केन्द्र, बुथ स्तर की बैठक जनसम्पर्क स्थापित करने में सफल दिखे।

नेता, विधायक विहिन, प्रभारी के आपसी खींचतान-दलदल के बीच भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने कमल खिलाने में सफल दिखे। एक ओर दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़े-बड़े स्टार कम्पेनर श्री आदित्यनाथ योगी-मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य-उपमुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह-गृहमंत्री, हेमामालिन, भूपेन्द्र यादव, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, जैसे बड़े नेताओं द्वारा दर्जनों सभायें की गई, वही फतुहाँ एक-दो सभा उम्मीदवार द्वारा कर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जल्ला क्षेत्र को तो बिल्कुल उपेक्षित ही कर दिया गया। उसके बावजूद मोर्चा मंच मंडल के कार्यकर्त्ताओं ने अपने दमखम पर लगभग 12 हजार के जीत के अंतर से कांग्रेस प्रत्यासी को हराया, साथ ही स्थानीय विधायक डा. रामानंद यादव की एक न चली।

रवि शंकर	शत्रुघ्न सिन्हा	जीत अंतर
74872	62897	11975

फतुहाँ के जनता ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष (किसान नेता) एवं रोटरी क्लब के (झारखंड बिहार) के पर्यावरण चेयरमैन ने हमेशा समर्पित भाव से समाजिक एवं राजनीतिक गतिविधि देने का काम किया है। ●

तीहरे हत्या कांड में पुलिस की संवेदनहीनता

नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र में सिकन्दरा के तीन युवकों का अपहरण कर हत्या कर देने के मामले में नवादा पुलिस पॉच दिनों तक संवेदनहीन बनी रही। वहीं पॉच दिनों के बाद घटना स्थल से तीन कि0मी0 की दूरी पर लाश बरामदगी होना पुलिस की अत्याधुनिक तकनीक से जॉच-पड़ताल पर संदेह उत्पन्न करता है। जमुई से हमारे जिला ब्यूरो अजय कुमार की रिर्पोट :-

जमुई जिले के सिकन्दरा थानाक्षेत्र के सिकन्दरा से अगुवा हुए तीन युवकों की लाश आखिरकार पॉच दिनों बाद मिल ही गये। इस तीहरे हत्याकांड को नवादा पुलिस सब कुछ जानते हुए भी लाश तक को खुद पता नहीं लगा सकी और अब लाश बरामद हो जाने के बाद सांप की लकीर पीटती नजर आ रही है। हालांकि इस जघन्य हत्याकांड में सिकन्दरा पुलिस जितने भी पल्ले झाड़ ले पर उसकी भी भूमिका कम संदेह पैदा नहीं करती। बताया जाता है कि मृतकों में से एक अबैध शराब का बहुत बड़ा माफिया था। गौर करने वाली बात यह है कि शराब बंदी के वावजूद यदि कोई बड़े शराब माफिया माना जाता है तो यह तय है कि उस बड़े शराब माफियाओं को स्थानीय थाना का संरक्षण जरूर प्राप्त होगा। हालांकि जिले के पदाधिकारियों द्वारा जितने भी दावा किया जा रहा हो पर इतना तय है कि शराबबंदी के इतने साल बीत जाने के बाद भी शराब मिल रहा है और बालू-दारू माफियाओं की हत्या तक हो रही है। जमुई के सिकन्दरा में भी तीहरे मर्डर के पिछे का कारण भी यही बताया जाता है। हालांकि जमुई और नवादा पुलिस भले ही इस हत्या कांड के बिल्कुल समीप पहुँच जाने की दावा कर रही हो पर आज तक इस जघन्य हत्या कांड में प्रयोग किया जाने वाला न तो बोलेरो बरामद कर सकी है और न ही हत्यारों की पहचान की जा सकी। इतना तो तय ही कि सिकन्दरा के तीहरे मर्डर में दर्जन भर हत्यारों से कम की संख्यां नहीं होगी। स्वभाविक है कि तीनो मृतक के पास मोवाईल भी होगा और उस मोबाईल का लोकेशन के आधार पर भी अत्याधुनिक तकनीक से जांच होनी चाहिए थी? मोबाईल सीडीआर से पता हो सकता था कि हत्या से पहले किन लोगों से बात हुई होगी? क्या उन तीनो को मोबाईल के आधार से मृतक का पता नहीं लगाया जा सकता था? हत्या के 15 दिनों के बाद भी न तो हत्यारों को पकड़ा जा सका और न ही कुछ खुलासा किया जा सका जिससे कि परिजनों की सहानुभूति हासिल की जा सके?

नवादा पुलिस सिकन्दरा पुलिस के सहयोग से 2 जून को सिकन्दरा थाना क्षेत्र के धरसंडा और नारायणपुर समेत कई गावों में छापेमारी कर एक राईफल दो पिस्टल और 22 कारतूस समेत कई चीजों को बरामद किया तथा दो लोगों की गिरफ्तारी भी की पर यह साबित नहीं कर सका कि इनका इस हत्या कांड में कोई संलिप्तता है। कौवाकोल थाना प्रभारी बताते हैं कि हम हत्यारों के बिल्कुल करीब पहुँच गये हैं और बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं। पर लाश बरामदगी के आठ दिनों बाद भी पोस्टमार्डम रिपोर्ट पटना से नहीं ला सकी नवादा पुलिस और न ही खुलासा कर सकी कि आखिर तीनो की हत्या किस प्रकार से की गई थी जिससे कि मृतक का शरीर विकृत और क्षत-विक्षत हालात में पहुँच गये।

गौरतलव है कि सिकन्दरा के राजकुमार यादव उर्फ पल्लू पिता आनो यादव, जितेन्द्र यादव उर्फ रिंका पिता केसो यादव तथा विक्की रजक पिता ललन रजक दो अलग-अलग मोटरसाईकिल से शादी का न्योता देकर पकरीबरामा से लौट रहे थे। 24 मई को लौटते समय बोलेरो सवार अपराधियों ने तीनो का अपहरण नवादा के कौवाकोल थाना क्षेत्र के कदहर गांव के पास से अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि ग्रामिणों ने देखा कि कुछ नकाबपोश अपराधी तीनो को बलपूर्वक बोलेरो में बैठा कर जंगल के रास्ते ले गये। सूचना पर पहुंची पुलिस उसी दिन दोनो मोटरसाईकिल को बरामद कर लिया। पर उस दिशा में अपहर्त्ताओं का पिछा नहीं किया गया होगा जिससे घटनास्थल से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर उसी दिन उन तीनो की हत्या कर दी गई। परिजन बताते हैं कि पुलिस को पूरी तरह से जानकारी थी कि इन तीनो का अपहरण फिरौती के लिए नहीं किया गया है। यह भी पता था कि इसी रास्ते से तीनो को एक बोलेरो से ले जाया

गया है। परिजन सशंकित थे कि अपहर्त्ता उन लोगों की हत्या कर देंगे। 25 मई को राजकुमार का भाई दिनेश यादव अज्ञात के खिलाफ कौवाकोल थाना में एफआईआर दर्ज कराया। आखिरकार 29 मई को पॉच दिनों बाद तीनो अपहर्त्ता का लाश घटना स्थल से मात्र तीन किलोमीटर के नजदीक भोरमभाग के पहाड़ियों पर क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया गया। वह भी पुलिस नहीं चरवाहों के द्वारा बताये गये स्थान से लाश बरामद किया गया। पुलिस के इस संवेदनहीन रवैये के कारण लाश बरामदगी के बाद दो दिनों तक सिकन्दरा बाजार स्वत: बंद रहा। लाश इतना सड़ और विकृत हो गया था कि देखने से पता चलता था कि मारने के बाद लाश में एसिड डाल दिया गया होगा। लाश सड़ जाने के कारण लाश का पोस्टमार्टम भी नवादा में नहीं किया जा सका। उसी दिन लाश को पोस्टमार्डम के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा गया। पटना में भी लाश का पोस्टमार्टम एक दिन नहीं हो सका। तीन दिनों तक सिकन्दरा किसी अनहोनी के आशंका से सशंकित था। जमुई पुलिस रात-रात भर थाना क्षेत्र में गस्ती करती रही। सिकन्दरा पूर्व में भी कॉफी चर्चित स्थान रहा है। वर्चस्व की लड़ाई यहॉ काफी फला-फूला है। विगत कुछ वर्षो से शांत सिकन्दरा को किसी की नजर न लगे इस आशा से यहॉ के नागरिक आज भी आशान्वित नजर आते हैं। हालांकि इस बार हत्या के बाद जमुई पुलिस की कार्यशैली काफी चुस्त रहने तथा किसी भी अनहोनी से निवटने को तत्पर रहने के कारण तथा स्थानीय शांति समितियों से सामंजस्य के कारण कॉफी कुछ संभालने में कामयाब रहा। पर जिस प्रकार से जिले में दारू और बालू कारोबार आज भी चरम पर है उससे जिले तथा पुलिस विभाग को भी कॉफी क्षति पहुँच रही है।

हालांकि पुलिस लाश वरामदगी के बाद सिकन्दरा अलीगंज के आसपास के कई गांवों में छापेमारी कर रही है और बताया जाता है कि पुलिस अब मामले के बहुत नजदीक पहुँच गई है पर जिस प्रकार की गति अपहरण और लाश बरामदगी के बाद देखा जा रहा है उससे यही लगता है कि पुलिस सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आगे की तफतीश क्या गुल खिलाती है या फिर कोई दारू-बालू माफिया मौत का शिकार होता है। ●

एकलव्य ने एकलव्य का मान बढ़ाया

● **प्रो० रामजीवन साहू**

हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जन्म लेना और मर जाना उतना कष्टप्रद नहीं है जितना विद्याहीन रहना, क्योंकि जन्म लेने और मरने पर सिर्फ दो बार कष्ट होता है, लेकिन विद्याहीन रहने पर पग–पग पर कष्ट होता है, इसलिए हर व्यक्ति को विद्या ग्रहण करना चाहिए। तर्कशास्त्री तो यह भी कहते हैं कि विद्या तीसरी आँख है। 1980 के पूर्व जमुई में मात्र के०के०एम० कॉलेज था। इसके कारण प्रतिवर्ष निर्धन तबके के बच्चों का महाविद्यालय में प्रवेश करना कठिन था। 1980 में बिहार विधान सभा का चुनाव हुआ। उसमें इसी नगर के वरीय और प्रतिष्ठित जमुई व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता स्मृतिशेष नरदेव प्रसाद भगत ने अपने प्रतिद्वंदी विधान सभा अध्यक्ष स्मृतिशेष त्रिपुरारी प्रसाद सिंह को 3600 मतों से पराजित कर विजयी हुए। विधान सभा चुनाव के बाद जनता का एक ही मांग थी कि पहले महाविद्यालय फिर शिवालय। परिणामस्वरूप 28 अगस्त 1980 में एक नये महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका नाम प्रारंभ में एकलव्य डिग्री महाविद्यालय था बाद में इसका नाम सरस्वती अर्जुन एकलव्य महाविद्यालय हुआ। स्वर्ण आभूषण व्यवसायी पुराना बाजार जमुई के निवासी स्मृतिशेष अर्जुन प्रसाद केशरी ने एक लाख रूपये सहयोग कर महाविद्यालय की स्थापना में सहायता की। उनकी पत्नी का नाम स्मृतिशेष सरस्वती देवी था। एकलव्य महाभारत का एक महारथी था। कहा जाता है कि गुरू द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने गुरूदक्षिणा में एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांगे। एकलव्य ने बिना देरी किए हुए अपना अंगूठा काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया। उस महारथी के सम्मान में महाविद्यालय के नाम में एकलव्य शामिल किया गया। इस प्रकार एकलव्य ने एकलव्य का मान बढ़ाया।

अर्जुन प्रसाद केसरी

नरदेव प्रसाद

इस महाविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में भी तीर चलाते हुए एकलव्य की छवि अंकित है। नरदेव प्रसाद भगत ने एक ट्रस्ट की जमीन 99 वर्ष के लीज पर उपलब्ध कराये। इसके संस्थापक प्राचार्य प्रो0 गोपाल कृष्ण वर्मा थे। शुरूआत के दौर में प्राध्यापकों के रूप में प्रो0 महेश प्रसाद केशरी, प्रो0 नकुल साह, प्रो0 राजेन्द्र साह, डॉ0 मासूम अहमद, प्रो0 रमाशंकर प्रसाद कुर्मी, प्रो0 निरंजन रावत, प्रो0 मुरारी लाल स्वर्णकार, प्रो0 शैलेन्द्र कुमार तिवारी और प्रो0 रामजीवन साहू ने अपना योगदान किये। स्मृतिशेष नरदेव प्रसाद भगत एक जमीनदार परिवार से आते थे। उन्होंने अपना जीवन पढ़ाई के साथ–साथ राष्ट्रीय भाव को आत्मसात करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा की पढ़ाई आरा में प्रारंभ किये। कुछ वर्षों वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक के रूप में कार्य किये। स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद कानून की भी पढ़ाई पूर्ण किये। हिन्दुओं को संगठित करने के ध्येय से वकालत करना भी प्रारंभ किये। कुछ ही वर्षों के बाद ये जमुई व्यवहार न्यायालय के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में स्थापित हो गये। फिर क्या था 1980 के चुनाव में विधान सभा जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सका।

डॉ0 रामानन्द प्रसाद भगत द्वितीय प्राचार्य प्रो0 रमाशंकर प्रसाद कुर्मी के बाद इस महाविद्यालय के तीसरे प्राचार्य के रूप में भले

हीं नियुक्ति हुई हो लेकिन महाविद्यालय के हित में इन्होंने बहुत काम किया। आज जिस रूप में इस महाविद्यालय को देख रहे हैं इसमें इन्हीं का परिश्रम और विवेक का प्रतिफल है। इन्होंने गरीबी को बिल्कुल नजदीक से देखा है। इसलिए अन्य जगहों में इन्होंने बिल्कुल मितव्ययिता दिखायी लेकिन भवन बनाने में दिल खोलकर धन खर्च किया। आपको बता दूँ कि इनका जन्म 4 अगस्त 1958 में जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के मिर्जागंज गाँव में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री सीताराम भगत और माताजी का नाम स्मृतिशेष देवकी देवी था। माता का नाम देवकी होने के कारण इनका पुकारू नाम कन्हैया भी है। जन्म के समय से हीं इनके माता–पिता ने इनमें आई० ए० एस० की झलक पायी थी इसलिए एम० ए० (इंगलिश) और एल० एल० बी० उत्तीर्ण होने के बाद यू0 पी0 एस0 सी0 की तैयारी में लग गये। तैयारी चल ही रही थी कि इसी बीच श्री नरदेव प्रसाद भगत की दृष्टि इन पर पड़ गयी, फिर क्या था उन्होंने अपने नये महाविद्यालय में 6 सितम्बर 1982 को अंग्रेजी व्याख्यात के रूप में नियुक्त कर लिये। नियुक्ति के तुरन्त 7 महीने 22 दिन बाद हीं 28 अप्रैल 1983 में इनका विवाह नरदेव प्रसाद की सबसे छोटी पुत्री एम० ए० उत्तीर्ण उषा कुमारी के साथ हो गयी। 09 जुलाई 2001 में इन्होंने महाविद्यालय का प्रभारी प्रचार्य का पद ग्रहण किया। प्राचार्य बनने के बाद इन्होंने पहला काम महाविद्यालय में नामांकन बढ़ाने का काम किया। इसके लिए वे दूसरे प्रदेश में जाकर अभिभावकों से संपर्क किया। संख्या बढ़ने के बाद भवन बनाने के लिए सभी तरह के तंत्रों का उपयोग कर एक विशाल भवन खड़ा कर दिये। फलस्वरूप इस बीच उषा कुमारी की भी नियुक्ति इतिहास विभाग में हो गयी। 2016–17 में अन्य चीजों के विकास के साथ–साथ इनकी डिग्री में भी विकास हुआ अर्थात् दोनों पति–पत्नी पी0 एच0 डी0 की डिग्री हासिल कर लिये। वर्त्तमान समय में इस महाविद्यालय में इग्नू का अध्ययन केन्द्र भी स्थापित हो गया है। इसके कॉर्डिनेटर डॉ0 निरंजन दूबे हैं। साथ हीं इस महाविद्यालय में प्राक् प्रशिक्षण परीक्षा केन्द्र की स्थापना भी हो गयी है। इसके डायरेक्टर और प्राचार्य डॉ० रामानन्द प्रसाद भगत हैं। ●

कागज पर चल रहे बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता रद्द

● **मिथिलेश कुमार**

नवादा जिले में कागज पर चल रहे बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग कालेज की मान्यता रद्ध कर दी गयी है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए जांच कमिटी का गठन कर कालेज से पास आउट छात्रों की सूची खंगालने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14.03.2019 को बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग, नवादा का औचक निरीक्षण दल के माध्यम से कराया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि यह संस्थान कार्यरत नहीं है एवं प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि यह संस्थान केवल कागजों पर ही चलाया जा रहा है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा विषय के गंभीरता के आलोक में सख्त प्रशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं । संदर्भित संसथान के संचालक से मान्यता रद्द करने के सम्बन्ध में कारण पृच्छा का आदेश दिया गया था साथ ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट (criminal breach of trust) के मामले के तहत संस्थान के संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु सिविल सर्जन, नवादा को निर्देशित किया गया था । इस क्रम में सिविल सर्जन, नवादा के द्वारा उक्त संस्थान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है (सदर थाना कांड संख्या ख्र 459/2019 दिनांक ख्र 24.04.2019) । विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस संस्थान सम्बंधित वर्षवार नामांकन तथा पास किये छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से सूचना तलब की गयी थी । इस क्रम में विभाग ने एक औचक निरीक्षण दल का गठन किया गया है जो समयबद्ध रूप से सभी नर्सिंग संस्थान का निरिक्षण कर विभाग को प्रतिवेदन समर्पित कर रहा है । इस क्रम में सभी सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया था की वह अपने जिला अंतर्गत कार्यरत सभी नर्सिंग संस्थानों की जांच कर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन दो माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराएँ।

विभागीय औचक निरिक्षण के जांच प्रतिवेदन एवं सिविल सर्जन, नवादा के अनुश्रवण प्रतिवेदन के आधार पर एवं संस्थान से मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर संस्थान द्वारा नहीं दिए जाने की स्थिति में समयावधि समाप्ति होने पर विभाग ने दिनांक 23 मई 2019 को बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग, नवादा की ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रदत मान्यता रद्द किये जाने का अनुदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया की विभाग द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के निरंतर अनुश्रवण एवं आवधिक औचक निरिक्षण की प्रक्रिया से नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा / प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा । अनुश्रवण में INC के मानक अनुरूप नहीं पाए जाने पर संस्थानों को गुणवत्ता में सुधार हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तथा गंभीर शिकायतों की स्थिति में सख्त प्रशासनिक आदेश दिए जा रहे हैं। बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग, नवादा की मान्यता रद्द किया जाना निजी क्षेत्र में संचालित सभी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के लिए "हर हाल में INC मानक अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने "का सीधा-साधा संदेश है। स्वास्थ्य विभाग के इन प्रयासों से राज्य में कार्यरत नर्सिंग संस्थान को INC के मानक के अनुरूप संचालित करने की सुदृढ़ प्रणाली विकसित हो पायेगी। ●

आवश्यकता

भ्रष्टाचार एवं विभाग की गुंडागर्दी के विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए नवादा, नालन्दा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा और कोडरमा जिला में जिला ब्यूरो एवं संवाददाता की आवश्यकता है। बेरोजगारी की कोढ़ से मुक्ति पायें एवं समाज एवं सरकार में प्रतिष्ठा के साथ महीने का 25 से 30 हजार रूपया भी पारिश्रमिक कमा सकते हैं।

इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें:-

मिथिलेश कुमार:- 9934021022 - 9431410833 मनीष कमलिया:- 9934964551 - 6202340243
कृष्ण कुमार चंचल- 9430520291 अरबिन्द मिश्र - 6204617413, अमित कुमार सिंह- 9934706928

महिला उत्पीड़न बनाम नारी सशक्तिकरण

महिलाओं की सुरक्षा में क्यूं सक्षम नहीं है सरकार

● मिथिलेश कुमार

पूरी दुनिया के करीब 208 देशों में आर्थिक विकास के लिए नित नये नये प्रयोग किए जा रहे हैं। मानव सभ्यता को आधुनिकतम सुख सुविधा विलासताएं के नये तकनीक भी अपनाये जा रहे है। परन्तु वर्तमान परिवेश में अपराध की विभिन्न श्रेणियों का पर्दापन मनुष्य को अभिशप्त जीवन जीने पर विवश कर रहा है। इससे अलग महिला उत्पीड़न के मामले बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। दुनिया का एक भी देश इस भयानक रोग से अछुता नहीं है अगर हम अपने देश भारत की बात करते तो यहाँ के हालात खासकर और भी बदतर होती जा रही है। बिहार और उड़ीसा को सबसे गरीब राज्य का दर्जा प्राप्त है। हालात यहाँ भी अच्छे नहीं है। जनसंख्या घनत्व एवं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बड़े राज्य की श्रेणी में है। महिला उत्पीड़न मानव सभ्यता और संस्कृति को शर्मशार कर रही है । रोज नये नये घटनाओं का सृजन होता है। कितनी महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही तो कहीं बहनों को दहेज की बली वेदी पर चढ़ा दिया जा रहा है। घर में भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। यहाँ तक कि नर पिचास की शक्ल और मानव का खाल ओढ़े राक्षस अपनी हवश का शिकार छोटी छोटी नन्हीं नन्हीं बच्चियों को बना रहे हैं। पीड़ीत बच्चें महिलाएं जीवन भर अनचाहे बोझ को ढोने पर विवश रहती हैं। इतिहास साक्षी है जितना पुराना हमारा इतिहास है उतना ही पुराना महिला उत्पीड़न का इतिहास है। पुरी दुनिया में पुरूष मानसिकता का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। महिलाओं का ह्रदय कोमल होता है । यह स्वभाविक प्रकृति प्रदत गुण हैं। ईश्वर के बनाये मानव रूपी कृति में पुरूष और महिलाओं के व्यवहार गुण ह्रदय मानसिक सोच में अपेक्षाकत अन्तर होता है, महिलाएं प्रतिकार नहीं कर पाती है नतीजा कई तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है। खासकर बलात्कार कितना घृणित अपराध है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है की बलात्कार की घटना की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वाच्च न्यायालय ने भी कहा था कि हत्या तो किसी व्यक्ति को मार देता है परंतु बलात्कार तो आत्मा तक को मार देता है फलस्वरूप महिला जीवन भर इस उत्पीड़न से उबर नहीं पाती हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हो रहीं है वैसे वैसे महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी नहीं की महिलाओं का उत्पीड़न केवल गरीब परिवार में होते हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि महिलाओं का उत्पीड़न तो कोख से ही शुरू हो जाता है लिंग परीक्षण पर रोक के बाबजुद लड़कियाँ जन्म लेने के पुर्व ही समाप्त कर दी जाती है। जन्म लेने के बाद उसे भेद भाव का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न से संबंधित आंकड़े को राष्ट्रीय अपराध ब्युरो द्वारा क्राईम इन इंडिया में संकलित किया जाता है। आंकड़ो के अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं में यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार, वैवाहिक हिंसा, दहेज प्रताड़ना, परिवारिक हिंसा, वेश्यावृति एवं स्कुलो, कॉलेजों एवं कार्यालयों में उत्पीड़न के मामले लागातार बढ़ रहे हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा शोध और सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि दुनिया भर में जितने अपराध होते हैं। उसमें ज्यादातर महिलाओं के विरूद्ध होते हैं। हालांकि अपराध महिलाओं के खिलाफ पुरूषों के द्वारा किया जाता है परन्तु महिलाओं के द्वारा भी खूब अपराध किया जा रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में महिलाएं आगे हो रही है तो भला अपराध में क्यों पीछे होगी। महिलाओ के द्वारा भी कई अपराध किए जा रहे हैं। हम इस आलेख में सिर्फ महिला उत्पीड़न पर चर्चा कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न पर हम अपराध ों को विभक्त कर उसे परिभाषित कर रहे हैं । आइये हम सबसे पहले दहेज की ओर ले चलते हैं दहेज भी एक ऐसा कारण है कि महिलाएं परिवारिक हिंसा की शिकार हो रहीं हैं। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है कि जिसके शिकार आये दिन नवविवाहितों को होना पड़ रहा है। क्राइम के आकड़े गवाह हैं दुर्भाग्य है कि आधुनिक समाज में भी दहेज रूपी कैंसर रोग के कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने पर मजबुर हो जाती हैं। हमारी प्राचीन परम्परायें भी अजीब है यह भी महिलाओं के प्रति हिंसा को उत्प्रेरित करती हैं। हमारी संस्कृति में पुत्र रत्न की प्राप्ति वंश वृद्धि के लिये आवश्यक माना गया है। परन्तु जो महिला पुत्र न पैदा कर सिर्फ बेटी को जन्म देती है उसे प्रताड़ित किया जाता है हालांकि पुत्र या पुत्री पैदा होने मे शुक्राणु ही जिम्मेवार होते हैं पर दोष सिर्फ महिलओं पर मढ़ा जाता है और महिलायें घरेलु हिंसा की शिकार होती हैं। दुर्भाग्य है कि बेटी पैदा होने पर महिलाओं को कोसा जाता है। प्रकृति का अनमोल उपहार उसके जीवन में जहर भर देता है जिसकी पीड़ा से महिलाएं जीवन भर तड़पती हैं। प्रेम प्यार प्रकृति का कुदरती प्रवृति है कभी कभी एक तरफा प्रेम के कारण भी महिलायें उत्पीड़न का शिकार होती हैं एक तरफा प्रेम में सिर्फ पुरूष अपने भौतिक सुखों के लिये किसी को पसंद करते हैं परन्तु महिला उसे नापसंद करती है तो नतीजन एकतरफा प्यार में प्रेमी अपनी प्रमिका की हत्या तक कर बैठते हैं। एसीड अटैक की ज्यादातर घटनायें प्रेम प्रसंग या व्यक्तिगत कारणों से ही होता है। यौन उत्पीड़न बलातकार जैसे मामले आज तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हुये बलात्कार की घटना ने पूरे भारत में भूचाल ला दिया था । मानवता को शर्मशार करने वाली घटना से पूरी दिल्ली सहित पूरा देश अपने को लाचार महसूस कर रहा था। परंतु बलात्कार और यौन उत्पीड़न को सिर्फ कानून नहीं रोक सकता है समाज के प्रत्येक समुदाय को इसे रोकने के लिये आगे आना होगा । आम महिलायें आज अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। सुनसान जगहों, चलती गाड़ीयों, एवं कार्यस्थलों की बात छोड़ दें अपने घर की चहारदीवारी के अन्दर भी महिलाये यौन शोषण का शिकार अपने करीब के परिवारों से हो रही हैं। आज पिता, भाई या अन्य संबंधी भी उसके अस्मत को लुटने में लगे हैं । बलात्कार के कारण महिलायें शारिरिक, मानसिक और सामाजिक सभी चोटों से ग्रसित होती हैं । कई क्षेत्रों में ऑनर किलिंग की भी

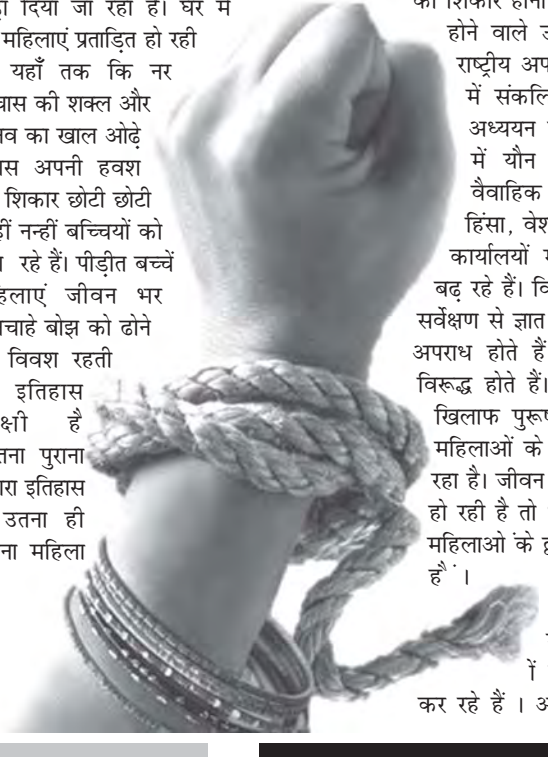

घटनाएं प्रकाश में आती है। जहाँ लड़की अगर प्रेम में वशीभूत होकर किसी अन्तर्जातीय लड़के से जो गरीब होते हैं अगर उससे प्रेम पूर्वक शादी करना चाहते हैं तो वैसे परिस्थिति में परिवार वाले उसकी हत्या तक करवा देते हैं। इससे उनके मानवीय एवं जीने के मौलिक अधिकारों का हनन होता है कभी कभी यह भी मामले आते हैं। जहाँ बाल सुधार गृह या जेलों में भी महिलाओं का यौन शोषण होता है नरभक्षी वहाँ भी उसे नहीं बख्शते हैं। शर्मनाक बात तो तब होती है जब धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण साधुओं और मुल्लाओं के द्वारा किया जाता है। पूर्व में भारत के कुछ राज्यों मे देवदासी प्रथा चलती थी भारत में धर्म को बहुत महत्व दिया गया है। परंतु धर्म के आड़ में कुछ घटनाऐं घटित हो रही है। ईश्वर और धर्म के नाम पर अबोध बच्चियों के जिस्म के सौदागर जी भर खेलते हैं। कितना घृणित अमानवीय अधार्मिक अपराध है। चर्चित लोगों पर यौन उत्पीड़ण एवं बलात्कार के मामले चल रहे हैं। आशाराम बापू जो ने जाने कितनी जिन्दगी को बरवाद किया होगा । उसी के नक्शे कदम चलने वाले उसके बेटे सत्य साई अपने बाप से भी दस गुणा आगे निकला । हम दाद देते हैं उस लड़की का जिसने अपनी हिम्मत दिखाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया और अपनी आवाज को कानून के सामने लायी । खाल में छिपे भेड़िये को बेनकाब किया है और भी कई तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। अब हम महिलाओं की सुरक्षा उसके अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण के बारे मे गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। जो वर्तमान परिवेश में लागू है अभी भी महिलाओं के सुरक्षा के जितने उपाय किए गए हैं वे नाकाफी हैं दिल्ली की

पॉक्सो क्या है?

☞ 14 नवंबर 2012 को 'द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट लागू हुआ।

☞ 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

☞ पहली बार कानून में यौन उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों को परिभाषित किया गया। बच्चों की कस्टडी के दौरान पुलिस व कर्मचारियों की ओर से किए गए उत्पीड़न के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए। तुरंत एफआईआर, विशेष अदालतों में सुनवाई।

☞ घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस या बाल पुलिस प्रकोष्ठ के अधिकारी मामले को दर्ज करेंगे। 24 घंटे के भीतर इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति, विशेष अदालत को देनी होती है।

☞ किसी भी व्यक्ति, होटल, मीडिया को बाल पोर्नोग्राफी की जानकारी होने पर उसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसे भी छह महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। गलत सूचना देने पर भी यही सजा।

☞ पीड़ित के मनपसंद जगह पर पुलिस की महिला अधिकारी सादे कपड़े में बयान दर्ज करेगी। इस दौरान उसके माता-पिता या भरोसेमंद साथ रहेंगे।

☞ पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई राज्य सरकार की अनुशंसा पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से गठित विशेष अदालत में होगी। राज्य सरकार विशेष अभियोजकों की भी नियुक्ति कर सकती है।

बच्चों की काउंसलिंग की व्यवस्था

☞ कानून की 39वीं धारा के तहत राज्य सरकार न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों की मदद करने के लिए एनजीओ, पेशेवरों और विशेषज्ञों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर सकती है।

☞ 40वें अनुच्छेद के तहत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (एनसीपीसीआर) और राज्यों के आयोग को प्रावधनों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अधिकृत करता है। (दिल्ली की भयावह तस्वीर)।

☞ 20 फीसदी 5 से 9 वर्ष के बच्चे किसी न किसी यौन उत्पीड़न के शिकार।

☞ 3 वर्षों में बच्चों के खिलाफ अपराध में 34 फीसदी का हुआ इजाफा।

☞ 96 फीसदी मामलों में अपराध करने वाला परिवार का ही जानकार।

☞ 76 फीसदी लोग भी मानते बच्चों को घर के आसपास ही सबसे अधिक खतरा सजा।

☞ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सात 10 साल कैद और अधिकतम उम्रकैद के साथ जुर्माना।

☞ बाल पोनोग्राफी के दोषी पाए जाने पर पांच साल कैद, अपराध दोहराने पर सात साल की कैद।

☞ यौन उत्पीड़न (दुष्कर्म नहीं) करने पर तीन साल जेल, इसके बढ़ाकर पांच साल तक किया जा सकता है।

घटना के बाद यौन उत्पीड़न कानून मे व्यापक बदलाव भी किए गए हैं। महिलाओं पर घरेलु हिंसा रोकने के लिये भारत सरकार ने घरेलु हिंसा निषेध कानून 2005 को लागू करने संबंधी अधिसूचना को 2006 में जारी किया 2005 के अगस्त माह में महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा संसद से पारित किया गया । जिसे 2005 के ही सितंबर माह में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कानून पर मुहर लगा दी। घरेलू हिंसा निवारण कानून एक महत्वपूर्ण कानून है। अगर इसे शत प्रतिशत लागू किया जाता है तो यह बहुत प्रभावी होगा । इस कानून में निम्न कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 1 महिला का शारिरिक भावनात्मक आर्थिक या यौन शोषण करना या इसकी धमकी देना। 2. महिला को ताने मारना, पुरूष द्वारा महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन और शरीर को कोई चोट पहुँचाना। 3. महिला की गरीमा एवं प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाना। 4. बच्चे नहीं होना या पुत्र नहीं होने पर ताने मारना। 5. महिला को अश्लील चित्र देखने को विवश करना। 6. महिला को अपमानित करना उसके वितीय जरूरतों को पूरा नहीं करना। 7. दहेज न लाने पर प्रताड़ित करना या उसे गलत नाम से पुकारना उसके बच्चे को मारना या पीटना उसे आत्महत्या के लिए उकसाना। उपरोक्त तथ्यों के अलावे और भी कई ऐसे कई कृत्यों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन कानून का उलंघन करने पर संज्ञेय और गैर जमानती अपराध